संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

ट्रम्प की नई चाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक तरफ ईरान युद्ध में उलझ गए हैं तो दूसरी तरफ अपने ही बुने हुए टैरिफ जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। ट्रम्प की दादागिरि को लेकर दुनियाभर से उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रियाएं तो सामने आ ही रही हैं, साथ ही वह अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता में भी लगातार गिरावट आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। स्वयं को नोबल शांति पुरस्कार का दावेदार जताने वाले ट्रम्प की छवि अब अशांति दूत की बन चुकी है। न तो उन्हें युद्ध से निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है और न ही उनकी ट ैरिफ नीतियां सफल हो रही हैं। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए ट्रैरिफ को लेकर जो फैसला दिया उससे ट्रम्प पूरी तरह से बौखला चुके हैं। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति के पास अन्तर्राष्ट्रीय आपात आर्थिक अधिनियम के अन्तर्गत टैरिफ लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। ट्रम्प को सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरन्त ही 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10 फीसदी शुल्क लगा दिया और बाद में इसे बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया। यह प्रावधान राष्ट्रपति को 150 दिनों तक अधिकतम 15 फीसदी शुल्क लगाने की अनुमति देता है, ताकि बड़े भुगतान संतुलन घाटे का समाधान किया जा सके। इसके बाद ट्रम्प लगातार शुल्क लगाने के नए-नए तरीके तलाश रहे हैं। अलग-अलग देशों से व्यापार समझौतों पर बातचीत में ट्रम्प सरकार का दबदबा कमजोर हुआ।

अब ट्रम्प ने एक बार फिर दुनिया के तमाम देशों पर नया टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर ली है। ट्रम्प ने धारा 301 का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से व्यापार करने का आरोप लगाते हुए भारत सहित 16 देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आरोप लगाया गया है कि यह देश अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर व्यापार में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो इन देशों पर ट्रम्प नया टैरिफ अथवा कुछ नए तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस तरह भारत, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड आदि देश इसकी जांच के जद में आ गए हैं। धारा 301 जो ट्रेड एक्ट 1974 का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल व्यापार में असंतुलन अथवा मानक से हटकर ट्रेड देने पर किया गया है।

> **ट्रम्प को सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरन्त ही 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10 फीसदी शुल्क लगा दिया और बाद में इसे बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया। यह प्रावधान राष्ट्रपति को 150 दिनों तक अधिकतम 15 फीसदी शुल्क लगाने की अनुमति देता है, ताकि बड़े भुगतान संतुलन घाटे का समाधान किया जा सके।**

लाख टके का सवाल यही है कि अभी तक भारत के साथ ट्रेड डील करने की ओर बढ़ रहे अमेरिका को अचानक उसके व्यापार में खोट कैसे नजर आने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत की उस पॉलिसी को बताया जा रहा है, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में एंट्री आसान नहीं होने देती। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनकी कंपनियों के डाटा को भारत में ही एकत्र करना और उनकी डिजिटल सेवाओं पर भारतीय कानून लागू करने से अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो जाती है। साथ ही फार्मा जैसे सेक्टर में कीमतों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से भी अमेरिकी कंपनियों के लिए व्यापक अवसर नहीं बनते हैं। यही वजह है कि ट्रेड डील पर चल रही बातचीत के बावजूद अमेरिका ने भारत को सेक्शन 301 के तहत जांच के दायरे में ला खड़ा किया है।

अमेरिका द्वारा शुरू किए गए शुल्क और व्यापार बाधाओं ने कई देशों को वैकल्पिक बाजार तलाशने को मजबूर किया। अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत ने लगातार रचनात्मक कदम उठाए और एक के बाद एक व्यापार समझौते किए। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। इसके अलावा आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, खाड़ी सहयोग परिषद, न्यूजीलैंड से व्यापार समझौते किए। भारत ने अब तक कुल 21 मुक्त व्यापार समझौते किए जिससे भारत को लगातार फायदा हो रहा है। भारत के निर्यात में बढ़ौतरी की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रक्षा और तकनीकी सहयोग का विस्तार हुआ है। फिलहाल अमेरिका हाथ मलता नजर आ रहा है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ का बहुत मामूली असर देखने को मिला है। इस मामूली प्रभाव को भी खत्म करने के लिए भारत ने उत्पादकता और व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार के उद्देश्य से आंतरिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। हताश ट्रम्प ने अब धारा 301 का ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर नया दाव खेला है। ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि ट्रम्प राष्ट्रीय सुरक्षा को बहाना बनाकर कुछ नए टैरिफ लगा सकते हैं। इन उत्पादों में बड़ी बैटरियां, कास्ट आयरन, प्लास्टिक पाइप, इंडस्ट्रियल कैमिकल, पॉवर ग्रिड, मैटल, औद्योगिक पुर्जे और टैलीकॉम उपकरण जैसे सैक्टर शामिल हैं। अगर अमेरिका ने नया टैरिफ थोपा तो भारत के कई सैक्टर प्रभावित हो सकते हैं। ईरान से युद्ध के चलते अमेरिका के भीतर ट्रम्प का विरोध बढ़ने लगा है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के चलते अमेरिका ने खाड़ी देशों में अपने सभी बेस खो दिए हैं। अरबों रुपए का नुक्सान हो रहा है। अमेरिकी जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर इससे हासिल क्या होगा? इस बार अमेरिकी जनता युद्ध के विरोध में एकजुट नजर आ रही है। डैमोक्रेट्स भी अब ट्रम्प के पीछे एकजुट होने को तैयार नहीं हैं। टैरिफ और महंगाई को लेकर भी 10 में से 6 अमेरिकी असहमत हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर भी अमेरिकी जनता में निराशा है। भरोसे के मुद्दे पर भी तस्वीर ट्रम्प के अनुकूल दिखाई नहीं देती। ईरान के मकड़जाल में उलझे ट्रम्प अपनी छवि को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकी महसूस करते हैं कि विश्व के लिए मुसीबत बने ट्रम्प की कीमत अमेरिका को ही चुकानी पड़ेगी। तेल और गैस का खेल बिगड़ रहा है। भारत को भी ट्रम्प जैसे 'दोस्त' की चालों से सतर्क रहना होगा और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को निर्बाध जारी रखने के हर सम्भव प्रयास करने होंगे।

नई सीख देते हैं जीवन के उतार-चढ़ाव

गीता पाढा

जीवन के उतार-चढ़ाव हमें हर दिन नयी सीख सीखाते हैं,
अंधेरों के बाद ही तो उजाले मुस्कुराते हैं,,
यहीं तो हैं जो अपने और परायों की पहचान कराते हैं,
सच्चे लोग वक्त की आंधी में और निखर जाते हैं,,
किताबों से हम केवल कागजी ज्ञान पाते हैं,
पर बुजुर्गों के अनुभव हमें एक सच्चा इंसान बनाते हैं...।।"

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रयोग

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक

स्वतन्त्र भारत के इतिहास में संभवत: यह पहला अवसर है जब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग भारत की ऐसी स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था है जो अपना कार्य सीधे संविधान से शक्ति लेकर करती है और उसके कामकाज पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं रहता। भारत के लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी भागीदारी होती है अत: चुनाव आयोग को इन राजनीतिक दलों के नियमन का अधिकार भी दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि देश के लोकतन्त्र के कर्णधार इन दलों के भीतर भी पूरी तरह से लोकतन्त्र हो। अत: राजनीतिक दलों की जवाबदेही चुनाव आयोग के प्रति भी तय की गई। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के विवादों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग को कुछ न्यायिक अधिकार भी दिये गये। इसीलिए हम देखते हैं कि जब किसी राजनीतिक दल के भीतर बंटवारे या अन्य किसी आन्तरिक मुद्दे पर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निपटारा चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है।

भारत में ऐसा पहला मामला 1969 में तब आया था जब केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था और तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी को दो भागों में विभाजित कर दिया था । उस समय चुनाव आयोग में एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे । तब इस पद पर स्व. एस.पी. सेनवर्मा थे। इस विवाद के दौरान कांग्रेस पार्टी की सम्पत्ति से लेकर उसके चुनाव निशान (दो बैलों की जोड़ी) तक पर पार्टी के दोनों गुटों ने अपना– अपना दावा चुनाव आयोग के समक्ष ठोका था। यह प्रकरण इसलिए इतिहास में दर्ज हो चुका है क्योंकि तब मुख्य चुनाव आयुक्त एस.पी. सेनवर्मा पर सत्ता पर काबिज इन्दिरा गांधी गुट के कांग्रेस धड़े का कोई प्रभाव नहीं चला था और उन्होंने अपना फैसला पूरी तरह निष्पक्ष रहते हुए हर मुद्दे पर दिया था। एस.पी. सेनवर्मा ने कांग्रेस के चुनाव निशान दो बैलों की जोड़ी को जब्त कर लिया था और इसके स्थान पर कांग्रेस के दोनों धड़ों को अलग-अलग चुनाव निशान दे दिये थे। यह समय उस दौर के इस फैसले की तफसील में जाने का नहीं है बल्कि मन्तव्य यह है कि चुनाव आयोग का काम इस तरह चलना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल को उसकी नीयत पर शक करने की हिम्मत न हो। ठीक ऐसी ही स्वतन्त्र व निष्पक्ष भूमिका चुनाव आयोग ने तब भी निभाई थी जब इमरजेंसी समाप्त होने पर मार्च 1977 में चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव कराये थे जिनमें देश के प्रधानमन्त्री पद पर रहते हुए ही श्रीमती इन्दिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव हार गई थीं। इसके बाद 90 के दशक मे मुख्य चुनाव आयुक्त स्व. टी.एन. शेषन बने और चुनावों की प्रक्रिया को लेकर कई प्रकार के संशोधन किये जिनकी वजह से वह अक्सर चर्चा में रहा करते थे। भारतवासी जानते हैं हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था जिन चार पायों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व चुनाव आयोग पर टिकी हुई है उनमें दो पाये न्यायपालिका व चुनाव आयोग सरकार के अंग नहीं बनाये गये हैं । इसकी वजह यही है कि भारत की राजनीतिक शासन व्यवस्था में हर हाल में संविधान का ही शासन रहे। इस सिलसिले में चुनाव आयोग की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रखी गई है बल्कि संविधान निर्माताओं ने उस पर जिम्मेदारी डाली है कि वह केवल संविधान के प्रति वफादार रहने वाली राजनीतिक पार्टियों को ही मान्यता देकर भारत में राज्य स्तर से लेकर केन्द्र स्तर तक हर पांच साल बाद चुनाव करा कर सरकारों के गठन का मार्ग प्रशस्त करे। इस काम को चुनाव आयोग संविधान की रुह के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदाता बना कर ही करता है। अत:भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो भी भारतीय नागरिक 18 वर्ष की आयु को पा लेता है वह मतदाता बनने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह भारत की बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप मतदाताओं की संख्या भी बढ़ाता रहे। परन्तु संविधान ही चुनाव आयोग को यह अधिकार भी देता है कि वह केवल वैध भारतीय नागरिकों को ही मतदाता बनाये और कोई भी अवैध व्यक्ति मतदाता न बन सके। इसके लिए चुनाव आयोग को समय–समय पर मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार भी मिला हुआ है। वर्तमान समय में इसी पुनरीक्षण कार्रवाई को लेकर देश के प्रमुख विपक्षी दलों में चुनाव आयोग के प्रति गुस्सा है क्योंकि आयोग जिस राज्य में भी पुनरीक्षण का काम कर रहा है वहीं लाखों की संख्या मे मतदाताओं के नाम सूची से काट रहा है। अत: राजनैतिक दलों का कहना है कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग मतदाताओं के सामने एसे कागजात भरने की शर्ते लगा रहा है जिनका उनके **दैनन्दिन** जीवन से ज्यादा लेना-देना नहीं रहता है और अथक प्रयास करने पर उन्हें ये कागजात सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद बनवाने पड़ते हैं। यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी गया जहां से मतदाताओं को राहत मिली क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वैध मतदाता की पहचान करने के लिए उसका आधार कार्ड भी पर्याप्त सबूत माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तब हस्तक्षेप किया था जब बिहार में वहां होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही चुनाव आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू किया था।

शुरू में चुनाव आयोग ने मतदाताओं से जिन 11 कागजात दिखाने की मांग की थी उनमें आधार कार्ड को शामिल ही नहीं किया गया था। इसके बाद उसने अन्य राज्यों में पुनरीक्षण का काम शुरू किया जिसका सबसे ज्यादा विरोध प. बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी ने किया । उन्होंने चुनाव आयोग पर बहुत भीषण आरोप भी लगाये और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार पर अहंकारी होने के आरोप भी लगाये। मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी गया और वहा पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाये गये जिस पर न्यायालय ने ममता दीदी को कुछ राहत भी दी । वैसे गौर से देखा जाये तो जिन-जिन राज्यों में भी विपक्षी दलों की सरकारें हैं सभी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाये मगर इसका मतलब यह नहीं है कि संसद में ही विपक्षी दल मिल कर ज्ञानेश कुमार को पद मुक्त करने के लिए महाभियोग लेकर आ जायें। भारत का लोकतन्त्र इस व्यवस्था के तहत सृजित विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की पवित्रता व साफगोई के भरोसे चलता है जिनसे भारी मतभेद भी हो सकते हैं अत: उनके कामकाज को दुरुस्त कराने के लिए कई प्रकार के लोकतान्त्रिक हथियार भी होते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि श्री ज्ञानेश कुमार राजनीतिक भेदभाव करते हैं और उनका व्यवहार भी उचित नहीं रहता तथा वह भारी संख्या में मतदाताओं का नाम काट रहे हैं जो कि लोकतान्त्रिक दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता। परन्तु भारत में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का तो मूल विधान संविधान में था कि उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे परन्तु उन्हें हटाने का कोई सरल तरीका नहीं था अत: यह विचारा गया कि उन्हें भी संसद की सर्वोच्चता को देखते हुए केवल महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है किन्तु 2023 में मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सम्बन्धी जो विधान बनाया उसके अनुसार चुनाव आयुक्त को भी पदमुक्त करने की प्रणाली वही होगी जो कि किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है।

इसके अनुसार चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव संसद में आयेगा उस पर लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिएँ। विपक्ष में तृणणूल कांग्रेस की ओर से एसे प्रस्ताव को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई जिस पर लोकसभा व राज्यसभा के मिला कर 193 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिये अत: यह प्रस्ताव जो कि राष्ट्रपति को सम्बोधित है लोकसभा सचिवालय को सौप दिया गया है । यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में विचारार्थ स्वीकृत कर लिया जाता है तो अध्यक्ष एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करेंगे , यह समिति अपनी जांच के आधार पर आरोप पत्र अध्यक्ष को सौंपेगी । इसके बाद अध्यक्ष उसे सदन में रखेंगे और यदि जांच में पाया जाता है कि आरोपों में सत्यता है तो वह इसे बहस कराने के लिए पेश कर देंगे परन्तु प्रस्ताव पारित होने के लिए सदन के दो तिहाई बहुमत की जरूरत इस शर्त के साथ होगी कि मतदान के समय सदन में सदस्यों की उपस्थिति उसकी कुल शक्ति के 50 प्रतिशत से ज्यादा हो। परन्तु विपक्ष की यह सारी कवायद केवल सांकेतिक ही होगी क्योंकि संसद के दोनों सदनों में सत्ताधारी भाजपा के एनडीए समूह का पूर्ण बहुमत है। अभी दो दिन पहले ही लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है, परन्तु यह भी हकीकत है कि लोकतन्त्र में सांकेतिक कृत्यों का कम महत्व नहीं होता क्योंकि इस प्रणाली में जन अवधारणा की महत्ता सबसे ऊपर मानी जाती है।

रवि के तबादले से स्टालिन खुश, ममता नाराज

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

तमिलनाडु का फ़ायदा, पश्चिम बंगाल के लिए मुसीबत बन सकता है। गवर्नर आर.एन. रवि के तबादले पर दोनों राज्यों में बिल्कुल अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। तमिलनाडु में खुशी मनाई गई, तो पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुए। चेन्नई में सत्ताधारी डीएमके सरकार के लिए रवि एक कांटे की तरह थे, क्योंकि कई मुद्दों पर उनके बीच अक्सर टकराव होता रहता था। इसलिए, जब उनके तबादले का ऐलान हुआ, तो डीएमके नेता सुखद रूप से हैरान रह गए। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तंज कसते हुए कहा कि वे तो असल में चाहते थे कि रवि वहीं बने रहें, क्योंकि उनके "जन-विरोधी कामों" से आने वाले विधानसभा चुनावों में डीएमके को फ़ायदा मिल रहा था। तमिलनाडु के मंत्री टी.आर.बी. राजा ने ट्वीट किया कि रवि, हम तुम्हें याद करेंगे!" वहीं, डीएमके सांसद पी. विल्सन ने ट्वीट किया कि डीएमके ने रवि के रूप में अपना एक "स्टार प्रचारक" खो दिया है। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बदलाव से अपनी नाराज़गी नहीं छिपा पाईं। उन्होंने कहा कि गवर्नर के पद से सी.वी. आनंद बोस के अचानक इस्तीफ़े की ख़बर सुनकर उन्हें "गहरा सदमा लगा है और वे बेहद चिंतित हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया, बोस के ख़िलाफ़ उनके पहले के विरोध प्रदर्शनों से बिल्कुल उलट थी; बोस के साथ भी उनके कई बार टकराव हुए थे। हालांकि, रवि और डीएमके सरकार के बीच जिस तरह का टकराव था, उसके मुक़ाबले बोस के साथ हुए ये टकराव बहुत ही मामूली थे। रवि ने न सिर्फ़ तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों को मंज़ूरी देने से साफ़ इनकार कर दिया, बल्कि उनके नाम यह रिकॉर्ड भी दर्ज है कि वे इतिहास के एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं, जिन्होंने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर दिए गए अपने भाषणों में, सत्ता में बैठी सरकार की ही आलोचना की। रवि के टकराव वाले रवैये से डरकर, बनर्जी ने कहा कि उन्हें शक है कि उन्हें कोलकाता भेजने के इस फ़ैसले में कोई साज़िश ज़रूर है। टीएमसी के गलियारों में इस बात की ज़ोरदार चर्चा है कि विधानसभा चुनाव टाले जा सकते हैं और राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। दरअसल, बोस भी अपने इस अचानक इस्तीफ़े से काफ़ी नाराज़ और दुखी लग रहे थे। बताया जाता है कि इस्तीफ़ा सौंपने के बाद वे तुरंत गवर्नर हाउस से बाहर निकल गए और अपना सामान पैक करने का काम अपनी पत्नी पर छोड़ गए।

ट्यूलिप फ़ेस्टिवल जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ा

दिल्ली का मशहूर ट्यूलिप फ़ेस्टिवल इस साल जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ गया। इसकी शुरुआत 23 फ़रवरी को हुई थी और इसे 10 मार्च तक चलना था। लेकिन, एक हफ्ते से भी कम समय में, चिलचिलाती धूप की वजह से सारे फूल मुरझा गए और नष्ट हो गए। पिछले पांच सालों से, दिल्ली के अधिकारी नीदरलैंड्स से ट्यूलिप के बल्ब मंगवा रहे हैं और उन्हें राजधानी के खास गोलचक्करों पर और शांतिपथ के दोनों किनारों पर लगा रहे हैं। शांतिपथ राजनयिक इलाके से होकर गुज़रता है। इस साल भी, लगभग 2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 5 लाख बल्ब मंगवाए गए। बदकिस्मती से, फरवरी का महीना उम्मीद से कहीं ज़्यादा गर्म रहा। असल में, दिल्ली में पिछले तीन सालों में फरवरी का महीना सबसे ज़्यादा गर्म रहा, और मार्च में तो तापमान और भी बढ़ गया; महीने का पहला शनिवार पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म दिन साबित हुआ। ट्यूलिप ठंडी जगहों के लिए बने होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों की कामयाबी ने दिल्ली सरकार को और भी ज़्यादा उत्साहित कर दिया था। इसलिए इस साल, उन्होंने जितनी ज़्यादा हो सकें, उतनी ट्यूलिप लगाने की पूरी कोशिश की। ट्यूलिप फेस्टिवल अब दिल्ली वालों के लिए एक बहुत ही खास और पसंदीदा कार्यक्रम बन गया है। लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर इन नाज़ुक फूलों के साथ सेल्फ़ी और तस्वीरें लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत निराशा हुई कि ज़्यादातर फूल तो मुरझा चुके थे; वहां बस सूखी डंडियाँऔर सूखी मिट्टी ही बची थी। राजधानी में वसंत के इस खास आकर्षण के इस तरह खत्म हो जाने की एकमात्र वजह जलवायु परिवर्तन ही नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि फूल देर से खिले, और फरवरी की उस बेमौसम गर्मी की चपेट में आ गए।

किसानों ने ईरान के पक्ष में प्रदर्शन करके अमेरिका से जताई नाराजगी

हाल ही में, पंजाब के किसानों ने ईरान के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। कश्मीर के बाद पंजाब दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसने ईरान के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति ज़ाहिर की है। ऐसा लगता है कि पंजाब के किसान हाल ही में हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि इस समझौते के तहत कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल देने से उन पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए, अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने का एक तरीका उन्होंने यह निकाला कि वे ईरान के साथ अपनी एकजुटता दिखाएं, और इस तरह ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमलों का विरोध करें।

किसानों के इस मिज़ाज को समझते हुए, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता सबसे पहले उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने ईरान में अमेरिका और इज़रायल की कार्रवाई की आलोचना की। दूसरी प्रमुख हस्ती कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी थीं; उन्होंने एक अख़बार में लिखे अपने लेख के ज़रिए अपनी गहरी चिंता ज़ाहिर की, और मोदी सरकार से यह अपील की कि वह ईरान के साथ खड़ी हो। यह बात भी गौर करने लायक है कि सोनिया गांधी का वह आलोचनात्मक लेख छपने के कुछ ही दिनों बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे। वहां उन्होंने, मारे गए नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए रखी गई शोक-पुस्तिका पर अपने हस्ताक्षर किए।

भारत की दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति को मजबूत बनाना

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने विश्व ऊर्जा कीमतों पर व्यापक प्रभाव डाला है, जिससे कुछ ही दिन पहले कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। तब से, कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं, जिससे पूरा ऊर्जा बाजार तनाव में है। वैश्विक चिंता के केंद्र में होर्मुज जलडमरूमध्य है, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट है, जिससे होकर वैश्विक कच्चे तेल का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। होर्मुज जलडमरूमध्य भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। पिछले 11 वर्षों में, भारत ने सक्रिय रूप से अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाई है। भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण को बदलने के लिए भी काम किया है, और घरेलू स्तर पर उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है।

कल्पना कीजिए, अगर यह संकट भारत में एक दशक पहले आया होता। हमारे लगभग सभी तेल और गैस एक ही अस्थिर क्षेत्र से आते और कोई ठोस विकल्प मौजूद नहीं रहता, तो इसका प्रभाव विनाशकारी होता। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रातों-रात आसमान छू जातीं, जिससे परिवहन व्यवस्था ठप्प हो जाती और महंगाई बेतहाशा बढ़ जाती। भारत इस संकट से उत्पन्न उथल-पुथल से अपेक्षाकृत अछूता रहा है। इसके विपरीत, अन्य देश काफी संघर्ष कर रहे हैं। जापान, जो पहले से ही रिकॉर्ड-उच्च सार्वजनिक ऋण से बोझिल है, सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। गैस पर निर्भर ब्रिटेन में कीमतों में तत्काल वृद्धि देखी गई है, जिससे मुद्रास्फीति फिर से बढ़ गई है। मिस्र और तुर्की जैसे देश नए मुद्रास्फीति दबावों का सामना कर रहे हैं। सिंगापुर बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि से जूझ रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया ने तेल की कीमतों में उछाल के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए लगभग तीन दशकों में पहली बार ईंधन की कीमतों पर सीमा लगा दी है। इसलिए वर्तमान संकट एक महत्वपूर्ण सबक देता है, भारत की आज की सापेक्षिक लचीलापन कोई संयोग नहीं है। यह पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और घरेलू क्षमता को मजबूत करने के लिए किए गए सुनियोजित नीतिगत निर्णयों का परिणाम है।

पिछले एक दशक में भारत ने लगातार इसी दिशा में प्रगति की है। बहुआयामी कूटनीति की रणनीति के माध्यम से, देश ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार 27 देशों से बढ़ाकर 40 से अधिक देशों तक कर दिया है, जिससे किसी एक आपूर्तिकर्ता या क्षेत्र पर निर्भरता कम हो गई है। विश्व के किसी भी हिस्से में आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में, यह व्यापक नेटवर्क भारत को समायोजन करने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इस प्रकार, सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखने से हमें संकट से उबरने में मदद मिली है। साथ ही, भारत ने अपनी घरेलू ऊर्जा क्षमता के विस्तार में तेजी लाई है। पिछले 11 वर्षों में देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता दोगुनी से अधिक हो गई है और अब 520 गीगावॉट से अधिक हो गई है, जिसमें से आधे से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा सहित गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होती है। स्वच्छ ऊर्जा के इस तीव्र विस्तार के बिना, बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भारत आज आयातित ईंधनों पर कहीं अधिक निर्भर होता। इस बदलाव का एक अन्य सबसे स्पष्ट उदाहरण प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसका उद्देश्य एक करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल लगाना है। इससे परिवारों को अपनी बिजली खुद पैदा करने में मदद मिली है, विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिला है और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर दबाव कम हुआ है। घरेलू बिजली बिलों को कम करने के अलावा, इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी हैं। भारत का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र 2014 में मात्र 2,600 इलेक्ट्रिक वाहनों से बढ़कर 2025 में 16.71 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तक तेजी से पहुंचा है, जो स्वच्छ परिवहन को तेजी से अपनाने का संकेत है। इस परिवर्तन में सरकारी नीतियों ने अहम भूमिका निभाई है। FAME-I योजना (2015) ने लगभग 2.78 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन दिया, जिससे लगभग 5 करोड़ लीटर ईंधन की बचत हुई। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ रहा है, इसका प्रभाव स्वच्छ परिवहन से कहीं अधिक व्यापक हो रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा का विद्युत गतिशीलता के साथ एकीकरण एक शक्तिशाली गुणक प्रभाव पैदा करता है। पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत पहले से ही काफी कम है। जब इलेक्ट्रिक वाहनों को घर पर उत्पन्न सौर ऊर्जा से चार्ज किया जाता है, तो परिवहन न केवल स्वच्छ बल्कि काफी सस्ता भी हो जाता है। इसका व्यापक प्रभाव आर्थिक और रणनीतिक दोनों है। ईंधन आयात में कमी से न केवल वायु गुणवत्ता और गतिशीलता में सुधार होता है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को बाहरी तेल संकटों से भी बचाता है, जैसे कि वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हो रहे हैं। भारत ने भू-राजनीतिक संकटों के दौरान आपूर्ति में व्यवधान की तैयारी के लिए पिछले दशक में अपनी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) क्षमता को भी मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पडूर में रणनीतिक भंडार के साथ अपने आपातकालीन तेल भंडारण अवसंरचना का विस्तार किया, जबकि चांदीखोल और पडूर चरण-II में अतिरिक्त सुविधाओं की शुरुआत की। परिणामस्वरूप, आज भारत के पास इतना तेल भंडार है जो रणनीतिक भंडार और व्यावसायिक भंडार को मिलाकर देश की ज़रूरतों को लगभग 74 दिनों तक पूरा कर सकता है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

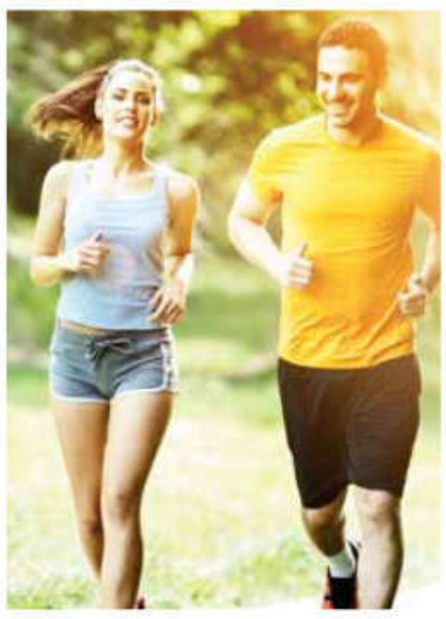

वॉक, जॉगिंग या दौड़ना, जल्दी वजन घटाने के लिए ये हैं अच्छे और इनके अलग-अलग फायदे

फिटनेस का एक ही मंत्र है एक्टिव रहना, शरीर स्वस्थ रखने के लिए रोजाना किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। शरीर को चलाने के लिए वॉक करना, जॉगिंग करना और रनिंग करना बेस्ट एक्सरसाइज हैं। आप इसमें से कुछ भी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। हालांकि तेजी से वजन घटाने के लिए वॉक, जॉगिंग और रनिंग में से क्या बेस्ट है। आइये जानते हैं, कौन से व्यायाम से मोटापा सबसे जल्दी कम होता है?

वॉक के फायदे

अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो इससे शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहते हैं। रोजाना 1 घंटे की वॉक करने से मोटापा कम होता है। दौड़ने से मांसपेशियां मजबूत बनती है और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। रनिंग से याददाश्त में सुधार आता है और पूरी सेहत कुछ ही दिनों में दिल की बीमारियों को दूर रखने के लिए वॉक सबसे अच्छी मानी जाती है। रोज कुछ देर टहलने से ब्लड शुगर लेवल कम होता है इससे डायबिटीज के मरीज की मुश्किलें कम हो सकती हैं। वॉक करने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। हाइपरटेंशन के मरीज को रोजाना वॉक करनी चाहिए। जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए भी वॉक असरदार व्यायाम है।

जॉगिंग के फायदे

अगर आप रोज कुछ देर जॉगिंग करते हैं तो इससे वजन घटाने पर कहीं ज्यादा तेजी से असर होता है। जॉगिंग में आपकी स्पीड रनिंग से कम होती है लेकिन आप वॉक से तेजी से चलते हैं। जॉगिंग को आप लंबे समय तक बिना थके कर सकते हैं। 30 मिनट की जॉगिंग करने से तेजी से वजन कम होता है। इससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और आपके शरीर पर असर जल्दी नजर आता है। जॉगिंग करना हार्ट के लिए बेस्ट कार्डियो एक्सराइज है। इसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं।

रनिंग के फायदे

दौड़ना एक हाई इंटेंसिटी का फुल बॉडी वर्कआउट है। तेजी से कैलोरी बर्न करने के लिए रोजाना आधा घंटे दौड़ना काफी हो सकता है। वजन घटाने के लिए रनिंग को बेस्ट माना जाता है। रनिंग करने से दिल मजबूत बनता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। इससे शरीर में बढ़ी हुई चीजें जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर तेजी से कम होता है। रनिंग करने से शारीरिक ही नहीं मानसिक तनाव भी कम होता है। दौड़ने से मांसपेशियां मजबूत बनती है और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। रनिंग से याददाश्त में सुधार आता है और पूरी सेहत कुछ ही दिनों में सुधर जाती है।

अगर आपको तेजी से वजन घटाना है तो इसके लिए रनिंग बेस्ट है। रनिंग करने से सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती हैं। हालांकि लंबे समय तक इसे बरकरार रखने के लिए आप जॉगिंग और वॉक अपना सकते हैं। रोजाना वॉक करने और कुछ देर की जॉगिंग से आप जिंदगी भर हेल्दी वजन को मेंटेन कर सकते हैं। इससे आपकी ओवरऑल सेहत भी बेहतर रहेगी। वॉक आप बढ़ती उम्र में भी बरकरार रख सकते हैं। जबकि एक उम्र के बाद दौड़ना मुश्किल हो जाता है। ●

दूसरों की गलती से भी आपको हो सकता है कैंसर

कैंसर दुनियाभर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तेजी से बढ़ता सबसे गंभीर संकट है, जो हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनता है। आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के वर्षों में हर साल कैंसर से करीब 96 लाख से एक करोड़ मौतें दर्ज की गई हैं। कैंसर से होने वाली मौतों में फेफड़ों का कैंसर सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद कोलोरेक्टल और लिवर कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कैंसर के चलते आने वालों वर्षों में मौत के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कोशिकाओं के अंदर डीएनए में बदलावों के कारण ये जानलेवा बीमारी होती है। ये आनुवंशिक कारणों से लेकर जीवनशैली से जुड़ी आदतों जैसे तंबाकू, खान-पान में गड़बड़ी, मोटापा और कुछ तरह की पर्यावरणीय स्थितियों की वजह से भी बढ़ रही है। लाइफस्टाइल में सुधार करके आप कैंसर के खतरे को काफी कम कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दूसरों की गलती की वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है?

धूम्रपान न करने वालों में लंग्स कैंसर

लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर दुनियाभर में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। आमतौर पर माना जाता रहा है कि फेफड़ों का कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने वालों को होता है, हालांकि ये खतरा उन लोगों में भी बढ़ रहा है जिन्होंने कभी सिगरेट पी ही नहीं। फेफड़ों के कैंसर के कई मामलों में देखा गया है कि लोगों की लाइफस्टाइल तो ठीक है, वो धूम्रपान भी नहीं करते फिर भी उनमें कैंसर हो गया। इसका मतलब है कि आप दूसरों की गलतियों की वजह से भी इस घातक कैंसर की चपेट में आ सकते हैं।

दुनियाभर में बड़ी संख्या में नॉन-स्मोकर्स यानी जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, उनमें भी लंग्स कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। जहां रसायनों के अक्सर संपर्क में अधिक रहते हैं उनमें भी लंग्स कैंसरये दूसरे के सिगरेट से होने वाले धुएं के संपर्क में आने की वजह से हो सकता है। ●

कैंसर का बढ़ता जोखिम

डॉक्टर कहते हैं, जब फेफड़ों की कोशिकाओं में असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, तो कैंसर हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण धूम्रपान है। सिगरेट के धुएं में 70 से अधिक कैंसर पैदा करने वाले रसायन पाए जाते हैं, जो कैंसर को बढ़ा सकते हैं। हालांकि सिर्फ धूम्रपान ही नहीं, सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी दूसरों के धुएं में रहने से भी आपमें इस कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। आप धूम्रपान नहीं करते हैं पर यदि आपमें कैंसर की फैमिली हिस्ट्री रही है तो भी लंग्स कैंसर को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। ●

ऐसीखांसी जो ठीक न हो रही हो या समय के साथ और बिगड़ जाए।
खांसी के साथ खून आना या गाढ़े रंग का बलगम आना।
सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, घरघराहट या सांस लेते समय आवाज आना।
लगातार सीने में दर्द बने रहना जो अक्सर गहरी सांस लेने, हंसने या खांसने पर और बढ़ जाता है। ●

दमकती त्वचा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

चेहरे की खूबसूरती हर किसी के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर चेहरे पर कुछ भी लग जाए या कट जाए, तो आपके चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। इसके लिए कई लोग तरह-तरह के फेस पैक, क्रीम का यूज करते हैं। ठीक वैसे ही अगर आंखों के नीचे काले धब्बे दिखने लगते हैं, तो कोई भी आपको टोक सकता है। इसके चक्कर में आप तरह-तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। ऐसे में इस समस्या के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से काले घेरे को दूर कर सकते हैं। आइए जानें-

नींबू का रस

नींबू में विटामिन सी होता है जो त्वचा को निखारता है और काले घेरों को कम करने में मदद कर सकता है। नींबू के रस को घेरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें।

आलू का रस

आलू में विटामिन ई होता है जो त्वचा के रंग को निखारता है और काले घेरों को कम कर सकता है। आलू को पीसकर उसका रस निकालें और इसे घेरे पर लगाएं। 15-20 मिनट तक ऐसे ही रखें, जब सूख जाए, तो फिर धो लें।

शहद और नींबू

शहद और नींबू का मिश्रण बनाकर इसे घेरे पर लगाएं। इससे आंखों पर आए काले घेरे कम होंगे।

बेसन और दही

बेसन में थोड़ा सा नींबू का रस और दही मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। इसे अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ें और फिर हल्के हाथों से मसाज करें। फिर पानी से धो लें।

एलोवेरा जेल

एलोवेरा का जेल काले घेरों को कम करने में मदद कर सकता है। एलोवेरा जेल निकालकर उसे घेरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। ●

औषधीय गुणों से भरपूर हरे रंग का पानी

साधारण सी दिखाई देने वाली ये ड्रिंक आपकी सेहत को काफी हद तक सुधार सकती है। पोषक तत्वों से भरपूर हरे रंग का पानी आंवला का पानी है। पुराने जमाने से आंवले को सेहत के लिए वरदान माना जाता रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंवला का पानी भी सेहत को चौतरफा लाभ पहुंचा सकता है। अगर आप आंवले का पानी पीते हैं, तो सेहत से जुड़ी किन गंभीर समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है

कंट्रोल करे कोलेस्ट्रॉल-शुगर- कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाने के लिए आंवले का पानी पी सकते हैं। अगर आप दिल से जुड़ी गंभीर और जानलेवा बीमारियों के खतरे को कम करना चाहते हैं, तो आप इस ड्रिंक को कंज्यूम करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, उन्हें भी आंवले का पानी पीकर देखना चाहिए। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी आंवले का पानी पिया जा सकता है।

वजन घटाने में कारगर- बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए आंवले का पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, शरीर में जमा जिद्दी चर्बी से छुटकारा पाना चाहते हैं, मोटापे को अलविदा कहना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज के साथ-साथ इस ड्रिंक को अपने डाइट प्लान में शामिल कर लीजिए। विटामिन सी से भरपूर आंवले का पानी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

एसिडिटी, गैस और अपच- आंवले का पानी आपकी गट हेल्थ को सुधारने में कारगर साबित हो सकता है। अगर आप एसिडिटी, गैस और अपच जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं के खतरे को कम करना चाहते हैं, तो आंवले का पानी पीना शुरू कर सकते हैं। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सुबह-सुबह खाली पेट औषधीय गुणों से भरपूर आंवले का पानी पीना चाहिए। इस ड्रिंक के टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप थोड़े से शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ●

हल्के में न लें हाइपरटेंशन की समस्या

बर्नआउट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है, जो पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गई है। देश में 60त्न नौकरीपेशा इस परेशानी से जूझ रहे हैं। दरअसल, हाई पोजीशन, अच्छे सैलेरी पैकेज और लग्जरी के पीछे दौड़ते लोग अपनी सेहत और पर्सनल लाइफ को दांव पर लगा देते हैं। तनाव से लड़ने की कैपेसिटी, एनर्जी, नींद और इम्यूनिटी घटने लगती है और तो और हार्ट और पाचन तंत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर पर पड़ता है असर- बर्नआउट सिंड्रोम से न केवल चिड़चिड़ापन, एंगर, हर वक्त थकान, शुगर, मसल पेन ट्रिगर होने लगता है बल्कि ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। ब्लड प्रेशर से पहले बर्नआउट सिंड्रोम से बचने के उपाय के बारे में जानते हैं। ऑफिस में काम करने के घंटों को 30-30 मिनट में बांट लीजिए और हर 30 मिनट में 20 मिनट बैठकर काम कीजिए, 8 मिनट खड़े होकर फिर 2 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए।

योग-ध्यान-प्राणायाम- ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के लिए योग-ध्यान-प्राणायाम की मदद ली जा सकती है। हाइपरटेंशन पर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ सकता है। हाइपरटेंशन के कारण वेन्स में दबाव बढ़ता है, दिमाग की नसें फट जाती हैं, खून निकलने लगता है और ब्रेन हैमरेज हो जाता है। हाई बीपी से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, भी बढ़ सकता है। ●

केसरी सूडोकू- 5108

			8		2		6	
					4	3		7
3		2					1	
	7	1			6		8	
	4		7			6	9	
	6					5		2
4		8	2					
	9		3	7				

हल करने का तरीका

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।
- आड़ी व खड़ी पंक्ति में और 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

सूडोकू 5107 का हल

9	6	2	1	8	7	5	3	4
3	5	7	4	2	6	1	9	8
4	1	8	9	5	3	2	7	6
8	2	1	3	4	5	7	6	9
7	4	6	2	1	9	8	5	3
5	3	9	6	7	8	4	2	1
2	8	3	7	6	4	9	1	5
1	9	5	8	3	2	6	4	7
6	7	4	5	9	1	3	8	2

हिम्मत और दृढ़ता के पास जादुई तावीज होता है, जिसके सामने मुश्किलें लुप्त हो जाती हैं और बाधाएं हवा में नष्ट हो जाती हैं।

– जान क्विंसी एडम्स

महंगाई की आंच

जब किसी भी तरह के रोजगार से आय का स्तर ठहरा हुआ हो, जरिया सीमित हो, तो आम आदमी की उम्मीद यही होती है कि बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमतें उसकी पहुंच में हों या फिर कम से कम स्थिर रहें। मगर पिछले कुछ वर्षों से आमदनी की तुलना में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को जितना खर्च करना पड़ रहा है, वह कई बार भारी पड़ता है। माना जाता है कि दिसंबर से फरवरी तक की अवधि में बाजार में सब्जियों की आवक ज्यादा होने की वजह से महंगाई काबू में रहेगी। मगर सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में खुदरा महंगाई फरवरी में बढ़ कर 3.21 फीसद हो गई। हालांकि जनवरी में यह 2.74 फीसद के स्तर पर रही थी। जाहिर है, सिर्फ एक महीने के भीतर जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेज इजाफा हुआ और यह पिछले दस महीने के सबसे उच्च स्तर पर दर्ज किया गया। कहा जा सकता है कि फरवरी के आंकड़े के मुताबिक महंगाई दर चार फीसद से नीचे है, लेकिन यह भी देखने की जरूरत है कि कीमतों के संदर्भ में जरूरी सामान तक आम लोगों की पहुंच किस हद तक आसान है।

यह छिपा नहीं है कि रोजगार और आय की कसौटी पर देश की ज्यादातर आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। लंबे समय से स्थिर आमदनी और कमजोर क्रयशक्ति की स्थिति में जब सबसे जरूरी चीजों पर लोगों का खर्च थोड़ा भी बढ़ता है, तो उसके लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। फरवरी में महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण दरअसल खाने-पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी रहा। खुदरा महंगाई से इस बात का पता चलता है कि ग्राहकों की खपत और खर्च की स्थिति क्या है। इसी वजह से रिजर्व बैंक अपनी नीति तय करते समय खुदरा महंगाई को ही अपना आधार बनाता है। अगर खुदरा महंगाई की दर उसके तय दायरे यानी चार फीसद के बाहर चली जाती है तो फिर कर्ज के सस्ता होने की उम्मीद भी कम हो जाती है। महंगाई के ताजा आंकड़े फरवरी के हैं, जब पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात नहीं थे। अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की साझा जंग चल रही है, उसका बाजार में थोक और खुदरा महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

दरअसल, युद्ध की वजह से तेल की सहज आपूर्ति को लेकर पहले ही कई तरह की आशंकाएं उभर रही थीं कि इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के समुद्री मार्ग को बाधित कर दिया। इसके बाद उस रास्ते से भारत में भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति व्यापक पैमाने पर बाधित हुई है और इसका असर बाजार पर पड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल खाना पकाने वाले गैस की कीमत में इजाफा और गैस सिलेंडरों की कमी की आशंका में लोगों के बीच मची अफरा-तफरी देखी जा सकती है। ऐसे में इस बात की आशंका गहरा रही है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा और कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित रही, तो भारत में भी पेट्रोल-डीजल के दाम पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है। इसके बाद माल ढुलाई में बढ़ोतरी के साथ स्वाभाविक रूप से बाजार में मौजूद सभी चीजें महंगी होंगी। जाहिर है, सरकार को आने वाले दिनों में हालात का आकलन कर महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है।

दावे के बरक्स

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे करती रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। मगर पिछले कुछ समय से लगातार अपराध, लूटपाट और हत्या के बढ़ते मामलों ने दावों की कलई खोल दी है। अपराधी बेशक बाद में पकड़ लिए जाते हों, लेकिन सच है कि वे वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। सवाल है उनके भीतर पुलिस का खौफ क्यों नहीं दिखता। पिछले दिनों संभल में कुछ लोग एक युवक को घर से खींच कर ले गए और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि बदायूं में गुरुवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इथेनाल संयंत्र के दफ्तर में घुस कर दो वरिष्ठ अधिकारियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि काली सूची में डाले गए एक विक्रेता ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की कार पर हमला कर चुका था। जब इस मामले की पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर शिकायत दर्ज करा दी गई थी, तो आरोपी पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल यह भी है कि उच्च सुरक्षा वाले संयंत्र में हथियार लेकर वह कैसे घुसा? कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के पास इसका क्या जवाब है?

उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो स्पष्ट है कि राज्य के पूरे पुलिस तंत्र में समन्वय का अभाव है। आए दिन हो रहीं हत्या की घटनाओं से समझा जा सकता है कि राज्य में अपराध पर लगाम लगने के दावे में दम नहीं है। जमीनी सच्चाई यही है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस की तमाम कथित सख्ती और सक्रियता के बावजूद आपराधिक मानसिकता के लोगों में कानून और सजा का कोई डर नहीं है। ऐसा लगता है कि अपराध नियंत्रण में कहीं न कहीं कमजोर कड़ी रह गई है, जिसकी शिनाख्त नहीं की जा रही है। आज स्थिति यह है कि लोग खुद को घरों से लेकर दफ्तरों तक सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। आए दिन जघन्य अपराधों के मद्देनजर उनकी चिंताएं नाहक नहीं हैं। सवाल है कि राज्य सरकार अपराध और अपराधियों पर काबू करने के जो दावे करती रही है, हकीकत उसके उलट क्यों दिख रही है।

जैव विविधता के साथ टिकाऊ विकास

लंबे राजमार्गों ने व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को नई गति दी है, लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक आवासों की क्षति, पेड़ों की कटाई और जैव विविधता पर दबाव भी बढ़ा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मधुमक्खियों की संख्या लगातार घटती रही, तो खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है।

विनीता परमार

भारत में विकास की कहानी अक्सर सड़कों की लंबाई और गति से मापी जाती है। एक्सप्रेस-वे, चौड़ी होती राष्ट्रीय राजमार्गों की पट्टियां और तेज रफ्तार यातायात- ये सब मिलकर आधुनिक भारत के बुनियादी ढांचे की पहचान बन चुके हैं। हजारों किलोमीटर लंबे राजमार्गों ने व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को नई गति दी है, लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक आवासों की क्षति, पेड़ों की कटाई और जैव-विविधता पर दबाव भी बढ़ा है। परागणकर्ता, विशेषकर मधुमक्खियां इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित जीवों में शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मधुमक्खियों की संख्या लगातार घटती रही, तो खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में दुनिया की फसलें परागण पर निर्भर हैं। वैश्विक खाद्य उत्पादन का लगभग (एक-तिहाई) हिस्सा सीधे तौर पर मधुमक्खियों और अन्य परागणकों पर निर्भर करता है। एक अध्ययन के अनुसार, परागण करने वाले कीटों की आबादी में काफी गिरावट आई है।

इस बात की गंभीरता को देखते हुए देश के राजमार्ग अब केवल तेज रफ्तार यातायात की रेखाओं के समांतर धीरे-धीरे जैव विविधता के जीवित गलियारों में बदलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 'मधुमक्खी गलियारे' (बी-कारिडोर) विकसित करने की पहल जैव विविधता के संरक्षण की सोच का संकेत है। इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत 2026-27 तक लगभग चालीस लाख पेड़ और फूलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के लिए सुरक्षित आवास बनाकर पारिस्थितिकी संतुलन को मजबूत करना है। बी-कारिडोर का मतलब है राजमार्गों के किनारे पेड़ों और फूलों की ऐसी हरित पट्टी, जो मधुमक्खियों के लिए खाद्य और आवास मार्ग का काम करे।

यह पहल नीतिगत सोच में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है, जहां बुनियादी ढांचा केवल उपयोगिता नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन का हिस्सा भी माना जा रहा है। पहले जहां सड़क किनारे पौधरोपण का उद्देश्य मुख्य रूप से सजावटी या धूल नियंत्रण तक सीमित रहता था, वहीं अब ध्यान स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल प्रजातियों के चयन पर दिया जा रहा है। राजमार्गों के किनारे सतत् हरित पट्टियां कई पर्यावरणीय लाभ देती हैं। पेड़-पौधे तापमान को नियंत्रित करते हैं, धूल और प्रदूषण को कम करते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर हरित पट्टियां सड़क किनारे सूक्ष्म जलवायु को संतुलित करती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में तापमान का प्रभाव कम होता है।

दूसरी ओर, मधुमक्खी गलियारे का प्रभाव वास्तव में एक बहुस्तरीय परिवर्तन की संभावना को जन्म देता है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग कृषि परिदृश्य से होकर गुजरते हैं। जब इन सड़कों के किनारे परागणकर्ता के अनुकूल पौधों और वृक्षों का रोपण किया जाता है, तो यह केवल हरियाली बढ़ाने का कार्य नहीं करता, बल्कि एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करता है, जो आसपास के खेतों से सीधे जुड़ जाता है।

सबसे पहला प्रभाव कृषि उत्पादकता पर दिखाई देता है। मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता पौधों के प्रजनन की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाते हैं, जिससे फसलों में दानों का भराव, फल का आकार, बीज की गुणवत्ता और कुल उपज बढ़ती है। सरसों, सूरजमुखी, सेब, आम, टमाटर, कद्दू वर्गीय सब्जियां और कई तिलहन फसलें ऐसी हैं, जिनकी उत्पादकता परागण की उपलब्धता से सीधे प्रभावित होती है। जब परागणकर्ता लगातार उपलब्ध रहते हैं, तो किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों को बढ़ाने की आवश्यकता कम पड़ती है और प्राकृतिक उत्पादकता चक्र मजबूत होता है।

> मधुमक्खी गलियारे की सफलता केवल पौधे लगाने से तय नहीं होगी। इसकी असली चुनौती दीर्घकालिक रखरखाव में है। सड़क किनारे पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई, चराई से संरक्षण और कीटनाशकों के सीमित उपयोग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। अगर इन पहलुओं की अनदेखी हुई, तो पौधरोपण केवल कागजी उपलब्धि बनकर रह सकता है। यह पहल दरअसल एक महत्त्वपूर्ण विचार की ओर संकेत करती है। ऐसा विकास प्रारूप, जिसमें प्रकृति और बुनियादी ढांचा, आपसी में विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी हों।

दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू गुणवत्ता का है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि पर्याप्त परागण होने पर फलों का आकार अधिक समान होता है, उनका पोषण मूल्य बेहतर होता है और बाजार में उनकी कीमत भी अधिक मिलती है। इस तरह मधुमक्खी गलियारा अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकता है। तीसरा आयाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। अगर इस पहल को योजनाबद्ध तरीके से मधुमक्खी-पालन से जोड़ा जाए, तो यह दोहरी आय का ढांचा बन सकता है। राजमार्ग के किनारे विकसित पुष्प संसाधन मधुमक्खियों के लिए निरंतर भोजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे शहद उत्पादन बढ़ सकता है। स्थानीय किसान या स्वयं सहायता समूह शहद, मधुमोम और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा, यह पहल पारिस्थितिकी की स्थिरता को भी मजबूत करती है। परागणकर्ताओं की संख्या बढ़ने से जैव विविधता में वृद्धि होती है, क्योंकि इनके साथ-साथ पक्षी, तितलियां और अन्य कीट भी आकर्षित होते हैं। इससे खेतों और आसपास के परिदृश्य में प्राकृतिक संतुलन बेहतर होता है और कीट प्रबंधन में भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है।

व्यापक सामाजिक-आर्थिक महत्त्व के लिहाज से देखें तो मधुमक्खी गलियारा पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ कृषि, ग्रामीण रोजगार और जैव विविधता- इन चारों को जोड़ने वाला एक समेकित ढांचा बन सकता है, जो भविष्य की हरित अवसंरचना की दिशा भी तय करता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं को निरंतर भोजन और आश्रय उपलब्ध कराना है। इसके लिए राजमार्गों के किनारे ऐसी वनस्पति लगाई जाएगी जिसमें साल भर फूल आते रहें। इस योजना में नीम, पलाश, जामुन और अन्य स्थानीय फूलदार पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें फूलदार पौधों को लगभग पांच सौ मीटर से एक किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाएगा, ताकि मधुमक्खियों की उड़ान दूरी के भीतर लगातार भोजन स्रोत उपलब्ध रहे।

हालांकि, मधुमक्खी गलियारे की सफलता केवल पौधे लगाने से तय नहीं होगी। इसकी असली चुनौती दीर्घकालिक रखरखाव में है। सड़क किनारे पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई, चराई से संरक्षण और कीटनाशकों के सीमित उपयोग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्त्वपूर्ण है। अगर ग्रामीणों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय प्रशासन को इस पहल से जोड़ा जाए, तो इसकी स्थिरता और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। यह पहल दरअसल एक महत्त्वपूर्ण विचार की ओर संकेत करती है। ऐसा विकास प्रारूप, जिसमें प्रकृति और बुनियादी ढांचा, आपस में विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी हों। तेज रफ्तार वाहनों के बीच अगर सड़क किनारे फूलों पर मंडराती मधुमक्खियां दिखाई दें, तो वह दृश्य केवल सुंदर नहीं होगा। वह इस बात का संकेत होगा कि विकास की दिशा में हम एक अधिक संतुलित और टिकाऊ रास्ता चुन रहे हैं।

आने वाले वर्षों में यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि मधुमक्खी गलियारे की पहल कितनी व्यापक रूप से लागू होती है और इसके परिणाम कितने सकारात्मक और प्रभावी होते हैं। अगर इसे वैज्ञानिक योजना, स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी के साथ लागू किया जाए, तो यह भारत में हरित बुनियादी ढांचे का एक उदाहरण बन सकता है। इस पहल का असली मूल्य पर्यावरणीय आंकड़ों से आगे उस दृष्टि में है, जिसमें सड़कें केवल शहरों और बाजारों को नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्रों को भी जोड़ती हैं। राजमार्गों की गूंज के बीच मधुमक्खियों की भनभनाहट इस ओर इंगित करती है कि प्रगति का सबसे टिकाऊ रास्ता वही है, जिसमें जीवन के सभी रूपों के लिए जगह हो।

बहस बनाम विवाद

पूनम पांडे

मनुष्य हमेशा एक ही भाव में मुश्किल से ही दिखता है। वह कभी खुश कभी नाखुश है। कभी मुखर तो कभी मौन। कभी चुस्त-दुरुस्त तो कभी आलसी और सुस्त। कभी स्वस्थ तो कभी अस्वस्थ। कभी कंजूस तो कभी खर्चीला। यह इंद्रधनुषी रंग हर जगह देखने को मिल जाते हैं। इसे हर कोई स्वीकार भी कर लेता है। एक कहावत भी है कि इंसान अपने वातावरण के जैसा ही बन जाता है। रोजाना महसूस हो रही जीवनशैली की उजली-धुंधली चित्रकारी आदमी के मन में बैठकर उसका व्यवहार बनने लगती है।

इसीलिए एक आदत आजकल के लोगों में बहुतायत से देखने को मिल रही है। वह है बात-बात पर बहस और नाहक वाद-विवाद। हर बात पर तकरार का संस्कार सब पर हावी होता जा रहा है। अगर आभासी दुनिया की बात की जाए, तो वहां भी हालात इसी तरह के हैं। एक ने सोशल मीडिया पर अपनी वाल कुछ लिखा, तो दूसरे को अखर जाता है। तीसरा उस पर खुलेआम अपशब्द लिख देता है। चौथा तो पांच, छह, सात अपनी ही मानसिकता वालों को आवाज देकर बुलाता है। उसके बाद गरमागरम बहस और तानेबाजी चल पड़ती है। जमीन के जगत में आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हों, तो चार लोग बिना बात के ऊल-जलूल बोलने लगते हैं। आभासी दुनिया का ज्ञान उलीचने लगते हैं। चारों तरफ से बहस ही बहस हो रही होती है। सड़क पर, बस, मेले, जुलूस में या किसी सामाजिक समारोह में, हर जगह यह आम बात होती जा रही है। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर में मौनी साधक बनकर चुप बैठे रहते हैं, लेकिन घर की चारदिवारी से बाहर निकलकर वे लोग भी अपने दिमाग का तरकश लेकर तैयार रहते हैं और फिर बातों के तीर चलाने से जरा भी बाज नहीं आते हैं। यानी हर जगह हर किसी को बहस करना तथा उलझना मजेदार लगने लगा है।

दरअसल, टीवी बहसों ने भी लोगों को झगड़ालू-सा बना दिया है। आजकल चैनलों की बाढ़ इस कदर आ गई है कि कोई व्यक्ति इनकी भाषा और बोली से अछूता नहीं रहा है। परिणाम यह है कि अब हर किसी को औरों से तीखी बात करने में अपने सामने वाले से नोकझोंक करने में ही बहुत रस आने लगा है। न जाने यह कौन-सा तनाव है, उलझन है, बेचैनी है कि लोग बात-बात पर बहस करने लगते हैं। एक दिन तो एक चौराहे पर एक कूरियर वाला संबंधित पते पर गया। उसने पार्सल देते हुए बस इतना ही कहा कि 'ओटीपी' दीजिए। इस पर पार्सल लेने वाले ने कहा कि हां-हां, मुझे भी मालूम है... ज्यादा मत बोलो। और बस इसी बात पर देखते ही देखते दोनों की गरमागरम बहस शुरू हो गई और आखिर ओटीपी कूरियर वाले को नहीं मिला। कूरियर वाला पार्सल वापस लेकर चला गया। इसी तरह, एक कस्बे की बारात में एक नकचढ़े बाराती की पसंद का गीत न बजाने पर इतनी बहस हुई कि गाली-गलौज से नाराज और रूठे हुए बैंडवाले वापस चलते बने। मुहूर्त चला जा रहा था, दूसरे बैंडवाले खाली नहीं थे, तो बाकी बारात ऐसे ही खामोश होकर गई। जरा-सी बात ने यह हालत कर दी। फिर बहस इस बात पर खड़ी हो गई कि यह भी क्या कोई बहस वाली बात थी!

देखा जाए तो बहस करना इतना बुरा नहीं है। कितनी ही बार चिकित्सक से समुचित बात करने के बाद कितने ही लोग अनावश्यक सर्जरी से खुद को बचा पाए हैं। वे चिकित्सीय रिकार्ड के साथ यह सार्वजनिक रूप से बताते भी हैं कि उस संवेदनशील पल में तकरार और झगड़ा न किया होता, तो आठ-दस लाख का आपरेशन हो जाता, जिसकी वास्तव में इतनी भी जरूरत नहीं थी। घर-परिवार में कोई प्रतिभावान बालक या बालिका अगर बहस न करे, तो अपनी इच्छानुसार करिअर नहीं चुन सकता।

रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं कि मनमानी करने वाले दुकानदार से बराबर बहस करनी होती है, तब जाकर उचित मूल्य पर मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। मगर साथ ही यह भी सच है कि बेकार और बेमतलब की बहस या तकरार का कोई हासिल नहीं होता। बहस करने वाला अपनी ऊर्जा भी खर्च करता है और बेवकूफ भी साबित होता है। खासतौर पर अगर बहस खुद को बाकी लोगों से बढ़कर दिखाने की भूख न हो। बहस अगर सफाई अभियान के लिए, नशामुक्ति के लिए हो, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए हो, अपने अवगुण खत्म करने के लिए हों, तब बहस का कोई मतलब समझ में भी आता है। हम बेमानी बहसों में उलझने के बजाय सार्थक मुद्दों और सही समय का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें बहस करने के बाद कुछ हासिल हो। मगर बेवजह की बहस में उलझना हमेशा ही नुकसानदेह ही साबित होता है। महान दार्शनिक सोफोक्लीज अपने अनुयायियों को वाद-विवाद और बहस से बचने का पाठ हमेशा पढ़ाया करते थे। सोफोक्लीज के मुताबिक, बहस का असली कारण अपनी कमजोरी छिपाना और दूसरे को अपराधी या दोषी ठहराना होता है। महात्मा गांधी सही मामले के लिए उपयुक्त बहस के पक्षधर थे। बहस को शुरू करना अंगारों पर चलने के बराबर है, इसलिए जुबान खोलते समय सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो मुल्ला नसरुद्दीन, अकबर के प्रिय बीरबल और तेनालीराम लचीली बहस करने में माहिर थे। यानी बहस ऐसी हो कि बात-विचार भी हो जाए और बिना विवाद के मसले का हल भी निकल आए। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।

दुनिया मेरे आगे

> बहस अगर सफाई अभियान के लिए, नशामुक्ति के लिए हो, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए हो, अपने अवगुण खत्म करने के लिए हों, तब बहस का कोई मतलब समझ में भी आता है। हम बेमानी बहसों में उलझने के बजाय सार्थक मुद्दों और सही समय का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें बहस करने के बाद कुछ हासिल हो।

बढ़ती चुनौतियां

ईरान-इजराइल और रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर हम प्रायः अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करते हैं और अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन इन संघर्षों का सीधा प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ रहा है। रसोई गैस की कमी और ईंधन की आपूर्ति में बाधा इसका उदाहरण है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से भारत तेल और गैस का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यदि यह समुद्री मार्ग बंद होता है या वहां तनाव बढ़ता है, तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होना स्वाभाविक है। यों इसका असर आम लोगों के जीवन पर अभी से दिखने लगा है। कई महानगरों में रेस्तरां और छोटे भोजनालय गैस की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। गैस और ईंधन की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती है, जिससे आम नागरिक और छोटे व्यवसाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यह स्थिति भारत की आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर भी असर डाल सकती है। ऐसे समय में अपनी ऊर्जा नीति को और मजबूत करना चाहिए। सरकार को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक निवेश करना होगा, ताकि संकट आने पर देश की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित न हो।

– मो नैयर आजम, सीतामढ़ी, बिहार

संयम का समय

'चुनौतियों का दायरा' (संपादकीय, 12 मार्च) पढ़ा। इसमें ईरान-इजराइल संघर्ष के वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। युद्ध के कारण तेल और गैस आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, जिससे कई देशों में ऊर्जा संकट और महंगाई बढ़ने की आशंका है। भारत में भी तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने से रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर दबाव बन सकता है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, परिवहन और जमाखोरी पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि तेल-गैस की आपूर्ति, परिवहन और बाजार व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है। इसलिए सरकार को नए ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रखने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

– ऐश यादव, जम्मू

विकल्प की ऊर्जा

'सिमटते संसाधनों के बीच अक्षय ऊर्जा' (लेख, 11 मार्च) पढ़ा। आज ऊर्जा के बिना इंसान की जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस समय हर काम में ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ देर के लिए बिजली न आने से लोगों के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगती है। इसके लिए जरूरी है कि इसकी निरंतरता बनाए रखें। हालांकि हम इस खतरे को समझ चुके हैं और ऊर्जा के नए स्रोतों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और यही वजह है कि सौर ऊर्जा के महत्त्व को हमने समझा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है। हमें ऊर्जा का उपयोग अब सोच समझ कर करना है। आवश्यकता होने पर ही बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे बल्बों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बिजली की खपत कम से कम हो। मकानों में उजाले की पर्याप्त व्यवस्था हो। तेजी से विकास करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा को भी बढ़ावा देना होगा।

– साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

दोधारी तलवार

सोशल मीडिया दोधारी तलवार है, जो संपर्क और सूचना साझा करने में मदद तो करता है, लेकिन इसकी लत से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ गलत सूचनाओं का जोखिम बढ़ गया है। यह जहां तत्काल वैश्विक संचार, शैक्षिक विकास और रचनात्मक अभिव्यक्ति को सक्षम बनाता है, वहीं अनियंत्रित उपयोग के कारण यह दुनिया भर की सरकारों को भी खटकने लगा है। मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, विश्व भर की सरकारें बच्चों-किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठा रही है या इस पर विचार कर रही हैं। हमारे यहां की कुछ राज्य सरकारें भी पहल कर रही हैं। कर्नाटक ने तो बड़ी पहल की है। गोवा और आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्य भी प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं। अब बिना कोई देरी किए देश के बाकी राज्यों को भी आगे आना चाहिए।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

संसद में एलपीजी पर विपक्ष का हंगामा

सांसदों ने केंद्र सरकार को घेरा, दो बार स्थगन के बाद सदन स्थगित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 मार्च

लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के सदस्यों ने देश में एलपीजी गैस कमी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। विपक्ष के सांसदों ने सबसे पहले यह मामला संसद परिसर में प्रदर्शन करके उठाया और इसके बाद सदन के भीतर भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आसन पर थे। अध्यक्ष ने विपक्ष को सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग करने के लिए कहा, लेकिन जब हंगामा जारी रहा तो मात्र तीन मिनट में ही सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन के बाहर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सांसदों ने इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की।

हंगामे के बीच कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने की बात कहते सुना गया। लेकिन अध्यक्ष ने पहले सदन में व्यवस्था बनाने और प्रश्नकाल शुरू करने के लिए कहा। हंगामा जारी रहने के बाद सदन को फिर दो बजे तक स्थगित किया गया। ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्त्वपूर्ण समय होता है और आज भी विपक्ष के आठ सांसदों के प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में जहां देश के मुद्दे, क्षेत्रों की समस्याएं उठाई जाती हैं, वहीं सरकार की जवाबदेही भी तय होती है।

> *ओम* बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्त्वपूर्ण समय होता है और आज भी विपक्ष के आठ सांसदों के प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप कहते हैं कि बोलने का अवसर नहीं मिलता। जब आपको बात रखने का समय और अवसर दिया जाता है, तब आप बोलना नहीं चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद यदि सदस्य कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। बिरला ने कहा कि एक और आग्रह कर रहा हूं कि संसद के अंदर हो या बाहर या फिर संसद परिसर में उसकी पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी सभी की है।

विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों से शुरू हुई एलपीजी की कमी की अफवाह : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 मार्च।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों से रसोई गैस (एलपीजी) की कमी की अफवाह फैलने की शुरुआत का आरोप लगाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि सबसे पहले कर्नाटक (जहां कांग्रेस की सरकार है) और फिर पश्चिम बंगाल (जहां तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार है) से एलपीजी की कमी की खबरें सामने आईं।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर भ्रम फैलाने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में पार्टी के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि संयोग से, कर्नाटक पहला ऐसा राज्य था, जहां से एलपीजी की कमी की खबरें सामने आने लगी थीं। इसके तुरंत बाद, पश्चिम बंगाल से भी ऐसी ही खबरें आईं।

> *केंद्रीय* कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर भ्रम फैलाने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया।

अब मीडिया रपट से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता गैस सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहे हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, विपक्षी नेता जिम्मेदारी दिखाने के बजाय आम नागरिकों के लिए मुश्किलें खड़ी करने पर अधिक ध्यान देते नजर आ रहे हैं।

विपक्ष ने बिरला से आठ सांसदों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 मार्च।

सूत्रों के मुताबिक रिजीजू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष के सामने उठाएंगे।

विपक्षी दलों ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, द्रमुक सांसद कनिमोई और तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी राय ने गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू से मुलाकात की और आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की।

सूत्रों के मुताबिक रिजीजू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष के सामने उठाएंगे। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक के दौरान कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने बिरला और रिजीजू के सामने फिर से यह मुद्दा उठाया। सूत्रों ने यह भी बताया, 'रिजीजू ने विपक्ष से कहा है कि वह परामर्श के बाद इस मुद्दे पर उनसे संपर्क करेंगे। सूत्रों ने कहा कि निलंबित सांसदों का विषय विपक्ष और सरकार के बीच टकराव का एक मुद्दा है। विपक्ष पश्चिम एशिया संघर्ष और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की मांग कर रहा है। पहले चरण के दौरान तीन फरवरी को सदन में आसन की ओर कागज फेंकने के कारण सदन की अवमानना के मामले में विपक्ष के आठ सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।

निलंबित सांसदों में कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एस. वेंकटेशन शामिल हैं। निलंबन के बाद से ये सांसद संसद की कार्यवाही वाले दिन संसद के मकर द्वार पर धरना देते आ रहे हैं।

मुलाकात

राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के संसद सदस्यों और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों से मुलाकात करतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।

तिरुमला लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

भ्रामक सूचना देने संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं

नई दिल्ली, 13 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला लड्डू विवाद के बारे में पोस्टर या सार्वजनिक बयानों के माध्यम से कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायालय ने चार अक्तूबर 2024 को पांच-सदस्यीय एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया था, जिससे तिरुपति में लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच की जा सके और 'करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत किया जा सके। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि अदालत को 'राजनीतिक युद्धक्षेत्र' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस सिलसिले में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप विशेषज्ञ क्यों बन गए हैं। जाइए और अधिकारियों को बता दीजिए।

> *पीठ* ने यह भी कहा कि यह याचिका कुछ और नहीं, बल्कि उन संदिग्धों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में बचाव पक्ष की दलील को मजबूत करने का एक प्रयास है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जांच एजंसी को जो भी पता चलता है, उसे संबंधित अदालत के सामने रखा जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि यह याचिका कुछ और नहीं, बल्कि उन संदिग्धों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में बचाव पक्ष की दलील को मजबूत करने का एक प्रयास है।

अदालत ने कहा कि हम इस याचिका को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता या कोई भी अन्य इच्छुक व्यक्ति जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के उद्देश्य से जांच एजंसी को कोई भी सामग्री प्रस्तुत कर सकता है। याचिका में आंध्र प्रदेश सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि होर्डिंग, पोस्टर या सार्वजनिक बयान के माध्यम से गलत जानकारी फैलाने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।

आपदा से निपटने के लिए राज्यों को मिलेगी 1912 करोड़ की मदद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 मार्च।

बाढ़- बादल फटने, चक्रवात और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को 1912 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक में लिया गया।

समिति ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 1,912.99 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। मंत्रालय के मुताबिक यह धनराशि केंद्रीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से प्रदान की गई है, जो वर्ष की प्रारंभिक शेष राशि में उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के 50 फीसद के समायोजन के अधीन है। इस राशि में आंध्र प्रदेश के लिए 341.48 करोड़, छत्तीसगढ़ के लिए 15.70 करोड़, गुजरात के लिए 778.67 करोड़, हिमाचल प्रदेश के लिए 288.39 करोड़, नगालैंड के लिए 158.41 करोड़ तथा जम्मू-कश्मीर के लिए 330.34 करोड़ की मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार यह अतिरिक्त सहायता उन धनराशि से अतिरिक्त है, जो केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ के तहत राज्यों को पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत 20,735.20 करोड़ रुपए तथा 21 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 3,628.18 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमफ) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।

'ट्रांसजेंडर' की परिभाषा के लिए विधेयक पेश

विधेयक में कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जरूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 मार्च।

'ट्रांसजेंडर' शब्द की उपयुक्त परिभाषा देने और इस वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामले में सजा के प्रावधान वाला एक विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। 'ट्रांसजेंडर' व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया।

विधेयक में कहा गया है कि 'ट्रांसजेंडर' व्यक्तियों की सही और सुनिश्चित पहचान करना और उनकी सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त परिभाषा देना जरूरी है ताकि उन्हें मौजूदा कानून का फायदा मिल सके। इसमें कहा गया है कि 2019 के मौजूदा कानून के तहत दी जाने वाली सुरक्षा और फायदे बहुत व्यापक हैं और इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसी पहचान किसी व्यक्ति की किसी खासियत या निजी पसंद या खुद की बताई गई पहचान के आधार पर नहीं दी जा सकती। संशोधन विधेयक में एक नया उपखंड जोड़ा गया है, जिसके अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होगा जिसकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान 'किन्नर, हिजड़ा अथवा जोगता के रूप में हो, या जन्म से ही पुरुष या महिला के शारीरिक विकास की तुलना में एक या अधिक लैंगिक विशेषताओं में जन्मजात भिन्नता वाला हो।

राज्यसभा में पेश हुए 18 निजी विधेयक

राज्यसभा में शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के प्रावधानों वाले एक विधेयक सहित विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा कुल 18 विधेयक पेश किए गए। उच्च सदन में भाजपा के सुजीत कुमार ने सिल्वर अर्थव्यवस्था (विकास और सशक्तीकरण) विधेयक पेश किया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अर्थव्यवस्था में योगदान देने तमाम प्रावधान किए गए हैं। कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने दो निजी विधेयक पेश किए, जिनमें जलवायु अनुकूल कृषि एवं किसान संरक्षण विधेयक तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता विधेयक शामिल हैं। इसी पार्टी की जेबी माथेर हीशम ने भारतीय न्याय संहिता संशोधन विधेयक पेश किया।

राज्यसभा में उठा निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के गठजोड़ का मामला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 मार्च।

निजी अस्पतालों में महंगे इलाज और निजी एवं चिकित्सा बीमा कंपनियों द्वारा मरीजों के दावे मनमाने तरीके से खारिज किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मांग की कि इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है।

> *आम* आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मांग की कि इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है।

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए स्वाति ने कहा कि आज निजी अस्पतालों और निजी बीमा कंपनियों के बीच गठजोड़ बन गया है जो आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मरीज की अस्पताल में मौत हो जाती है। निजी बीमा कंपनी 'क्लेम' देने से मना कर देती है। पूरा भुगतान न होने पर अस्पताल शव देने से मना कर देता है। गरीब परिवारों के लिए ऐसे में कर्ज लेने या अपना घर, गहने बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता।

स्वाति ने कहा कि निजी बीमा कंपनी जानीमानी हस्तियों से प्रचार करवाती हैं और विज्ञापनों में कहा जाता है कि मिनटों में 'क्लेम' मिलेगा। इस झांसे के बाद व्यक्ति निजी अस्पताल और निजी बीमा कंपनी के बीच टेनिस गेंद बन जाता है। अस्पताल में भर्ती होते ही टीपीए में पता चलता है कि आपकी बीमा कंपनी काली सूची में है।

पेज 1 का बाकी

तेहरान के फिरदौसी चौक पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, पास में हुआ भीषण विस्फोट

दुर्घटनाग्रस्त होने से उसके चालक दल के सभी छह सदस्यों की मौत हो गई है। तेहरान के चौक पर हुए विस्फोट का कारण तत्काल ज्ञात नहीं हो सका है। विस्फोट से ठीक पहले इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वह इस क्षेत्र में हमला कर सकता है। फिलीस्तीन के लोगों के समर्थन में वार्षिक कुद्स दिवस समारोह के लिए रैलियां शुरू होने से ठीक पहले तेहरान के आसपास भीषण हवाई हमले शुरू हो गए।

हमलों के बावजूद, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। सऊदी अरब ने शुक्रवार को कहा कि उसने तड़के सुबह अलग-अलग समय भेजे गए लगभग 50 ड्रोन मार गिराए। ओमान न्यूज एजंसी के अनुसार ओमान के सोहार क्षेत्र के एक औद्योगिक इलाके में दो ड्रोन गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।

बहरीन में हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज सुनी गई और दुबई में एक औद्योगिक क्षेत्र से काला धुआं उठता देखा गया। अधिकारियों के अनुसार, किसी मिसाइल या हमले को रोकने की कार्रवाई (इंटरसेप्शन) के बाद गिरे मलबे से आग लग गई थी।

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों के अनुसार, 'सफल इंटरसेप्शन' के बाद गिरे मलबे की वजह से इमारत को नुकसान हुआ है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, देश में अब तक 1,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल ने 12 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं, अमेरिका के कम से कम सात सैनिकों की मौत हो चुकी है और आठ सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

अमेरिकी मध्य कमांड ने कहा कि केसी-135 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने में न तो दुश्मन की गोलीबारी और न ही अपनी तरफ से हुई गोलीबारी का कोई हाथ था। उन्होंने बताया कि यह ईंधन विमान ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में शामिल था। इस घटना में शामिल दो विमानों में से एक था और दूसरा विमान सुरक्षित रूप से उतर गया।

एलपीजी को लेकर जगह-जगह हड़कंप, सरकार ने कहा पर्याप्त

कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी देखने को मिला। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि पांच मार्च से अब तक घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30 फीसद की वृद्धि की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि घबराहट में सिलेंडर की बुकिंग की कोई जरूरत नहीं है, और किसी भी एलपीजी डीलर के पास स्टाक खत्म नहीं हुआ है। शर्मा ने बताया कि ईरान युद्ध से पहले औसतन 55.7 लाख बुकिंग के मुकाबले इस समय एलपीजी बुकिंग बढ़कर 75.7 लाख हो गई है, जो स्पष्ट रूप से घबराहट में की जा रही बुकिंग को दर्शाता है।

सरकार ने पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) नेटवर्क के करीब रहने वाले लगभग 60 लाख परिवारों से इस सुविधा को अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी दी है कि अगर वे पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण पैदा हुए संकट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस समस्या को लेकर शुक्रवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने की मांग करते हुए नारे लगाए। तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने सुबह करीब 10:30 बजे संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और एलपीजी संकट व सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए नारे लगा रहे थे। उनके साथ कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों के सांसद भी शामिल हुए।

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश में एलपीजी का बहुत बड़ा संकट है। परिवारों के सदस्य, बूढ़े लोग, जवान माता-पिता अपने सिलेंडर बुक करने के लिए लाइन में खड़े हैं और सरकार यह जानकारी दे रही है कि आपको ढाई दिन में सिलेंडर मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किए। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेताओं ने सड़क किनारे पारंपरिक चूल्हे पर रोटियां सेंक कर एलपीजी की किल्लत और महंगाई को लेकर विरोध जताया। पार्टी नेताओं ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और उन्हें खरीदने में परिवारों और छोटे व्यवसायों के सामने आने वाली कठिनाइयों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने एलपीजी सिलेंडर संकट के विरोध में प्रदर्शन किया।

ओड़ीशा में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी के कारण कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए तथा सड़कों पर अवरोध की स्थिति रही। यहां उपभोक्ताओं ने भरे हुए एलपीजी सिलेंडर को प्राप्त करने में देरी से संबंधित शिकायत की थी। राजस्थान में विपक्षी दल कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडरों की कमी को लेकर अजमेर, जैसलमेर, नागौर, अलवर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। पार्टी ने सरकार पर सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता परेशान हो रही है।

पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर खाना बनाकर इस संकट पर प्रतीकात्मक विरोध जताया। सरकार घरेलू रसोई के साथ ही अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है और उन्हें निर्बाध एलपीजी दी जा रही है। दूसरी तरफ होटलों और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की आपूर्ति में कटौती की गई है। देश में 33.37 करोड़ एलपीजी उपयोगकर्ता हैं और 1.5 करोड़ लोगों को उनके रसोई घर में पाइप के जरिए ईंधन (पीएनजी) मिलता है। उन्होंने कहा कि पीएनजी बुनियादी ढांचे के पास रहने वाले परिवारों को पाइप वाली रसोई गैस अपनाने से लाभ हो सकता है। इससे उन्हें लगातार आपूर्ति मिलेगी।सिलेंडर बुकिंग में करीब डेढ़ गुना बढ़ोतरी संयुक्त सचिव ने डेटा पेश करते हुए कहा कि देश में रोजाना की 50 से 55 लाख सिलेंडर की बुकिंग होती है जो वर्तमान में बढ़कर 75 लाख तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि 'काल सेंटर' और कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है ताकि लोगों की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान हो सके।

उन्होंने कहा, कालाबाजारी को रोकने में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक की अहम भूमिका है। कई राज्यों ने अपनी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के बाद उचित निर्देश भी दिए हैं और नियंत्रण कक्ष की शुरुआत की है। राज्यों में कार्रवाई, दिए गए निर्देश -उत्तर प्रदेश में झांसी में ट्रक लोड की चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की।

इंडिगो की उड़ान आज से हुई महंगी

कदम उठाया गया है। एअरलाइन ने कहा, अगर ईंधन की बढ़ी कीमतों का पूरा असर टिकट किराए पर डाला जाता तो किराए में काफी इजाफा करना होगा। यात्रियों पर कम बोझ पड़े इसलिए अपेक्षाकृत कम राशि का ईंधन शुल्क लगाया गया है।

इससे पहले 10 मार्च को एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने भी टिकटों पर ईंधन अधिभार लगाने की घोषणा की थी। दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख महानगरों में एटीएफ पर उच्च उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के कारण यह दबाव और बढ़ जाता है और इसका असर परिचालन लागत पर भी पड़ता है।

एअर इंडिया ने नए ईंधन अधिभार को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है, जिसमें सभी उड़ानों पर यात्रा शामिल है। पहले चरण में 12 मार्च से एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों की बुकिंग, दूसरे चरण में 18 मार्च से यूरोप, आस्ट्रेलिया जबकि तीसरे चरण में हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया पर लागू होगा।

ईडी ने पांच शहरों में छापेमारी के बाद 90 खातों पर रोक लगाई

साझेदार स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला हैं। निदेशालय ने कहा कि यह घोटाला पिछले वर्ष बैंक के पूर्व कर्मचारियों की सहायता से अंजाम दिया गया, जिनमें ऋषव ऋषि शामिल हैं। एजंसी के अनुसार अपराध से प्राप्त धन ऋषि और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा के खातों में खर्च या स्थानांतरित कर दिया गया।

ईडी ने कहा कि छापेमारी के दौरान 90 से अधिक बैंक खातों पर रोक लगा दी गई और डिजिटल तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में अभियोजन के लिए आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। इस छापेमारी से पहले एजंसी ने हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो की प्राथमिकी को ध्यान में रखते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। ब्यूरो के अनुसार इस जांच के तहत अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें छह बैंक कर्मचारी, चार निजी व्यक्ति और एक सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

विपक्ष ने ज्ञानेश के खिलाफ दोनों सदनों में नोटिस दिए

(सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि अब राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस पर निर्णय लेना है। नियमों के मुताबिक, नोटिस देने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।

विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। विपक्ष मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद को लेकर पिछले कुछ महीनों से उन पर निशाना साधता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआइआर का उद्देश्य भाजपा की मदद करना है। सीईसी को पद से हटाने का नोटिस संसद के किसी भी सदन में दिया जा सकता है और इसे अवश्य ही विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए।

प्रेरणा

वी जीते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वी जीतेंगे।

-स्वेट मार्डेन

संपादकीय

खाना पकाने का संकट कोई मामूली मुद्दा नहीं है

अगर शहरों, गांवों और कस्बों में करोड़ों लोग काम-धंधा छोड़कर रात से ही गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाने के बावजूद खाली हाथ लौटें या दस गुना महंगी दर पर ब्लैक में खरीदें तो इसे बेवजह पैनिक पैदा करना नहीं कहेंगे। इस संकट की प्रकृति समझनी होगी। यह पेट्रोल/डीजल/सीमेंट/चीनी का संकट नहीं है। इसके अभाव में गरीब खासकर प्रवासी मजदूर खाना नहीं पका सकेगा। भले ही सरकार ने एलपीजी संकट के चलते प्रदूषण पैदा करने वाले कोयला/उपले/जलावन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी हो, असंगठित क्षेत्र के मजदूर या कस्बाई आबादी के पास तो ऐसे विकल्प भी उपलब्ध नहीं हैं। पका भोजन जीवित रहने के लिए अपरिहार्य है। पर्यावरण चेतना के कारण आधुनिक युग में भोजन पकाने वाला ईंधन भी बदल चुका है लिहाजा उसकी उपलब्धता भी अनिवार्य है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार गत 1 जनवरी को देश में 33.21 करोड़ एलपीजी और मात्र 1.60 करोड़ पीएनजी (पाइप्ड गैस) कनेक्शंस थे। यानी शहरों के कुल 8.5-9 करोड़ परिवारों में हर पांच घरों में केवल एक के पास पाइप्ड गैस है, जबकि अन्य चार के भोजन पकाने का एक मात्र सहारा एलपीजी सिलेंडर है। ऐसे में सुदूर गांवों से लेकर कस्बों और 80 फीसदी शहरी आबादी के लिए अगले दिन खाना कैसे पकेगा, यह सवाल आज सबसे बड़ी चिंता बन गया है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

हर व्यक्ति या परिस्थिति में ईश्वर को अवश्य ढूंढिए

जिस दुनिया को हम जानते हैं, उससे भी ज्यादा अनजानी दुनिया है। मैं इन दिनों चार देशों- फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा पर हूं। यहां मेरे प्रवचन चल रहे हैं। जितने लोगों से मिलता हूं, जितने दृश्य देखता हूं, लगता है कि हरेक के भीतर एक नई दुनिया है। जो कुछ इस उम्र में हमने जाना है, देखा है, उससे कई गुना अनदेखा रह गया। इसलिए जीवन में आने वाला हर दृश्य और हर व्यक्ति परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकारा जाए। ईश्वर हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए नया-नया दिखाता है। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है- निज प्रभुमय देखहिं जगत् केहि सन करहिं बिरोध। इस सारे जगत को मैंने अपने ईश्वर जैसा देखा है तो फिर किससे विरोध करें? अगर किसी दृश्य को देखकर अच्छा लग रहा है तो मानकर चलिएगा उसमें ईश्वर बसा है। दुःख आए तो अपने दोष ढूंढना, सुख आए तो ईश्वर की कृपा मानना। नए दृश्य और नए व्यक्ति मिलें तो समझना कहीं न कहीं भगवान ही मिला है, नए का आनंद और बढ़ जाएगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नजरिया • सुपरस्टार संस्कृति के बजाय टीम संस्कृति

अब यह सोच जीत रही है कि खिलाड़ी से बड़ी टीम होती है

क्रिकेट

सुधीर चौधरी

वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक

sudhirchaudhary@esprit.co.in

टी-20 विश्व कप में भारत की जीत को अगर हम सिर्फ स्कोरबोर्ड की नजर से देखें, तो इसके असली मायनों को चूक जाएंगे। यह जीत भारतीय क्रिकेट के भीतर आ रहे एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ 11 खिलाड़ियों की टीम की नहीं, बल्कि उस नए सिस्टम की जीत है, जो पिछले कुछ वर्षों में तैयार हुआ है।

लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द घूमता रहा। कभी यह टीम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानी गई, कभी सौरव गांगुली के नेतृत्व ने इसे पहचान दी, फिर महेंद्र सिंह धोनी और उसके बाद रोहित शर्मा जैसे कप्तानों के दौर में टीम की पहचान अकसर एक व्यक्ति से जुड़ जाती थी।

1983 का विश्व कप आज भी कपिल की टीम के नाम से याद किया जाता है। 2007 और 2011 की टीमें धोनी की टीमें कहलाईं। पिछले कुछ वर्षों में रोहित की टीम शब्द भी बार-बार सुनाई देता रहा। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। इस टीम में कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है, जिसकी छवि बाकी खिलाड़ियों से कई गुना बड़ी हो। इस टीम में युवा खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरी टीम पर हावी हो। ये खिलाड़ी शायद विज्ञापनों में कम दिखते हों, लेकिन मैदान पर सही समय पर कमाल जरूर दिखाते हैं। यही इस जीत की सबसे बड़ी खासियत है।

भारतीय क्रिकेट अब सुपरस्टार संस्कृति से आगे बढ़कर टीम संस्कृति की तरफ जा रहा है, जहां जीत का श्रेय किसी एक खिलाड़ी को नहीं, पूरे सिस्टम को मिलता है। इस बदलाव का एक और दिलचस्प पहलू है। पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम का सबसे बड़ा चेहरा कोई खिलाड़ी या कप्तान नहीं, बल्कि टीम का कोच बन गया है। और वो पोस्टर बॉय हैं- गौतम गंभीर।

फुटबॉल की दुनिया में यह मॉडल काफी पुराना है। वहां बड़े क्लबों की पहचान उनके मैनेजर से होती है। भारतीय क्रिकेट में यह सोच अब दिखाई देने लगी है। गौतम गंभीर ने जब टीम की कमान कोच के रूप में संभाली, तो उन्होंने शुरुआत में ही एक बात साफ कर दी थी- अब टीम में जगह नाम से नहीं, बल्कि प्रदर्शन से मिलेगी। पहले ऐसा होता था कि बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करने में चयनकर्ताओं, कप्तान और कोच के हाथ फूल जाते थे। लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है।

गौतम गंभीर ने ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की, जहां टीम किसी एक स्टार पर निर्भर न रहे। जहां हर खिलाड़ी यह समझे कि अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, तो उसकी जगह लेने के लिए कई खिलाड़ी तैयार बैठे हैं। यह सोच उनके अपने अनुभव से भी निकली है। 2011 के विश्व कप फाइनल को याद कीजिए। उस मैच में गौतम गंभीर ने 97 रन की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली थी। लेकिन उस जीत की चर्चा में अकसर धोनी के छक्के और उनकी कप्तानी का ही जिक्र होता है।

टी-20 विश्व कप में भी संजू सैमसन की तीन पारियों को देखिए- 97, 89, 89... हर बार वो शतक के इतने नजदीक आए, लेकिन उन्होंने निजी रिकॉर्ड बनाने के लिए रन रेट को गिरने नहीं दिया और एक भी बॉल खराब नहीं की। पहले बड़े खिलाड़ी शतक के करीब पहुंचकर बड़े शॉट्स छोड़कर सिंगल लेकर पहले अपना शतक पूरा करते थे, लेकिन अब 99 पर पहुंचकर भी ये नए खिलाड़ी छक्के या चौके के बारे में सोचते हैं।

गौतम गंभीर ने कई बार कहा है कि क्रिकेट एक टीम गेम है और जीत का श्रेय किसी एक खिलाड़ी को नहीं दिया जाना चाहिए। आज जब वे भारतीय टीम के कोच हैं तो उन्होंने उसी सोच को टीम की संस्कृति का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। हालांकि यह बदलाव आसान नहीं था। जब टीम हारती थी तो

इस टीम में कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है, जिसकी छवि बाकी खिलाड़ियों से कई गुना बड़ी हो। इस टीम में युवा खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। ये विज्ञापनों में कम दिखते हैं, लेकिन मैदान पर सही समय पर कमाल जरूर दिखाते हैं।

सबसे पहले गंभीर को ही निशाने पर लिया जाता था। सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होती थी और कई बार यह कहा गया कि वह टीम को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी योजनाओं के परिणाम कभी भी रातों-रात नहीं मिलते।

आज भारत शायद दुनिया का इकलौता देश है, जिसके पास टेस्ट, वनडे और टी-20 के लिए अलग-अलग मजबूत टीमें तैयार हैं। इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर के करीब 100 खिलाड़ियों का विशाल टैलेंट पूल भी मौजूद है।

यह स्थिति अचानक नहीं बनी है। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, जहां खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग और तकनीक की सुविधाएं मिलती हैं। घरेलू क्रिकेट की प्राइज मनी को लगभग 300 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। महिला क्रिकेट को भी पुरुष क्रिकेट के बराबर महत्व दिया गया और आईपीएल की तरह महिला प्रीमियर लीग शुरू की गई। और आज स्थिति यह है कि भारत पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में विश्व चैंपियन है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

डिफ्रेंट एंगल • चिंता से चिंतन का सफर तय करें

थोड़ी-बहुत फिक्र भली, पर ज्यादा चिंता किस काम की?

सैल्फ-हैल्प

रश्मि बंसल

लेखिका और स्पीकर

mail@rashmibansal.in

रोज ऑफिस से निकलने के पहले आप मम्मी को मैसेज करती हो- निकल गई। एक दिन रिक्शे में बैठने के बाद पता चलता है कि फोन ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, मम्मी समझ जाएंगी। लेकिन आप घर में घुसे, तब जाकर मम्मी ने चैन की सांस ली। फोन ऑन किया तो देखा- 12 मिस्ड कॉल।

अरे, चिंता तो होती है, न!- मम्मी ने कहा, जैसे कि उनकी चिंता प्रकृति की देन हो। जैसे हम सांस लेते हैं, उसी तरह इस देश में हम 24 घंटे किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। बच्चों के एग्जाम- चिंता। घर पर मेहमान- चिंता। कामवाली आज लेट- चिंता।

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लव लैंग्वेज यानी कि प्यार जताने के पांच तरीके होते हैं। उन्हें क्या पता हमारे पास एक और तरीका है- चिंता।

वैसे शायरों ने भी भले सीधे तरीके से इसका जिक्र नहीं किया हो, लेकिन उनके गाने अगर आप ध्यान से सुनें तो समझ जाएंगे- आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे-बैठे जीने का सहारा हो गया। मतलब?

मतलब ये कि बीस साल बाद कोई होगा पूछने वाला- तुमने खाना खाया? दवाई ली? बिजली का बिल भरा? वैसे अंग्रेजी में इसे कहते हैं 'नैगिंग' और कई बार आप चिढ़ के जवाब भी दोगे- बस करो। लेकिन अगर कल ये सवाल बंद हो जाएं तो आपको बुरा भी लगेगा। कि किसी को मेरी पड़ी नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा।

आज ज्यादातर शादियां इसी पूछ-ताछ के सहारे चल रही हैं। चाहे कोई 'आई लव यू' न कह रहा हो, कम से कम इस विशाल दुनिया में मेरे ब्लड प्रेशर की किसी को तो फिक्र है।

वैसे कभी-कभी हंसी भी आती है। प्लेन में जैसे ही अनाउन्स होता है- 'आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो'- आस-पास चार फोन बजेंगे। सवाल है- 'पहुंच गए'? अब फोन बजा है, उठाया है, मतलब पहुंच ही गए होंगे। भगवान न करे, कोई हादसा हो जाए, तो सवाल-जवाब का मौका ही नहीं मिलेगा...

अब यहां तक की चिंता तो चलो, एक तरह से ठीक है। मगर मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम में से कई लोगों ने अपनी चिंता का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। दुबई में बम- चिंता। स्टॉक मार्केट डाउन- चिंता। पॉलिटिक्स में घोटाला- चिंता। इन टॉपिक्स पर चिंता से दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन असर होता है आप पर।

सुना होगा आपने 'हॉन्टेड हाउस' के बारे में। जैसे बंगले पर कब्जा करके भूत बेमतलब घूमता है, उसी तरह चिंता। यह एक भूत है, जिसने एक बार आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया, तो फिर वो आपको डराता रहेगा। कोई भी सिचुएशन हो, आपको उसमें कुछ नेगेटिव ही दिखाई देगा।

मैं यह नहीं कह रही कि आप आंखें मूंद कर बैठिए। दुनिया में जो हो रहा है। उससे वाकिफ होना जरूरी है। लेकिन चिंता के बजाय चिंतन कीजिए। दोनों के बीच बस एक फर्क है- चिंतन करने वाला इंसान डरता नहीं। हालात आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन हालात के प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, यह आपके हाथ में है।

आजकल एग्जाम के पहले कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उल्टियां आने लगती हैं। डॉक्टर मानते हैं इसकी वजह है एंग्जायटी यानी कि घबराहट- जो है चिंता का बड़ा भाई। अजीब बात यह है कि ज्यादातर वो बच्चे घबराते हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है, अच्छी तरह से। उनका डर यह है कि नंबर थोड़े कम आए तो क्या होगा?

उन्होंने अपने मन में एक लंबी कहानी लिख डाली है कि मेरा एडमिशन सही जगह नहीं होगा, मेरी

हम में से कई लोगों ने अपनी चिंता का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। दुबई में बम- चिंता। स्टॉक मार्केट डाउन- चिंता। पॉलिटिक्स में घोटाला- चिंता। इन सब पर चिंता से दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन असर होता है आप पर।

लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भाई, जीवन में सुख और सफलता पाने के एक नहीं, अनेक रास्ते हैं। लेकिन घबराए हुए इंसान को उन रास्तों पर चलने की हिम्मत न होगी।

इसलिए पैरेंट्स को मेरी सलाह है, बच्चों को निडरता से जीना सिखाइए। थोड़ी-बहुत चिंता ठीक है, लेकिन अगर वे आपको हर वक्त चिंतित देखेंगे, तो वे भी उस भूत को अपने मन में बसा लेंगे। जो ज्यादा चिंता करता है, कुछ भी करने से डरता है। सोच ही सोच में फंस जाता है, सुख में भी दुःख ही पाता है।

जो होना है सो होकर रहेगा, आपकी चिंता से कुछ न बदलेगा।

चिंता से चिंतन का सफर तय कीजिए, जीवन अपना आनंदमय कीजिए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

14 मार्च के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में

इकोनॉमिस्ट ने मिडिल ईस्ट युद्ध के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के सभी पहलुओं का विश्लेषण किया है। मैगजीन ने चीन में वसीयत न होने से बढ़ रहे विवादों को भी खास खबर में जगह दी है।

The Economist

दैनिक भास्कर

अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल **DB एप** पर **हर शनिवार** पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

इंग्लैंड के बैंक नोटों पर वन्य जीवन की झलक मिलेगी

70 प्रतिशत ब्रिटिश नागरिक स्वयं को पशु प्रेमी बताते हैं। लोगों ने 2023 में पेट्स की देखभाल पर 64 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। लिहाजा, अचरज की बात नहीं है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने अगले बैंक नोटों पर जानवरों को पेश करने की घोषणा की है। मौजूदा नोटों पर मनुष्य अंकित हैं लेकिन उन पर विवाद उठे हैं। पांच पौंड के नोट पर चर्चिल की तस्वीर है। उन्हें रंगभेदी कहा जाता है। वन्य जीवन सुरक्षित पसंद हो सकती है। बैंक नोट पर पेश किए जाने वाले जानवर का चयन करने से पहले जनता की राय ली जाएगी।

ट्रम्प की लोकप्रियता में गिरावट आने के आसार बढ़े

2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प ने पेट्रोल की कीमतों के मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना की थी। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। इससे उनकी रेटिंग कम होने के आसार नजर आते हैं। किसी सैन्य अभियान की शुरुआत में जनता के बीच राष्ट्रवाद में आने वाला सामान्य उछाल सामने नहीं आया है। वैसे, एक नए सर्वेक्षण में 83% रिपब्लिकनों ने ईरान युद्ध के लिए ट्रम्प का समर्थन किया है। वहीं रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकन का कहना है, युद्ध जितना लंबा चलेगा, राष्ट्रपति के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा।

आर्कटिक में नाटो के सैन्य अभ्यास के पीछे कई संकेत

उत्तरी नार्वे और फिनलैंड के इलाकों में इस समय 14 नाटो देशों के 32,500 सैनिक आर्कटिक युद्ध की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोल्ड रिस्पॉन्स नामक दस दिन की रूटीन एक्सरसाइज का लक्ष्य आमतौर पर अकेले रूस को संकेत देने के लिए रहता है। इस वर्ष इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर भी है। ट्रम्प कई मर्तबा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी वहां पहुंचकर अमेरिका को साफ संदेश देंगे कि नाटो देश तैयारियां कर रहे हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन होर्मुज की खाड़ी के वर्तमान घटनाक्रम से दुनिया के लिए तेल और गैस सप्लाई का बाजार हमेशा के लिए बदल जाएगा

ईरान युद्ध से भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 9 मार्च को ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ उनका अभियान जल्द खत्म हो जाएगा। ट्रम्प को पहले टैरिफ लगाने की कीमत समझ में आई और अब उन्हें युद्ध के असर का अहसास होने लगा है। ईरान द्वारा होर्मुज की खाड़ी बंद करने से दुनिया की 15 प्रतिशत तेल सप्लाई रुक गई है। अमेरिकी वोटर महंगाई से त्रस्त हैं। इसलिए मध्यावधि चुनाव का सामना कर रहे ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वे यह कीमत नहीं चुका सकते। युद्ध से ग्लोबल अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान होगा। हालांकि, इसका असर देशों पर अलग-अलग होगा। अमेरिका और यूरोप के मुकाबले भारत सहित एशिया के कुछ देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इन देशों की जीडीपी कम हो सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को आघात लगने की शुरुआत हो चुकी है।

फिर भी, आर्थिक नीति की तरह ट्रम्प युद्ध और शांति के मामले में भी अराजक हैं। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पहले से कहीं ज्यादा विकट लड़ाई की बात कही है। भ्रम की स्थिति ट्रम्प के पास अच्छे विकल्पों की कमी दर्शाती है। जहां व्यापार युद्ध को कम करना कमोबेश उनके हाथ में है, वहीं पुराने ऊर्जा बाजार जैसे- तेल, गैस, बिजली आदि को वे बहाल नहीं कर सकते हैं। घटनाक्रम कुछ भी हो पर विश्व ऊर्जा असुरक्षा के नए दौर में प्रवेश कर रही है।

यह सच है कि दुनिया 1973 के समान आज तेल पर निर्भर नहीं है जब अरब देशों के प्रतिबंध से कच्चे तेल के मूल्य चार गुना बढ़ गए थे। परंतु आज तेल की मांग बहुत अधिक है, लिहाजा सप्लाई अस्त-व्यस्त होने से मूल्य बढ़ेंगे। 1970 के मुकाबले सप्लाई में ज्यादा कमी आएगी। संकट के सबसे बुरे दौर में भी व्यापारियों ने खाड़ी के अनिश्चितकाल तक बंद होने की संभावना को ध्यान में रखकर तेल मूल्यों को ज्यादा नहीं बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में मांग और सप्लाई के बीच संतुलन के लिए आवश्यक तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो सकती है। विश्व की इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट की अहम भूमिका है। जाहिर है, उसमें रुकावट से गंभीर नुकसान होगा।

युद्ध का आघात तेल तक सीमित नहीं है। ड्रोन हमले से कतर का मुख्य गैस प्लांट बंद है। कतर से निर्यात बंद होने से एशिया में हड़बड़ी मच गई है। युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया बदल जाएगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अब जानते हैं कि पेट्रोल, गैस के मूल्य अमेरिका की कमजोरी है। खासतौर से यदि ईरान मान लेता है कि सुरक्षित रहने के लिए उसे परमाणु हथियार की जरूरत है तो भू-राजनीतिक तनाव के साथ ऊर्जा बाजार अस्त-व्यस्त होते रहेंगे। निवेशकों, कारोबारियों और नीति निर्माताओं को नए हालात से जूझना पड़ेगा। पेट्रोल, गैस के मूल्यों में बढ़ोतरी के खतरों के साथ कारोबारों को नए जोखिम का सामना करना पड़ेगा। वोटर राजनेताओं से पेट्रोल, गैस पर सब्सिडी की अपेक्षा करेंगे। यूक्रेन युद्ध के समय यूरोपीय देशों की सरकारों ने जनता को भारी ऊर्जा सब्सिडी दी थी। इससे एशिया के गरीब देशों पर बोझ पड़ेगा। उन पर कर्ज बढ़ेगा।

ट्रम्प को विश्वास होगा कि अगर बाजारों में दहशत फैलती है तो वे लड़ाई रोककर युद्ध के आर्थिक नुकसान को सीमित कर सकते हैं, लेकिन काफी नुकसान पहले ही हो चुका है। उनके द्वारा छेड़े गए व्यापार युद्धों के विपरीत उनके हाथ में नियंत्रण के सभी सूत्र नहीं हैं। इस सप्ताह ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक प्रवक्ता ने कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा, यह हम तय करेंगे।

शेयर बाजारों की हालत पतली

अमेरिका के शेयर सूचकांक एसएंडपी 500 में मार्च में 1.5% की गिरावट आई। यूरोप में इस माह शेयर बाजार 5-6% नीचे आ चुके हैं। वहीं एशिया में स्थिति और ज्यादा खराब है। जापानी शेयर बाजार में 7.3% और दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में 10% से अधिक की गिरावट अभी तक आ चुकी है।

एशियाई देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा

एशियाई देश आयातित तेल, गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। समुद्री मार्ग से सप्लाई होने वाले खाड़ी के 40% तेल और 80% गैस की खरीद चीन, भारत और जापान करते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लाखों वर्कर खाड़ी से अपने देश अरबों रु. भेजते हैं। खाड़ी देशों की इकोनॉमी को नुकसान से इसमें कमी आएगी।

भारत की जीडीपी 0.6% घटने का अनुमान

भारत अपनी जीडीपी का 3 प्रतिशत हर साल दुनियाभर से तेल आयात करने पर खर्च करता है। तेल के दाम बढ़ने से यह खर्च तेजी से बढ़ेगा। गोल्डमैन सॉक्स का अनुमान है, तेल के मूल्य 70 डॉलर प्रति बैरल से 85 डॉलर होने की स्थिति में भारत की जीडीपी में 0.6 प्रतिशत तक की कमी आएगी।

उर्वरक सहित कई चीजों के दाम बढ़ेंगे

- होर्मुज की खाड़ी से दुनिया की 15% तेल और 20% गैस सप्लाई बंद। गैस से बनने वाले फर्टिलाइजर के मूल्य बढ़ेंगे। फूड के मूल्य बढ़ सकते हैं।
- तेल रिफाइनिंग से बनने वाला सल्फर महंगा। हीलियम गैस की कमी से चिप का उत्पादन प्रभावित होगा।
- यदि होर्मुज की खाड़ी माह के अंत तक बंद रहेगी तो कच्चे तेल के मूल्य 150 डॉलर या 200 डॉलर प्रति बैरल तक उछल सकते हैं।
- निर्यातक होने के कारण तेल के मूल्य बढ़ने से अमेरिका को फायदा है। फिर भी, अमेरिकी उपभोक्ता पेट्रोल के दाम बढ़ने से प्रभावित हो रहे हैं।
- गैस के दाम बढ़ने से यूरोप पर ज्यादा असर। यूरोप में 9 मार्च को एक मेगावाट घंटा गैस के दाम 65 डॉलर से अधिक हो गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद ये 75% की बढ़ोतरी है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

समाज चीन के बुजुर्गों के हाथ में संपत्ति

विरासत में मिली संपत्ति संभालने के लिए चीन में नई पीढ़ी को करा रहे कोर्स

चीन में समाज के एक छोटे वर्ग को जल्द ही अपार संपत्ति विरासत में मिलने वाली है। चीन की अधिकतर संपत्ति बुजुर्गों के पास है। हुरुन रिसर्च के मुताबिक 2025 में 5 अरब युआन (6655 करोड़ रु.) की संपत्ति 60 वर्ष या अधिक आयु के 49% लोगों के पास थी।

दरअसल 1970 में लागू हुए सुधारों के बाद संपत्ति बनाने वाली पहली पीढ़ी अब धीरे-धीरे दुनिया छोड़ रही है। 2025 के शुरुआती दशक में 462 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मालिक चीनी नागरिक करीब 194 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अपने वारिसों को सौंपेंगे। इससे गड़बड़ी पैदा होगी। सिंगहुआ यूनिवर्सिटी के गाव हाओ ने 2003 से 2024 के बीच लिस्टेड चीनी कंपनियों के फाउंडर या नियंत्रक शेयरहोल्डरों की मौतों का अध्ययन किया और पाया कि मृत्यु की औसत आयु 64 वर्ष थी। इनमें केवल छह लोगों ने अपनी

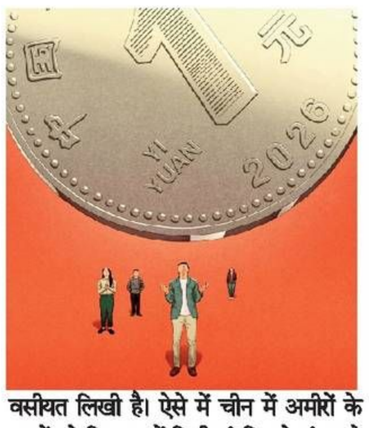

वसीयत लिखी है। ऐसे में चीन में अमीरों के बच्चों को विरासत में मिली संपत्ति को संभालने के लिए कोर्स कराए जा रहे हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

सुरक्षा

युद्ध के कारण इंश्योरेंस की संख्या में हो रही बढ़ोतरी

आम लोगों की तरह कंपनियों के बॉस भी पूछ रहे हैं, आगे क्या होगा। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। उन्होंने उससे पहले वेनेजुएला के तानाशाह राष्ट्रपति को पकड़ लिया था। यूक्रेन युद्ध और ताइवान की खाड़ी में चीन की आक्रामक गतिविधियों से भी कारोबार जगत में बेचैनी है। इसलिए कंपनियां इंश्योरेंस के जरिये सुरक्षा के प्रयास कर रही हैं। ऐसी पॉलिसी का इस्तेमाल गरीब देशों में निवेश की सुरक्षा के लिए होता है। इधर, इंश्योरेंस कारोबार का तेजी से विस्तार हो रहा है। 496 पश्चिमी कंपनियों को 2020 से 2025 के बीच किसी किस्म का राजनीतिक नुकसान हो चुका है। कई वर्ष तक कंपनियों के इंश्योरेंस पर विश्व बैंक की एजेंसी या अमेरिका चीन की सरकारी एजेंसियों का दबदबा था। अब प्राइवेट कंपनियों का दखल बढ़ा है। अब वे 18 प्रतिशत नई पॉलिसी दे रही हैं। पांच साल पहले यह दस प्रतिशत था।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बिजनेस एआई के क्षेत्र में वर्चस्व की जंग

लाखों करोड़ के आईपीओ ला रहे हैं, ऑल्टमैन, अमोदेई और इलॉन मस्क

सैम आल्टमैन के नेतृत्व की ओपनएआई, डैरियो अमोदेई की एंथ्रोपिक और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स आईपीओ लाने वाले हैं। 77 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाली ओपनएआई 92 लाख करोड़ रु. मूल्य का स्तर हासिल करना चाहती है। ऐसे ही 35 लाख करोड़ रु. मूल्य की एंथ्रोपिक 46 लाख करोड़ रु. और 115 लाख करोड़ रुपए मूल्य की स्पेसएक्स 138 लाख करोड़ रुपए के स्तर को छूने की इच्छा रखती है।

वेंचर कैपिटलिस्ट टोमास्ज तुंगुज कहते हैं यदि हर कंपनी अपने 15% शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इनके द्वारा जुटाई गई कुल रकम पिछले दस साल में अमेरिका में आए सभी आईपीओ की कुल धनराशि के बराबर होगी। ऑल्टमैन अवसरवादी हैं। आल्टमैन ने स्वयं को ट्रम्प और अमोदेई के बीच सुलह कराने वाले के रूप में पेश किया। फिर मस्क

की एक्सएआई के समान एंथ्रोपिक की कीमत पर डिफेंस के कांट्रेक्ट हासिल कर लिए। अमोदई ने एक मेमो में आल्टमैन को धोखेबाज और ट्रम्प का चाप्लूस बताया था। वहीं मस्क आल्टमैन के प्रति बेहद आक्रामक हैं। वे अपना 350 करोड़ रुपए का डोनेशन वापस मांग रहे हैं। उन्होंने ओपनएआई और उसकी बड़ी सहयोगी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बिज़नेस भास्कर

Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ

नई दिल्ली, शनिवार 14 मार्च, 2026

बिजनेस ब्रीफ

शेयर निवेशक तेजी से बढ़े, डीमैट खाते अब 21.6 करोड़

मुंबई | देश में शेयर निवेशक तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिसंबर तक डीमैट अकाउंट 21.6 करोड़ से ज्यादा हो गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आसान डिजिटल वेरिफिकेशन और मोबाइल ट्रेडिंग को इसकी वजह बताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीरो ब्रोकरेज मॉडल और नई टेक्नोलॉजी के कारण रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, जबकि करीब डेढ़ साल से शेयर बाजार से कोई कमाई नहीं हुई है।

फिच ने भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, अब 7.5%

नई दिल्ली| ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। पहले यह 7.4% था। एजेंसी के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग, उपभोक्ता खर्च और निवेश से आर्थिक रफ्तार बढ़ रही है। एजेंसी ने 2026-27 के लिए वृद्धि दर का अनुमान 6.7% रखा है। हालांकि ये भी कहा है कि बढ़ती महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता खपत घटा सकती हैं।

म्यूचुअल फंड्स के लिए लोन के नियम 1 अप्रैल से

मुंबई | बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए बैंकों से इंट्राडे उधार लेने के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उधार केवल यूनिट रीपर्चेज/रिडम्पशन और ब्याज चुकाने के लिए लिया जा सकेगा। उधार की राशि उसी दिन की 'गारंटीड रिसीवेबल्स' से अधिक नहीं होगी। यह नियम इसी साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। इससे टाइमिंग मिसमैच दूर होगा, लेकिन लागत एसेट मैनेजमेंट कंपनियां उठाएंगी।

टाटा मोटर्स को 5,000 से ज्यादा बसों का बड़ा ऑर्डर

मुंबई| टाटा मोटर्स को देशभर के अलग-अलग राज्य परिवहन निगमों से 5,000 से अधिक बस और बस चेसिस के ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर सरकारी ई-बिडिंग प्रक्रिया के जरिये हासिल किए गए हैं। कंपनी इनकी डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से करेगी। इन बसों का इस्तेमाल इंटरसिटी और सिटी ट्रांसपोर्ट सेवाओं में होगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

निर्यात की अनिश्चितता से बढ़ी चीनी मिलों की परेशानी

नई दिल्ली | देश का चीनी उद्योग इन दिनों पांच तरफ से दबाव का सामना कर रहा है। इससे उनकी माली हालत कमजोर हो सकती है। इसका असर किसानों को भुगतान या गन्ने की खरीदारी भी प्रभावित होने की आशंका है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के मुताबिक नीति में बदलाव, स्थिर समर्थन मूल्य, ऊर्जा संकट और निर्यात अनिश्चितता ने उद्योग की लागत बढ़ा दी है।

भास्कर एनालिसिस सपोर्ट लेवल टूटे; टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसे शेयर 16% तक गिरे

निफ्टी 9 दिनों में 6 बार 1% से ज्यादा गिरा; कोविड के बाद पहली बार इतनी तेज गिरावट

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

ईरान युद्ध के चलते घरेलू शेयर बाजार की गिरावट गहराती जा रही है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी शुक्रवार को 2% टूटकर 23,151 पर और सेंसेक्स 1,471 अंक (1.9%) गिरकर 74,564 पर बंद हुआ। इसी के साथ इन इंडेक्स ने वित्त वर्ष 2025-26 की पूरी बढ़त गंवा दी है। इस साल निफ्टी अब तक 13 बार 1% से अधिक टूट चुका है। पिछले 9 दिनों में से 6 दिन 1% से ज्यादा गिरावट देखी गई। कोविड के बाद पहली बार इतनी तेज गिरावट आई है। एसबीआई सिक्युरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट सुदीप शाह के मुताबिक, यह गिरावट लगातार तीसरे हफ्ते जारी रही। ये दर्शाता है कि निवेशक बाजार में 'बाय ऑन डिप' यानी गिरावट पर खरीदारी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। गिरावट इतनी गहरी रही कि मिडकैप इंडेक्स 2.6% और स्मॉलकैप इंडेक्स 2.7% गिर गए। यानी हर तरफ बिकवाली हुई।

बड़े संकट में औसतन 12% गिरता है इंडेक्स, 2000-09 के बीच ऐसा 22 बार हुआ

दशक	कितनी बार	औसत गिरावट	सबसे बड़ी गिरावट
1970-79	1	-11.3%	-11.3%
1980-89	16	-12.2%	-16.9%
1990-99	19	-14.1%	-23.3%
2000-09	22	-15.3%	-33.3%
2010-19	10	-11.8%	-14.5%
2020-29	4	-11.3%	-11.7%

डर हावी: मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, पर गिरावट का पलड़ा भारी

शाह के मुताबिक टेक्निकल चार्ट पर मोमेंटम इंडिकेटर (आरएसआई 25 से नीचे) बता रहे हैं कि बाजार 'ओवरसोल्ड' जोन में है, लेकिन गिरते ट्रेंड की ताकत (एडीएक्स) बेहद मजबूत है। ऐसे में निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए।

जियोजित इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर कहते हैं कि जब तक तेल की कीमतें कम नहीं होतीं, सुधार मुश्किल है। इससे भारतीय कंपनियों की बैलेंसशीट पर भी असर पड़ेगा। स्थायी सुधार तभी आएगी जब युद्ध शांत होने के ठोस संकेत मिलें। गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता पर स्पष्टता आए।

युद्ध की शुरुआत में क्रूड 120 डॉलर तक गया था, जो अभी 100 डॉलर के आसपास है। फारस की खाड़ी में अब तक 16 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से गैस की कीमतें भी 14% तक बढ़ गई हैं। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मार्जिन पर पड़ेगा।

इतिहास क्या कहता है?: पिछले 40 सालों में जब भी बड़े युद्ध हुए हैं, बाजार औसतन 11% तक गिरता है। अभी निफ्टी 8% गिरा है, यानी 3-4% की गिरावट की गुंजाइश अभी और दिख रही है।

जेफरीज की चेतावनी... बाजार अभी भी धोखे में

जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड का मानना है कि मार्केट युद्ध की गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। बाजार को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प आखिरी वक्त पर पीछे हट जाएंगे और युद्ध रुक जाएगा। लेकिन वुड चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बाजारों में और भी बड़ा नुकसान होना बाकी है।

5-10% और गिरावट की आशंका: चोक्कालिंगम

इक्विनॉमिक्स के फाउंडर और अनुभवी एनालिस्ट जी चोक्कालिंगम ने कहा कि बाजार में यहां से 5% से 10% की और गिरावट संभव है, जो लोग रिस्क नहीं ले सकते, उन्हें थोड़ा हिस्सा बेचकर कैश पर बैठना चाहिए। जोखिम लेने वाले निवेशक लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं।

ट्रेंड पलटा... गिरावट में ब्लूचिप कंपनियां तक टिक नहीं रहीं

आमतौर पर जब बाजार गिरता है, तो बड़ी कंपनियां खुद को संभाल लेती हैं, लेकिन इस बार विदेशी निवेशक इतना ज्यादा बेच रहे हैं कि दिग्गज कंपनियां भी धराशायी हो गई हैं। मार्च में अब तक टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, और मारुति जैसे शेयर 16% तक टूट चुके हैं। क्विक कॉमर्स एटर्नल (पूर्व में जोमैटो) एक माह में 25% टूट चुका है।

न्यू एसेट • शेयर बाजार में भारी गिरावट से निराशा के बीच राहत

रीटः छह साल में 6 गुना बढ़ा बाजार, 27 हजार करोड़ से 1.7 लाख करोड़

सुनयना चड्ढा | नई दिल्ली

अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदना मुमकिन नहीं है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। भारत का यह बाजार पिछले छह साल में 6 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। अब नए निवेशकों के लिए दरवाजे और चौड़े हो रहे हैं। रीट की ट्रेडिंग भी स्टॉक एक्सचेंज में होती है। सीबीआरई इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में भारत में लिस्टेड रीट्स का कुल मार्केट कैप 1,72,600 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2019-20 में यह सिर्फ 27,100 करोड़ रुपए का था। शेयर बाजार में लगातार गिरावट से फैली निराशा के बीच ये राहत देने वाला निवेश है।

7 लाख करोड़ से ऊपर निकलेगा बाजार: सीबीआरई का अनुमान है कि भारत में स्मॉल और मीडियम रीट्स का बाजार 7 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा हो सकता है।

कमाई: लिस्टिंग के बाद औसत रिटर्न 37%

देश में फिलहाल 5 रीट्स लिस्टेड हैं। इनमें से माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट की वैल्यू अप्रैल-दिसंबर 2025 में 31% बढ़ गई। बाजार में लिस्ट होने के बाद से इसने 57% रिटर्न दिया है। यह सभी रीट्स में सबसे ज्यादा है। वैसे सभी 5 रीट्स का लिस्टिंग के बाद औसत रिटर्न 37% रहा है।

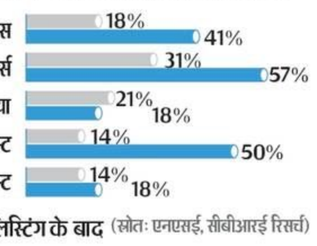

(स्रोतः एनएसई, सीबीआरई रिसर्च)

भास्कर नॉलेज

रीट्स क्या हैं, इन्हें कैसे कमाई होती है, इनमें कैसे निवेश कर सकते हैं?

रीट बड़ी प्रॉपर्टी में छोटे निवेश का माध्यम है। ये ऑफिस पार्क, शॉपिंग मॉल और वेयरहाउस जैसी प्रॉपर्टी से किराया कमाता है। उस कमाई का कम से कम 90% हिस्सा निवेशकों को लौटाता है। शेयर बाजार में इसकी यूनिट खरीदकर आप भी इस कमाई के हिस्सेदार बन सकते हैं।

मौकाः तीन फैसले रीट मार्केट को आगामी महीनों और रफ्तार दे सकते हैं

❶ सेबी ने 1 जनवरी 2026 से रीट्स को इक्विटी (जैसे शेयर) के रूप में वर्गीकृत किया है। इससे म्यूचुअल फंड की भागीदारी बढ़ेगी।

❷ आरबीआई ने बैंकों को सीधे रीट को कर्ज देने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। इससे रीट सेगमेंट में पूंजी की दिक्कत नहीं रह जाएगी।

❸ केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकारी कंपनियों की संपत्तियों को रीट्स के जरिये बाजार में लाने की योजना है। बाजार का तेज विस्तार होगा।

ट्रेंड • ईरान युद्ध का असर, फोन की जगह इंडक्शन की खरीद

स्मार्टफोन की बिक्री 15% घटने, पर दाम 20% बढ़ने के आसार

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

भारत के स्मार्टफोन बाजार पर ईरान युद्ध का गहरा असर पड़ा है। मोबाइल स्टोर्स पर ग्राहकों की आवाजाही 28% घटी है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण उपभोक्ता स्मार्टफोन खरीदारी फैसला टाल रहे हैं। इसके चलते 2026 में स्मार्टफोन की बिक्री 13-15% घट सकती है।

पिछले साल कंपनियों ने 15.2 करोड़ मोबाइल फोन बाजार में भेजे थे। आईडीसी के मुताबिक, इस साल की पहली तिमाही में शिपमेंट घटकर 2.7 करोड़ फोन रह सकती है, जो पिछले साल समान अवधि में 3.2 करोड़ थी। आईडीसी की सीनियर रिसर्च मैनेजर उपासना जोशी के मुताबिक उत्पादन लागत बढ़ने से स्मार्टफोन की औसत कीमत में 15 से 20% बढ़ोतरी हो सकती है। काउंटरपॉइंट के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक का मानना है कि अप्रैल-जून तिमाही, 2020 की महामारी के बाद सबसे कठिन होगी। यूएई, ईरान और यूक्रेन को होने वाले एक्सपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ा है।

प्राथमिकता: जरूरी घरेलू सामान पर बढ़ा फोकस

रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता रसोई गैस की किल्लत के डर से स्मार्टफोन के बजाय इंडक्शन स्टोव खरीद रहे हैं। वहीं, गर्मी शुरू होने के कारण एसी और फ्रिज भी ग्राहकों की पहली पसंद बन गए हैं।

लागत: मेमोरी कम्पोनेंट्स और मालभाड़ा महंगे हुए

- स्मार्टफोन के बढ़ते दाम का कारण मेमोरी चिप्स के दाम 50% तक बढ़ना है। हवाई मालभाड़ा भी बढ़ा है।
- फोन के 95% पुर्जे दिल्ली, बेंगलुरु के रास्ते हवाई मार्ग से आते हैं। मध्य-पूर्व में तनाव के बीच ईंधन महंगा होने से लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ा है।

बिक्री: रिटेल स्टोर्स पर बिक्री अब दो-तिहाई ही रह गई

आईडीसी के अनुसार जनवरी में बिक्री सिर्फ 80 लाख यूनिट रही। पहली तिमाही में शिपमेंट 50 लाख घटने का अंदेशा है। आर्थिक अनिश्चितता के कारण रिटेल स्टोर्स सेल केवल दो-तिहाई रह गई है।

आईडीबीआई का निजीकरण अटका, बोलियां कमजोर

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। सरकार को मिली दोनों बोलियां न्यूनतम तय कीमत से कम होने के कारण व्यावहारिक नहीं मानी गई हैं। इसके चलते बिक्री प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है।

सरकार और एक बीमा कंपनी मिलकर आईडीबीआई बैंक में अपनी 61% हिस्सेदारी बेचना चाहते थे। बैंक के इतने शेयरों का मौजूदा बाजार भाव करीब 55,000 करोड़ रुपए है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और यूएई की एमिरेट्स एनबीडी ने बोली लगाई थी। सरकार कई वर्षों से आईडीबीआई बैंक बेचने की कोशिश कर रही है। इस बीच यह बैंक हाल के वर्षों में घाटे से उबरकर मुनाफे में लौट आया है।

मौका • भारत में गोल्ड पर 9 साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, चीन में प्रीमियम पर बिक्री

सोना ₹2,465 छूट पर, 1 हफ्ते में 3 गुना डिस्काउंट

भास्कर न्यूज | मुंबई

भारत में इस हफ्ते सोने पर छूट 9 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। डीलरों ने इस हफ्ते सोना आधिकारिक कीमतों से 83 डॉलर प्रति औंस तक डिस्काउंट पर बेचा। यानी सोने पर 2,465 रु/10 ग्राम छूट मिल रही है। यह जुलाई 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। कमजोर मांग के बीच आयात शुल्क से बचने के लिए अपनाए जा रहे गैरकानूनी तरीके भारत में सोने पर छूट की वजह हैं। मध्य-पूर्व के देशों में बढ़ते तनाव ने चीन में सोने को संभावित जोखिम से बचाव का साधन बना दिया। वहां प्रीमियम दोगुना हो गया। यानी भारत में सोना बाजार से कम कीमतों पर व चीन में ऊंचे दाम पर बिक रहा है।

घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमत 1,904 रुपए, चांदी की 7, 813 रुपए घटी

घरेलू सराफा बाजारों में शुक्रवार को चांदी की औसत कीमत 7,813 रुपए घटकर 2,60,488 रुपए किलो रह गई। 24-कैरेट सोना भी 1,904 रुपए घटकर 1,58,399 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। 22-कैरेट (जेवराती सोना) 1,745 रुपए सस्ता होकर 1,45,093 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। जनवरी से अब तक सोना 16,941 रुपए और चांदी 1,19,500 रुपए सस्ती हो चुकी है।

छूट क्यों...तस्करी के जरिये आयात बढ़ा, वित्त वर्ष के अंत में ज्वेलर्स की मांग कम

तस्करी बढ़ी: सोने की तस्करी बढ़ी है। मुंबई के एक बुलियन डीलर ने बताया कि कुछ आयातक 90% से अधिक सोना वाले गहनों को 'प्लेटिनम-स्टडेड ज्वेलरी' घोषित कर रहे हैं, जिस पर आयात शुल्क नहीं लगता।

मांग कमः बुलियन ट्रेडरों का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दो ही हफ्ते बचे हैं। ऐसे में ज्वेलर्स अकाउंट क्लोज करने करने में व्यस्त हैं। वे खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इस बीच रिटेल मांग भी कम है।

भारत के उलट चीन, हांगकांग, जापान में सोने के दाम वाजिब भाव से ज्यादा

- चीन में सोना वैश्विक कीमतों से 20-30 डॉलर प्रति औंस ऊपर बिका। पिछले हफ्ते यह प्रीमियम 13-15 डॉलर ही था।
- चीन के बैंक पीबीओसी ने लगातार 16वें महीने सोने की खरीदारी की, हालांकि नए आयात कोटा न होने से आपूर्ति सीमित है।
- हॉन्ग कॉन्ग में सोना 3 डॉलर प्रीमियम पर, सिंगापुर में 2 डॉलर तक प्रीमियम पर और जापान में 1 डॉलर प्रीमियम पर बिक रहा है।

खास वेंडिंग मशीनें पर्यटकों को आकर्षित करेंगी

ब्रिटेनः 21 लाख रुपए में 2 ऐतिहासिक फोन बूथ नीलाम; बनेंगी वेंडिंग मशीन

एजेंसी | लंदन

दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड के कैंटरबरी में ऐतिहासिक फोन बूथों के दिन फिरने वाले हैं। इन दो संरक्षित ऐतिहासिक धरोहरों को डायलन एमेट ने नीलामी में करीब 21 लाख रुपए में खरीदा है। यह कीमत तय अनुमान से करीब 3.67 लाख रुपए ज्यादा रही। नए मालिक की योजना एक बूथ को आर्केड ग्रैब मशीन बनाने की है। इसमें लोग जॉयस्टिक से पंजा चलाकर खिलौने और रेस्तरां के वाउचर जीत सकेंगे। दूसरे बूथ में स्नैक वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। एमेट का मानना है कि यह बदलाव पर्यटकों को स्थानीय व्यवसायों से जोड़ेगा। इन बूथों को नई पहचान मिलने से वे अब शहर की रौनक का हिस्सा बनेंगे। यह प्रयास पुरानी धरोहर को आधुनिक जरूरतों के साथ जोड़ रहा है।

लोकलसर्कल्स सर्वे | 309 जिलों के 57 हजार लोग शामिल

57% लोगों ने कहा बीते एक हफ्ते में एलपीजी सिलेंडर मिलने में हुई देरी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश में रसोई गैस की संभावित कमी की आशंका के बीच एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। लोकलसर्कल्स के एक देशव्यापी सर्वे में के मुताबिक 57% घरेलू उपभोक्ताओं को पिछले एक सप्ताह में एलपीजी सिलेंडर मिलने में देरी का सामना करना पड़ा। वहीं, कुछ को ब्लैक मार्केट से ज्यादा कीमत देकर सिलेंडर खरीदना पड़ा।

देरी: 53% कम सप्लाई से परेशान

सर्वे में 19,307 लोगों से पूछा गया कि क्या बीते 1 हफ्ते में गैस सप्लाई में देरी हुई?

- जवाब में 43% उपभोक्ताओं ने कहा कि सिलेंडर पाने में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई।
- कुल मिलाकर 53% को डीलरों ने सप्लाई में देरी या कमी की जानकारी दी।
- 4% लोगों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

दिक्कत: 29% को सिलेंडर नहीं मिला

18,798 उपभोक्ताओं से पूछा गया कि क्या बीते 7 दिन में सिलेंडर लेने में दिक्कत हुई?

- 43% ने कहा कि बुकिंग, डिलीवरी सामान्य है।
- 29% ने बताया कि सिलेंडर उपलब्ध नहीं था।
- 7% को डिलीवरी के लिए सामान्य से ज्यादा इंतजार करना पड़ा।

कालाबाजारी: 36% से ₹500 तक ज्यादा वसूले

क्या 19,769 लोगों से पूछा गया कि क्या सिलेंडर ब्लैक मार्केट से खरीदा?

- 39% ने कहा कि उनके इलाके में ब्लैक मार्केट से खरीदारी नहीं हुई।
- 8% ने बताया कि गैस सिलेंडर पर 100 रु. तक अतिरिक्त देने पड़े।
- 11% ने 100-300 रुपए, 8% ने 300-500 रुपए अतिरिक्त दिए।
- 9% को 500 रुपए से ज्यादा अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।
- कुछ मामलों में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,500 से 2,800 रुपए तक बताई गई।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर LEAP इंडिया के पैलेट्स की बरामदगी की कार्रवाई शुरू

भास्कर न्यूज | रायपुर

बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सुपीरियर समूह की चार शहरों में स्थित कंपनियों पर शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई। कोर्ट रिसीवर ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बिलासपुर, रायपुर, नागपुर और जबलपुर स्थित परिसरों से करीब 11,951 पैलेट्स की बरामदगी शुरू की है। यह मामला 'LEAP इंडिया लिमिटेड' के साथ हुए किराये के समझौते के उल्लंघन और अक्टूबर 2025 से अवैध रूप से संपत्ति रोकने से जुड़ा है। इसके तहत LEAP इंडिया ने इन कंपनियों को पैलेट्स उपलब्ध कराए थे। कंपनी का आरोप है कि अक्टूबर 2025 में समझौता समाप्त होने के बाद भी पैलेट्स वापस नहीं किए गए और उनका उपयोग जारी रहा। कंपनी ने अदालत को बताया कि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सुपीरियर समूह ने न तो बकाया किराया चुकाया और न ही पैलेट्स वापस किए। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप वी. मारणे ने प्रारंभिक साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति की थी। न्यायालय ने पैलेट्स की पहचान, बरामदगी और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता लेने की अनुमति दी थी। फिलहाल पैलेट्स की बरामदगी की कार्रवाई जारी है।

राजमार्ग इनविट का आईपीओ 14 गुना भरा

भास्कर न्यूज | मुंबई

बाजार में भारी गिरावट के बावजूद एनएचएआई प्रायोजित राजमार्ग इनविट का आईपीओ 13.9 गुना भर गया। 6,000 करोड़ का यह पब्लिक इश्यू शुक्रवार को बंद हुआ। संस्थागत निवेशकों ने इसमें सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया। उनका हिस्सा 19.34 गुना भरा, जबकि धनाढ्य निवेशकों का हिस्सा 7.33 गुना सब्सक्राइब हुआ। यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए नहीं था। 99-100 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर जारी इस इश्यू का अलॉटमेंट 18 मार्च को होगा। बीएसई और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 24 मार्च को संभावित है।

बिजनेस एंकर फोर्ड, जीएम, स्टेलांटिस भी ईवी योजनाएं टाल रहीं, होंडा को पहली बार घाटे का अंदेशा

होंडा ने अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की योजना रद्द की; ट्रम्प ईवी से सब्सिडी घटा रहे, जबकि पेट्रोल कारों को बढ़ावा दे रहे

© The New York Times
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

जैक इविंग | न्यूयॉर्क

होंडा ने अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार (ईवी) लॉन्च करने की योजना रद्द कर दी है। कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में ईवी की मांग धीमी पड़ने और नीतिगत बदलावों के कारण उसने यह फैसला किया है। कंपनी को 1957 में शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद पहली बार 2025-26 में 36,550 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटा होने का अंदेशा है। ईवी से जुड़ी रणनीति बदलने से भी कंपनी को 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है।

होंडा के मुताबिक, अमेरिका में ईवी मार्केट का विस्तार कई कारणों से धीमा पड़ा है। सरकार ने ईवी प्रोत्साहन कम कर दिए हैं और पेट्रोल-डीजल से जुड़े नियमों में ढील दी है। अमेरिकी प्रशासन ऑटो कंपनियों को बड़े पिकअप और एसयूवी बेचने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कंपनी को नई टैरिफ नीति के कारण पेट्रोल और हाइब्रिड कारों से मुनाफा घट रहा है। इससे कमाई पर दबाव बढ़ा है। इसी वजह से कंपनी ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अपनी ईवी प्लान टालने का फैसला किया है। होंडा के साथ फोर्ड, जनरल मोटर्स और स्टेलांटिस जैसी कंपनियां भी ईवी योजनाएं टाल रही हैं। इन्हें इनमें किए गए निवेश पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

हालांकि कुछ कंपनियों ने अब भी ईवी रणनीति जारी रखी है। टोयोटा, सुबारू, बीएमडब्ल्यू, फॉक्सवैगन और ह्युंडई नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर रही हैं। यूरोप और एशिया के कई देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अभ बी बढ़ रही है। कार खरीद से जुड़े प्लेटफॉर्म एडमंड्स के अनुसार हाल के युद्ध और पेट्रोल कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद कुछ खरीदार इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी विचार कर रहे हैं। इतिहास बताता है कि पेट्रोल पम्प पर कीमतें बढ़ने से लोग अगली कार के रूप में ईवी विकल्प पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं।

स्टार्टअप्स सस्ते, तेज चार्ज होने वाले मॉडल बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे

अमेरिकी स्टार्टअप्स रिवियन और ल्यूसिड कम कीमत वाले नए मॉडल ला रही हैं। ये कंपनियां 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले ईवी बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं। मौजूदा मॉडल 65 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में ग्राहक इन्हें खरीद नहीं पाते हैं। ल्यूसिड ने 'कॉसमॉस' नाम की कार पेश करने की योजना बनाई है। यह 14 मिनट में चार्ज होकर 322 किमी चलने में सक्षम होगी। कंपनी इस साल सऊदी अरब में उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अपनी ईवी प्लान टालने का फैसला किया है। होंडा के साथ फोर्ड, जनरल मोटर्स और स्टेलांटिस जैसी कंपनियां भी ईवी योजनाएं टाल रही हैं। इन्हें इनमें किए गए निवेश पर भारी नुकसान

भारत समेत 9 देशों के लैंडिंग स्टेशन कनेक्ट करने की योजना अटकी

युद्ध की आंच इंटरनेट पर; मेटा ने 45,000 किमी का 'अंडरसी' केबल प्रोजेक्ट रोका

भास्कर न्यूज | मुंबई

फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण फारस की खाड़ी में अपना प्रमुख अंडरसी केबल प्रोजेक्ट स्थगित कर दिया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने 2अफ्रीका नाम के दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन केबल सिस्टम के पर्शियन गल्फ सेगमेंट पर काम रोक दिया है। यह फैसला क्षेत्र में चल रहे अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारण लिया गया है। इससे फ्रेंच कंपनी अल्काटेल सबमरीन नेटवर्क्स (एएसएन) के लिए ऑपरेशंस असुरक्षित हो गए हैं।

नए रूट तलाशे जा रहे, धीमी हो सकती है नेट स्पीड

यह घटना ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के भू-राजनैतिक जोखिम उजागर करती है। असर भारत पर भी पड़ेगा। टेलीजियोग्रैफी के विश्लेषक एलन मॉल्डिन ने कहा, 'केबल शिप्स एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस वाले इलाकों में काम नहीं करेंगे, यह बहुत रिस्की है।' सबसी केबल कंसल्टेंट हस्नैन अली ने बताया कि वैकल्पिक रूट्स तलाशे जा रहे हैं। मसलन ओमान और सऊदी अरब से टेरेस्ट्रियल रूट्स, पर इससे इंटरनेट स्पीड धीमी हो सकती है।

2 अफ्रीका प्रोजेक्ट 45,000 किलोमीटर लंबा है। यह अफ्रीका के तटों को यूरोप और मिडिल ईस्ट से जोड़ता है। इसके पर्शियन गल्फ सेगमेंट को 'पर्ल्स' कहा जाता है। यह ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब के लैंडिंग स्टेशनों को कनेक्ट करने वाला है। केबल का अधिकांश हिस्सा समुद्र तल पर बिछाया जा चुका है, लेकिन सभी स्टेशनों का कनेक्शन बाकी था। इसे इस साल के अंत तक चालू करने की योजना थी। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट अटक गया है।

अमर उजाला

प्रवाह

7 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ शनिवार, 14 मार्च 2026

हमें युद्ध करना तो आता है, लेकिन यह नहीं पता कि शांति के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए। -जैक्स-यवेस कूस्टो

वैश्विक संघर्षों का दूसरा पहलू

पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच संघर्ष केवल रणनीतिक हानि तक ही सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसी विषाक्त विरासत रच रहा है, जिसकी चर्चा अक्सर युद्ध की धूल में दब जाती है। ब्रिटेन स्थित पर्यावरणीय शोध संस्था कॉन्फ्लिक्ट एंड एन्वॉयरन्मेंट ऑब्जर्वेटरी (सीईओबीएस) ने इस संघर्ष के शुरू होने के बाद से अब तक 300 से अधिक ऐसी घटनाओं की पहचान की है, जिनसे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि, ईरान की करीब 5,000 जगहों को निशाना बनाने के अमेरिकी दावे को देखते हुए सीईओबीएस का आंकड़ा नुकसान का महज एक छोटा-सा हिस्सा ही दर्शाता है। इन जोखिमों का स्पष्ट संकेत तब मिला, जब इस्राइल द्वारा ईरान के तेल भंडारों पर किए गए हमलों के बाद तेहरान की सड़कें काली बारिश से भीग गईं। गौरतलब है कि ईरान के दक्षिणी प्रांतों में तेल रिफाइनरियों पर हुए हमलों से हजारों टन कच्चा तेल समुद्र में रिस रहा है और समुद्री जीवन को खत्म कर रहा है। यही नहीं, विस्फोटों का विषैला धुआं आसपास के क्षेत्रों में श्वास संबंधी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ा रहा है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता कि तेल रिफाइनरियों पर हुए हमलों के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होंगे और लोगों के हवा, पानी और भोजन पर भी इसका असर पड़ेगा। शोध का यह बताना गंभीर है कि बमबारी से पैदा हुए जहरीले प्रदूषक वर्षों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं और आसपास के समुदायों में फैल भी सकते हैं। गोला-बारूद में जिस टीएनटी नामक विस्फोटक का उपयोग होता है, जिसे अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) तक ने संभावित कैंसरकारक माना है, युद्ध खत्म होने के बाद भी मिट्टी में बना रह सकता है। बात सिर्फ इसी युद्ध की नहीं है। एक अन्य ब्रिटिश अध्ययन बताता है कि इस्राइल-गाजा संघर्ष में भी अब तक तीन करोड़ टन से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि युद्ध और पर्यावरण के मसले पर अंतरराष्ट्रीय नियम कुछ नहीं कहते। जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल में

पर्यावरणीय क्षति को भी युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह दुखद है कि संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं की आवाज महाशक्तियों की राजनीति में दब गई है। जब मिसाइलें खामोश हो जाती हैं, तब भी पर्यावरण में छिपे घाव लंबे समय तक बने रहते हैं। यह युद्धों की अदृश्य कीमत होती है। यह विषाक्त चक्र हमें निगल ले, इससे पहले इसका टूटना जरूरी है।

युद्ध तय नहीं करते कि कौन सही है

विख्यात दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध यह तय नहीं करता कि कौन सही है, वह सिर्फ यह तय करता है कि कौन बचा है। ऐसे में, पूरी दुनिया को मिलकर सोचना होगा कि इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए।

कोविड से बची दुनिया मानो यह मान बैठी है कि युद्ध करना और बम गिराना ही किसी राष्ट्र की पहचान है। नहीं तो फेफड़ों को बचाती और वैक्सीन ढूंढती उन भयभीत धड़कनों के बारे में सोचिए, जिन्हें अगले पल का पता नहीं था, फिर भी सभी, इनको-उनको बचाने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जितनी यह दुनिया इनकी है, उतनी उनकी भी है। लेकिन पता नहीं फिर से मानो इस पृथ्वी को नजर लग गई। अब बस अकड़ देखिए, उन मुल्कों की, जहां सिर्फ और सिर्फ तेल के कुएं हथियाने और बम गिराने की प्रतियोगिता चल रही है।

नन्दितेश निलय

स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

नैतिकता का प्रश्न, उस शांति का भाव, किसी और ग्रह का मालूम हो रहा है। हम सब देख रहे हैं और यह भी मान रहे हैं कि दुनिया धीरे-धीरे तीसरे विश्वयुद्ध की ओर बढ़ रही है। ऐसे में, सबसे जरूरी सवाल यह होगा कि युद्ध से कैसे बचा जा सकता है और शांति के मूल्यों को दोहराने के लिए दुनिया को क्या करने की जरूरत है। कई संघर्ष चल रहे हैं, जैसे ड्रोन कंट्रोल्ड युद्ध या साइबर हमले, वगैरह। क्या पैसे और बम जैसी धमकियों के जरिये देशों पर दबाव डालना सही है? क्या सबसे ताकतवर देश के तौर पर आम लोगों को मारने वाले ड्रोन का इस्तेमाल 'कोलैटरल डैमेज' के तौर पर करना या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना नैतिक है? युद्ध को अपनी पहचान समझाने के लिए मूल्यों या नैतिकता की जरूरत नहीं होती। यह शांति के मूल्य ही हैं, जो युद्ध की दुनिया को चुनौती देते हैं। शांति सिर्फ एकजुटता और संवेदनशीलता से आती है। इसे वैश्विक स्तर पर बनाने और फैलाने के लिए लीडरशिप की हर तरह की सोच में नैतिकता की भावना की जरूरत होती है।

परमाणु बम या दूसरे तरह के परमाणु परीक्षण का जलवायु परिवर्तन पर क्या असर होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस्राइल और फलस्तीन में हजारों युवा, बच्चे, औरतें-मर्द मारे गए और रूस तथा यूक्रेन में भी यही नतीजे हुए। अब अमेरिका व ईरान के साथ-साथ पश्चिम एशिया में गोले बरसाता यह युद्ध

क्या उन बच्चों से माफी मांग पाएगा, जो मारे गए। जो बच गए या बचेंगे उनकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक दिक्कतों का क्या? आखिरकार, वे शांति के दूत कहां हैं? क्या महात्मा गांधी, विवेकानंद ने कभी सोचा होगा कि एक इन्सान का अहंकार या घमंड और जिद लाखों हजारों लोगों को मौत की तरफ खींच लेगा, खासकर युद्ध व अनगिनत मौतें मानो एक सामान्य बात बन जाएंगी? एक बार जब महात्मा गांधी से किसी पत्रकार ने यह पूछा कि अगर कोई हवाई जहाज से बम गिर जाए, तो वह क्या करेंगे? गांधी जी का जवाब था कि वह उस पायलट के बारे में सोचेंगे, जो बम गिराते वक्त कितना परेशान रहा होगा।

अगर आज विवेकानंद होते, तो वह कह जाते कि विश्व के नागरिकों के हित में महान अमेरिका वह होगा, जो युद्ध नहीं, शांति का नेतृत्व करेगा, जो आने वाली नस्लों को जीवन की क्षणभंगुरता नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और प्रयोजन का अर्थ समझाएगा और उन्हें भी अपने 'मैं' से मुक्त होना सिखाएगा। आज अगर स्वामी विवेकानंद होते, तो वह बहुत चिंतित होते और फिर वह प्रश्न भी पूछते कि आखिर किसी राष्ट्र की अस्मिता क्या होती है? नेतृत्व शक्ति का केंद्र होता है या महान नैतिक मूल्यों का? किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा क्या है? ऐसी दुनिया में एक नागरिक का सम्मान क्या होता है, जहां इन्सानी रिश्ते व्यापारिक फायदों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जहां किसी देश की महानता को आसानी से तात्कालिक स्वार्थों से बदल दिया जाता है, जहां संस्थाएं कंकड़-पत्थरों को तो चमकाती हैं, लेकिन वे चुपचाप हीरों की चमक फीकी कर देती हैं, जहां देशों के रिश्ते रोज नए दुश्मनों के नाम पर बदल रहे हैं... जहां व्यापार के नाम पर, तेल के भंडार के नाम पर, टैरिफ के नाम पर, और आगे ड्रोन, मिसाइलों, लड़ाकू विमानों के नाम पर, तानाशाही के नाम पर, आतंकवाद, डर और हिंसा के नाम पर; दो राष्ट्रों के रिश्ते परिभाषित हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से, ईरान से, सभी से पूछते, और फिर पूरी दुनिया से पूछते। उन तमाम नेतृत्व से पूछते, जिन के लिए जनता एक ग्राहक है और देश बाजार। उस हर युवा से पूछते, जो देश और समाज से ज्यादा अपनी धुन में डूबा है? अपने ज्ञान और शख्सियत से जिस विवेकानंद ने अमेरिका को मनुष्यता, राष्ट्रवाद, अध्यात्म और जीवन का उद्देश्य सिखाया, उसके लिए अमेरिका और यहां तक कि दुनिया की लीडरशिप को भी स्वामी विवेकानंद को फिर से फॉलो करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसके लिए कोई टैरिफ नहीं लगेगा और इसमें कोई आर्थिक हित या व्यापार भी शामिल नहीं होगा।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता काफी हद तक नेताओं की नैतिक सोच और मूल्यों पर भी निर्भर करती है। क्या संसार के नेतृत्वकर्ता, युद्ध से पहले और उसके दौरान इन्सानियत का भविष्य शांति के नजरिये से देखना चाहते हैं? क्या गांधी, लिंकन या विवेकानंद ने कभी सोचा होगा कि हिटलर के बाद फिर कोई घृणा की हवा ऐसी चलेगी, जो तमाम नेतृत्व के घमंड और जिद की खातिर लाखों लोगों को कब्र की ओर खींच सकती है। और फिर शांति के लिए यूएनओ की क्या भूमिका है? पिछले दशक से वह ज्यादातर समय चुप या निष्क्रिय क्यों रहना पसंद कर रहा है? क्या संसार के लीडर्स कंसोर्टियम ऑफ पीस नहीं बना सकते? आखिर दुनिया अगर बम से ही संचालित होनी है, तो फिर उन तेल के कुओं का क्या होगा? आखिर जीने के लिए तो हवा, पानी और मूल्यों से लैस दुनिया चाहिए। क्या शांति के मूल्य को लेकर चलने वाला अब कोई नेतृत्व नहीं आएगा क्या? क्या यह दुनिया सिर्फ बम और बाजार से ही संचालित होगी? हमें सोचना होगा कि इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए?

एक तरफ एआई, दूसरी तरफ युद्ध में बरसते ड्रोन, आखिर मनुष्य जाए तो कहां जाए? गांधी जी तो दंगों के समय नोआखाली पहुंच गए थे। आखिर हम कहां पहुंचें। फिर से अहिंसा की आवाज उठेगी क्या? क्या कलिंग युद्ध से कोई महान अशोक बनकर लौटेगा, क्या? वे बच्चे जो बड़े भी न हो सके, वे जरूर पूछेंगे कि आखिरकार तेल के कुएं, जलियांवाला बाग का कुआं और वह ठाकुर का कुआं इतना गहरा और निर्मम क्यों रहा कि कभी इन सबका मन मनुष्यता के लिए नहीं पसीजा। उन धमाकों के बाद, जो शहर या गांव बचेंगे, उनको कौन संभालेगा? अंत में बर्ट्रेंड रसेल हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध यह तय नहीं करता कि कौन सही है, वह सिर्फ यह तय करता है कि कौन बचा है! इसलिए समय आ गया है कि इस दुनिया को अहिंसा के नायकों का नेतृत्व मिले और शांति के इतिहास को आवाज भी दी जाए। यह इन्सानियत की ओर वापसी होगी, उस आध्यात्मिक पुकार के साथ जो इस बार 'सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ वर्ल्ड' होगा।

edit@amarujala.com

रक्षा

आधुनिक युद्ध और भविष्य का खाका

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की शैली को देखते हुए, भारत को युद्ध खत्म होने का इंतजार किए बिना भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी सैन्य रणनीति बनानी चाहिए।

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इस्राइल-ईरान के बीच चल रहा त्रिकोणीय संघर्ष किस करवट बैठेगा, इसका अनुमान लगाना बेहद कठिन है। फिर भी, तेजी से बदलती दुनिया और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की शैली को देखते हुए, भारत को युद्ध खत्म होने का इंतजार किए बिना अपनी रणनीति व सैन्य व्यवस्था पर विचार करते रहना चाहिए। इस दूरदृष्टि की महत्ता को ध्यान में रखकर ही अभी दो दिन पहले ही भारत सरकार ने रक्षा बल विजन-2047 का दस्तावेज जारी किया है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता इस परिकल्पना के महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल है। नए भारत की रक्षा नीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां पारंपरिक सैन्य शक्ति और नई तकनीकों के बीच तालमेल बनाना जरूरी हो गया है। ऐसे में, भविष्य की सैन्य रणनीति का संतुलन आज की अपरिहार्य जरूरत है। ईरान-अमेरिका युद्ध में अमेरिका द्वारा ईरान के रणपोत को डुबाने के लिए पनडुब्बी से टॉरपीडो का इस्तेमाल किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यह पहला ऐसा कदम है, जो दिखाता है कि अमेरिका अपने बेहद महंगे व प्रसिद्ध एफ-35 जैसे लड़ाकू विमान के इस्तेमाल में कंजूसी दिखा रहा है। वहीं, ईरान हवाई हमलों के लिए पूरी तरह ड्रोन व मिसाइलों पर निर्भर है, जो अपेक्षाकृत बहुत सस्ते हैं।

अरुणेन्द्र नाथ वर्मा

फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से भारत की वायु शक्ति को मजबूती मिली है। यह विमान अपनी बहुउद्देश्यीय क्षमता, आधुनिक तकनीक और तेज मारक शक्ति के कारण आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि भारत में राफेल के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन से संबंधित दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी स्थापित होती है, तो उससे भारतीय रक्षा उद्योग को भी लाभ मिल सकता है। आधुनिक युद्ध का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भी लड़ा जाता है, जिसमें रडार प्रणाली को भ्रमित करना, संचार नेटवर्क को बाधित करना, डाटा लिंक को जाम करना और उपग्रह आधारित प्रणालियों को प्रभावित करना शामिल है। इसलिए, बड़ी सैन्य शक्तियां इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली पर तेजी से निवेश कर रही हैं। इसके अलावा, पहले ड्रोन का उपयोग मुख्यतः निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता था, पर अब वे आक्रामक भूमिका में दिखाई देने लगे हैं। कम संसाधनों में भी ड्रोन तकनीक से सैन्य ताकत बढ़ाई जा रही है, जिससे साफ है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ महंगे हथियारों पर निर्भर नहीं रहेंगे। भविष्य में मानव चालित विमान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां और स्वायत्त ड्रोन एक संयुक्त तंत्र के रूप में काम करेंगे। भारत के सामने इसलिए दोहरी चुनौती है। एक ओर उसे अपनी तात्कालिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है, तो दूसरी ओर स्वदेशी अनुसंधान और उत्पादन क्षमता को भी विकसित करना है। यदि भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक तकनीकी प्रवृत्तियों को समझते हुए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ड्रोन तकनीक और एआई आधारित सैन्य प्रणालियों के विकास में निवेश करता है, तो आने वाले वर्षों में वह वैश्विक रक्षा आपूर्ति शृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। इस दिशा में फिलीपींस और इंडोनेशिया को भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात बहुत उत्साहवर्धक संकेत है।

संभव है कि भविष्य में युद्ध का स्वरूप आज की तुलना में बिल्कुल अलग होगा। भारत तेजस मार्क-2, सुखोई-57 और एफ-35 जैसे विमानों को खरीदने पर भी विचार कर रहा है। पर पश्चिम एशिया का युद्ध दिखा रहा है कि आने वाले समय में लड़ाकू विमानों के साथ सस्ते ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक हमले और एआई आधारित तकनीक भी युद्ध की दिशा तय करेगी। इसलिए, भारत को सिर्फ वर्तमान ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया के युद्ध से सीख लेकर भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए।

डाटा एआई का ईंधन है। जैसे किसी इंजन की गुणवत्ता उसमें डाले गए ईंधन से तय होती है, वैसे ही एआई का प्रदर्शन भी डाटा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

-स्टीफन डी कार्वर

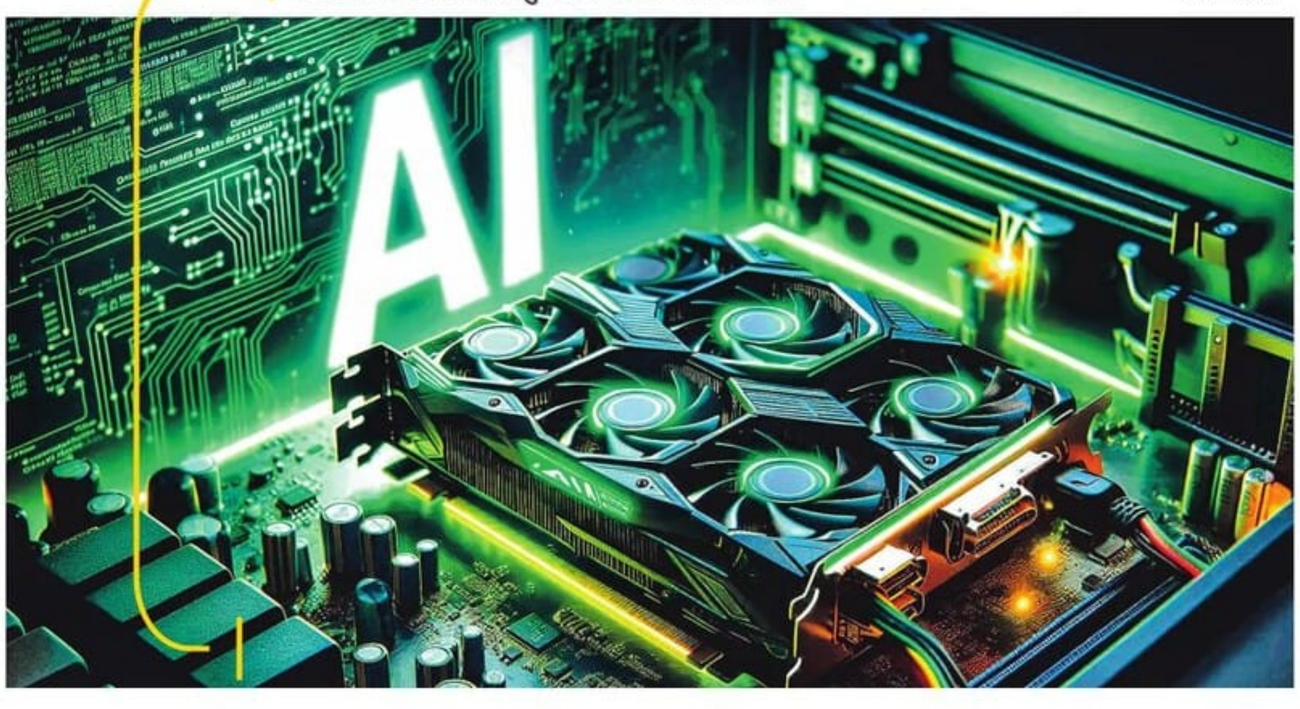

जहां हो तकनीक और नैतिकता का मेल

विज्ञान की असली जीत मशीनों के निर्माण में नहीं, बल्कि जिज्ञासा को जीवित रखने में है। हमें एक ऐसे भविष्य का सपना देखना चाहिए, जहां तकनीक व नैतिकता का मेल हो, और जहां मनुष्य केवल एक ग्रह का निवासी न होकर पूरे ब्रह्मांड का खोजी हो।

मानव इतिहास एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पृथ्वी का इतिहास प्राकृतिक आपदाओं और विलुप्ति की घटनाओं से भरा रहा है, और ऐसे में तकनीक ही वह एकमात्र 'बीमा पॉलिसी' है, जो मानवता को एक 'बहु-ग्रहीय प्रजाति' बना सकती है। तकनीक हमारी प्रजाति के अस्तित्व की रक्षा का कवच है। भविष्य की तकनीक हमें सौरमंडल की सीमाओं के पार ले जाने की क्षमता रखती है। हालांकि, तकनीक का असली चमत्कार तब होगा, जब हम केवल मशीनों को नहीं, बल्कि 'मानवीय चेतना' को लेजर के जरिये तारों तक भेज सकेंगे। यह 'डिजिटल अमरता' का विचार है, जहां हमारे मस्तिष्क का डाटा प्रकाश की गति से ब्रह्मांड के सुदूर कोनों में यात्रा कर सकेगा।

मिचियो काकू

हमें एक ऐसी तकनीक का समर्थन करना चाहिए, जो मंगल या चंद्रमा जैसे कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव शरीर को 'डिजाइन' कर सके, क्योंकि तकनीक प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नियमों को गहराई से समझकर उनके साथ तालमेल बिठाने का एक परिष्कृत तरीका है। अगर ऐसा हुआ, तो भविष्य में रोबोट और इन्सान मिलकर आकाशगंगा का अन्वेषण करेंगे।

वर्तमान में हम 'टाइप जीरो' सभ्यता हैं, जो अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। तकनीक का सही उपयोग हमें 'टाइप आई' सभ्यता की ओर ले जाएगा, जहां हम ग्रह की पूरी ऊर्जा (जैसे भूकंप, तूफान और ज्वालामुखी) को नियंत्रित कर सकेंगे। हमारे पास वह तकनीकी क्षमता है कि हम विनाशकारी हथियारों के बजाय इस ऊर्जा का उपयोग मानवता के उत्थान के लिए कर सकें। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने जंगलों से निकलकर पूरी दुनिया को अपना घर बनाया, उसी तरह तकनीक हमें पृथ्वी के पालने से निकालकर सितारों के बीच ले जा सकती है। इसीलिए, विज्ञान की असली जीत बड़ी मशीनों के निर्माण में नहीं, बल्कि मानवता की असीम जिज्ञासा को जीवित रखने में है।

जीवन धारा

हमें एक ऐसे भविष्य का सपना देखना चाहिए, जहां तकनीक और नैतिकता का मेल हो, और जहां मनुष्य केवल एक ग्रह का निवासी न होकर पूरे ब्रह्मांड का खोजी हो।

एआई पर असली नियंत्रण किसका

चुनौती एआई के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग की है, पर उससे बड़ी समस्या यह है कि इसके लिए किसी के पास कोई योजना नहीं है।

रॉस डॉट

द न्यूयॉर्क टाइम्स

मान लीजिए, यदि आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़ी किसी भयानक तबाही में मरना ही पड़े, तो क्या आपको यह सोचकर ज्यादा बुरा लगेगा कि विनाश की राह उन तकनीकी दिग्गजों के घमंड ने आसान बनाई, जो सिलिकॉन वैली में बैठकर आदर्शलोक और अमरता के सपने देख रहे थे, या पेंटागन के अधिकारियों की मूर्खता ने, जो रूस व चीन से आगे निकलने की होड़ में एआई को आजादी और ताकत की खुराक देते हैं?

शीतयुद्ध के दौर में अमेरिका की चिंता सैन्य गलतियों को लेकर रहती थी। उस समय भी एआई को लेकर लोगों में डर और शंकाएं थीं-फिल्म *डॉ. स्ट्रेंजलव* में 'डूम्सडे मशीन', *वॉरगेम्स* में खेल खेलने वाला कंप्यूटर और *टर्मिनेटर* में स्काईनेट को चालू करने का खतरनाक फैसला इसके उदाहरण हैं। पर पिछले कुछ वर्षों में जैसे-जैसे एआई की प्रगति हुई है, कुछ चुनिंदा कंपनियों और उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के हाथों में बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, जो साइंस-फिक्शन सपनों और दुनिया के खत्म होने की डरावनी संस्कृति में डूबे हुए हैं। राष्ट्रपतियों और सेनाध्यक्षों के बजाय एआई दिग्गजों की ताकत और महत्वाकांक्षा के बारे में चिंता करना अब आम बात हो गई है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग और अग्रणी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बीच टकराव ने इस बहस को और तेज कर दिया है।

सवाल यह है कि क्या एंथ्रोपिक के एआई मॉडल कंपनी के नैतिक दायरों में ही काम करेंगे, या फिर उन्हें पेंटागन की जरूरतों के अनुसार किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

एंथ्रोपिक के मौजूदा समझौते में दो तरह के उपयोगों पर साफ रोक है। पहला, बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए एआई का इस्तेमाल। दूसरा, पूरी तरह स्वायत्त हथियारों के रूप में एआई का उपयोग, जहां अंतिम निर्णय प्रक्रिया में किसी इन्सान की भूमिका न हो। इसलिए, पेंटागन की मांगें कुछ लोगों को उन काल्पनिक कहानियों की याद दिलाती हैं, जिनमें मशीनें खुद फैसले लेने लगती हैं। हालांकि, पेंटागन का कहना है कि उसका उद्देश्य हत्यारे रोबोट बनाना नहीं है। उसकी चिंता यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पर किसी निजी कंपनी का नैतिक वीटो नहीं होना चाहिए, भले ही वे कितने ही उचित क्यों न लगें। सरकार का तर्क है कि ऐसे फैसले चुनी हुई राजनीतिक व्यवस्था और उसके अधिकारियों को लेने चाहिए, न कि किसी कंपनी को। उदाहरण के तौर पर, पेंटागन ने यह आशंका जताई है कि अगर अमेरिका पर किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हो जाए और एआई कंपनी यह कहकर मदद से इन्कार कर दे कि यह उसकी नैतिक नीतियों के खिलाफ है, तो इससे गंभीर संकट पैदा हो सकता है।

फिर भी, यदि यह चिंता कुछ हद तक जायज भी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सरकार को एंथ्रोपिक के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए। कंपनी को 'सप्लाई चेन रिस्क' घोषित करने जैसी कार्रवाई से उसका संबंध उन तमाम कंपनियों से भी टूट सकता है, जो अमेरिकी सरकार के साथ काम करती हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी सरकार दुनिया की सबसे आक्रामक एआई नियामक बन सकती है। इसी वजह से एआई उद्योग के कई लोगों का मानना है कि कंपनियों को एंथ्रोपिक के साथ खड़ा होना चाहिए। खासकर वे लोग, जो इस बात से डरते हैं कि सैन्य नियंत्रण एआई के विकास को खतरनाक दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकता है। हालांकि, एंथ्रोपिक के प्रमुख डारियो अमोदेई जैसे लोग एआई के संभावित खतरों को लेकर काफी सतर्क दिखाई देते हैं। वे सैन्य या अनियंत्रित एआई से पैदा होने वाले जोखिमों को समझते हैं। पर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि लंबी अवधि में पेंटागन के अधिकारी एआई पर नियंत्रण के मामले में कुछ फायदे दे सकते हैं। पहला, उनका ध्यान सामान्यतः व्यावहारिक रणनीतिक लक्ष्यों पर होता है, न कि मशीनों के देवता बनने जैसे विचारों पर। दूसरा, वे नौकरशाही व्यवस्था और आदेशों की शृंखला से बंधे होते हैं, जिससे वे जोखिम उठाने से बचते हैं। तीसरा, वे अंततः जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर एआई वास्तव में उतनी बड़ी शक्ति बन जाती है, जितना तकनीकी विशेषज्ञ मानते हैं, तो यह कल्पना करना कठिन है कि इतनी महत्वपूर्ण तकनीक सिर्फ निजी कंपनियों के हाथों में ही रहे और सरकार उससे दूर रहे।

आने वाले समय में यह सवाल लगातार उठेगा कि एआई पर अंतिम नियंत्रण किसका होना चाहिए? दरअसल, वर्तमान टकराव इसी मूल राजनीतिक प्रश्न को सामने ला रहा है। पर केवल नियंत्रण की इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती। असली चुनौती यह है कि इस तकनीक को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से कैसे संचालित किया जाए। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए कोई ठोस और दूरदर्शी योजना है या नहीं।

सोरा 2

यह एक उन्नत एआई-आधारित टेक्स्ट-टू-वीडियो मॉडल है, जिसे ओपनएआई ने विकसित किया है। इसमें टेक्स्ट विवरण (प्रॉम्प्ट) या चित्रों के आधार पर यथार्थवादी वीडियो तैयार करने की क्षमता है। यह मॉडल भौतिकी के नियमों-जैसे प्रकाश, गति और वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया, आदि को ध्यान में रखते हुए दृश्य उत्पन्न करने का प्रयास करता है। जहां अन्य टूल्स तीन से 10 सेकंड के वीडियो बनाते हैं, वहीं सोरा 60 सेकंड तक के वीडियो बनाने में सक्षम है। यह एक ही वीडियो में विभिन्न कैमरा एंगल्स बना सकता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है, जैसे वीडियो को बेहतरीन अंदाज में पेशेवर रूप से शूट और एडिट किया गया हो।

एजुकेशन & कॅरिअर

शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है, बातें करना बंद करके काम शुरू करना।

अमर उजाला **Job Alert**

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

जूनियर ओवरमैन टी एंड एस ग्रेड-सी आदि पद खाली

667 पद

अंतिम तिथि : 06 अप्रैल, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष
यहां आवेदन करें : mahanadicoal.in

केएसएसएससीआई में निकली भर्ती ■ 122 पद

वरिष्ठ फार्मासिस्ट, तकनीशियन आदि के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि
31 मार्च, 2026
पात्रताएं
बीएससी, डिप्लोमा व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें
cancerinstitute.edu.in

एनएचपीसी लिमिटेड में संभावनाएं ■ 72 पद

ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि
06 अप्रैल, 2026
योग्यताएं
बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
nhpcindia.com

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ■ 291 पद

टेक्नीशियन, ड्रेसर व अन्य पदों पर करें आवेदन
अंतिम तिथि : 27 मार्च, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 व 45 वर्ष
यहां आवेदन करें : esb.mp.gov.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ■ 40 पद

सहायक पर्यावरण अभियंता आदि पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि
28 मार्च, 2026
पात्रताएं
ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें
uppcb.up.gov.in

सीयूएसबी ने जारी किया विज्ञापन ■ 35 पद

प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
30 मार्च, 2026
वेतनमान
रुपये 57,700 से लेकर रुपये 2,18,200 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें
cusb.ac.in

यहां भी रोजगार के अवसर...

- भारतीय नौसेना अग्निवीर, एसएसआर : अग्निवीर का पद रिक्त।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 06 अप्रैल, 2026
- joinindiannavy.gov.in
- एनएलसी इंडिया लिमिटेड : एयरपोर्ट डायरेक्टर का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 09 अप्रैल, 2026
- www.nlcindia.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

ताकि संवाद कायम रहे

ऑफिस की मीटिंग में चाहे छोटी हो या बड़ी पूरे मनोयोग से शामिल हों, क्योंकि बातचीत से ही नए विचारों का रास्ता खुलता है

एलिजाबेथ त्रिन्ह
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

अक्सर आप कार्यस्थल पर दिनभर कई मीटिंग्स में शामिल होते हैं, जैसे व्यक्तिगत मीटिंग, विभागीय अपडेट आदि। आपके पास समय सीमित होता है, इसलिए आप हर मीटिंग पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में आपकी सोच यही होती है कि क्या मीटिंग का यह विषय इतना महत्वपूर्ण या रोचक है कि मुझे इस पर पूरी गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए? असल में यह एक तरह का मानसिक शॉर्टकट है। यानी आप पहले से ही यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन-सी बातचीत आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यहां समस्या यह है कि शुरुआत में किसी विषय को कम रोचक समझने की वजह से आप नए विचारों से चूक सकते हैं। इसलिए केवल रोचक या बड़ी मीटिंग्स पर ध्यान देने के बजाय, सामान्य मीटिंग्स को भी गंभीरता से लेना जरूरी है।

Harvard Business Review

■ थोड़ा समय दें

अक्सर लोग पहले से ही यह तय कर लेते हैं कि उन्हें किस विषय या बातचीत पर ध्यान देना चाहिए और किस पर नहीं। इसके लिए वे जल्दी फैसला लेने वाले मानसिक शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार जो चर्चा शुरुआत में साधारण या कम रोचक लगती है, वही बातचीत शुरू होने के बाद ज्यादा प्रभावी और उपयोगी बन जाती है। इसलिए किसी विषय को पहले से नजरअंदाज करने के बजाय उसे थोड़ा समय देना बेहतर होता है।

■ मीटिंग्स में रुचि दिखाएं

जब आप किसी बैठक में पूर्ण गंभीरता और मनोयोग के साथ शामिल नहीं होते, जैसे बीच-बीच में दूसरे काम करना या जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करना, तो बातचीत गहराई तक नहीं जा पाती। लेकिन जब आप सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल होते हैं, सवाल पूछते हैं और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो साधारण-सा लगने वाला विषय भी महत्वपूर्ण और उपयोगी चर्चा में बदल सकता है। इससे नए विचार सामने आते हैं और टीम के साथ बेहतर समझ भी बनती है।

■ अपनी सक्रियता दिखाएं

यदि नियमित बैठकों या अपडेट के समय आप अनिच्छुक नजर आते हैं, तो आपके सहकर्मी भी खुलकर अपनी बात

साझा करने से हिचकने लगते हैं। ऐसी स्थिति में संगठन के अंदर एक दूरी पनपने लगती है। जब तक आपको इन समस्याओं की जानकारी मिलती है, तब तक वे काफी गंभीर रूप धारण कर चुकी होती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप नियमित अपडेट के दौरान भी सक्रियता दिखाएं, ताकि कर्मचारी खुलकर जानकारी साझा कर सकें।

■ बातचीत को बढ़ावा दें

रोजमर्रा के विषयों पर खुलकर बातचीत होने से काम में सुगमता और वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे में कर्मचारी भविष्य की चिंताओं या नए विचारों को साझा करने में खुलकर भाग लेते हैं। इसके अलावा, यह धारणा कि नियमित बैठकें काम करने की दक्षता को कम करती हैं, सही नहीं है। वास्तव में, सार्थक और खुला संवाद मानसिक संसाधनों की पुनः पूर्ति करने में मदद करता है, जिससे कर्मचारी अधिक उत्पादक और दृढ़ बनते हैं।

इंटर्नशिप स्कीम

आईआईटी, धनबाद का इंटर्नशिप प्रोग्राम

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईआईटी) धनबाद की ओर से अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से समर रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। बीटेक के छात्रों को कैटेगरी-I व पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को कैटेगरी-II में आवेदन करने हैं तथा लॉन्ग टर्म रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम में बीटेक, एमटेक, एमएससी व एमबीए के छात्र कैटेगरी-III के तहत आवेदन करेंगे। कैटेगरी-I व II की इंटर्नशिप स्कीम की अधिकतम अवधि दो माह और कैटेगरी-III की एक साल निर्धारित की गई है। कैटेगरी-I व II के प्रत्येक इंटर्न को प्रतिमाह 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। कैटेगरी-I व II में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2026 व कैटेगरी-III में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है। आधिकारिक लिंक tinyurl.com/sn8au3jn पर जाकर ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन आमंत्रित

स्पोर्ट्स फोटोग्राफी ग्रांट्स-2026

स्पोर्ट्स फोटोग्राफी ग्रांट्स के लिए फोटोग्राफरों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य उभरते फोटोग्राफरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसमें आवेदन करने के लिए आवश्यक है कि आवेदक ने अपने फोटोग्राफी कॅरिअर में तीन वर्ष से कम काम किया हो। चयनित सात फोटोग्राफरों को कॅरिअर में आगे बढ़ने के लिए 5,000 डॉलर का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, उन्हें 2026 डीपीपीएफ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन सात अनुदान प्राप्तकर्ताओं में से अधिकतम तीन को डीपीपीएफ सलाहकार बोर्ड में अग्रणी उद्योग पेशेवरों के साथ एक वर्ष तक चलने वाले मार्गदर्शन के लिए चुना जाएगा और विकास अनुदान के रूप में अधिकतम तीन अतिरिक्त आवेदकों का चयन किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को 2,500 डॉलर का अनुदान और 2026 डीपीपीएफ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी सम्मेलन में भाग लेने के लिए व्यय सहित यात्रा प्रदान की जाएगी। आवेदक आधिकारिक लिंक tinyurl.com/33t7ywxy पर जाकर 01 मई, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट — आगामी परीक्षाएं

सीबीएसई जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर टियर- II परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 19 मार्च, 2026
- इस परीक्षा में जनरल नॉलेज और करंट अफेअर्स, रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास व पॉपुलर हिंदी और इंग्लिश नॉवेल आदि से 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के व 30 प्रश्न वर्णात्मक प्रकार के पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें**
  cbse.gov.in

सीबीएसई सुपरिटेंडेंट टियर- II परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 19 मार्च, 2026
- इस परीक्षा में करंट अफेअर्स, भारतीय इतिहास व संस्कृति, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आदि से 150 अंकों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न व 150 अंकों के लिए वर्णात्मक प्रकार के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें**
  cbse.gov.in

खुद को परखें

1. शेषनाग-150 को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है?
   (a) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
   (b) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
   (c) न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज
   (d) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2. हाल ही में खबरों में चर्चित सिंहगढ़ किला किस राज्य में स्थित है?
   (a) महाराष्ट्र (b) कर्नाटक
   (c) केरल (d) तमिलनाडु
3. डार्ट (डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट) मिशन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था?
   (a) राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष
   (b) चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन
   (c) यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी
   (d) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

उत्तर : 1.c, 2.a, 3.a

सामान्य ज्ञान

बग बाउंटी प्रोग्राम

■ क्या है

बग बाउंटी प्रोग्राम एक साइबर सुरक्षा पहल है, जिसमें संगठन एथिकल हैकर्स और सुरक्षा शोधकर्ताओं को डिजिटल सिस्टम में कमजोरियों की पहचान करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

■ चर्चा में क्यों

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार इकोसिस्टम की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपना पहला संरचित बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है।

■ उद्देश्य

इसका उद्देश्य सुरक्षा संबंधी कमजोरियों की पहचान करके डिजिटल प्लेटफार्मों की सुरक्षा को मजबूत करना, सुरक्षा खामियों के बारे में जिम्मेदारीपूर्वक जानकारी देने को बढ़ावा देना और आधार प्रणाली जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे में विश्वास बढ़ाना है।

■ परीक्षण का दायरा

इसमें शोधकर्ता यूआईडीएआई की प्रमुख डिजिटल संपत्तियों का परीक्षण करेंगे, जिनमें यूआईडीएआई वेबसाइट, माई आधार पोर्टल और सुरक्षित क्यूआर कोड एप्लिकेशन शामिल हैं।

पहचान

शख्स : पीटर ब्रायन हेगसेथ

■ **चर्चा :** ईरान संघर्ष और पेंटागन मीडिया विवादों के कारण सुर्खियों में।
क्यों : ट्रंप के खासमखास और अमेरिका के दूसरे सबसे युवा रक्षा मंत्री।

पेंटागन का प्रहरी

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को अपना आदर्श मानते हैं। लिखने का शौक ऐसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट-सेलिंग लेखक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भरोसेमंद हैं। अमेरिका-ईरान संघर्ष को इस मुकाम तक ले जाने में बड़ी भूमिका रहे हैं और दुनिया इन्हें अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के नाम से जानती है।

दिन मंगलवार और तारीख थी 11 सितंबर, 2001। अमेरिका के प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय के छात्रावास के एक कमरे में एक युवा छात्र अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक टीवी पर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भयावह आतंकी हमले की खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। इस घटना के पहले तक उस छात्र के लिए सेना में जाने का विचार एक सपना भर था, पर जैसे ही उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों से उठते धुएं के गुबार को देखा, उसके अंदर एक आग भड़क उठी। उसने कुछ ही महीनों पहले विश्वविद्यालय के रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स (आरओटीसी) कार्यक्रम में दाखिला लिया था। अतः अन्य युवा सैनिकों की तरह उसने भी देश की सेवा का रास्ता चुना और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सेना में शामिल हो गया। फिर इराक और अफगानिस्तान जैसे कठिन व जोखिम भरे युद्धक्षेत्रों में उसने अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता तथा प्रतिबद्धता के साथ अपनी बटालियन का नेतृत्व किया। समय के साथ वह न केवल एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता बना, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे विश्वसनीय सिपहसालारों में भी शामिल हो गया। दुनिया उस व्यक्ति को दूसरे सबसे युवा अमेरिकी रक्षा मंत्री के रूप में जानती है, जो फिलवक्त अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अपनी भूमिका और पेंटागन में मीडिया की पहुंच से जुड़े विवादों के कारण सुर्खियों में हैं।

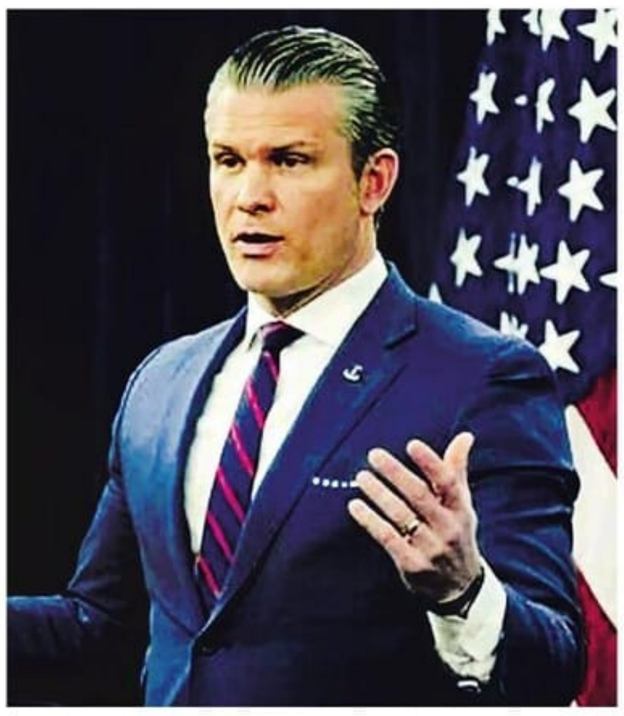

बेस्टसेलर लेखक भी हैं

पीट ने *द वॉर ऑन वॉरियर्स, बैटल फॉर द अमेरिकन माइंड: अपरूटिंग ए सेंचुरी ऑफ मिसएजुकेशन, द केस अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, ए ग्रेट रिपब्लिक और एंड हाउ वन स्पीच कैन रिइग्नाइट अमेरिका* जैसी कई चर्चित किताबें लिखी हैं। पीट *अमेरिकन क्रूसेड, मॉडर्न वॉरियर्स: रियल स्टोरीज फ्रॉम रियल हीरोज और इन द एरिना* के न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट-सेलिंग लेखक भी हैं। 2021 में, हेगसेथ को उनके हाथ पर बने ड्यूस वल्ट (ईश्वर की इच्छा) के टैटू की वजह से ड्यूटी पर तैनात होने से रोक दिया गया था। इसके चलते उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी बेस्टसेलर किताब *द वॉर ऑन वॉरियर्स* लिखी।

बास्केटबाल कोच के पुत्र

पीट हेगसेथ का पूरा नाम पीटर ब्रायन हेगसेथ है। उनका जन्म छह जून, 1980 को अमेरिका के मिनियापोलिस, मिनेसोटा में हुआ था। उनके पिता ब्रायन हेगसेथ बास्केटबाल कोच थे और मां पेनलोप (पेनी) हेगसेथ एक व्यवसाय कोच और नेतृत्व प्रशिक्षक रही हैं। उनका पालन-पोषण मिनेसोटा के फॉरेस्ट लेक क्षेत्र में हुआ और उन्होंने वहीं के एक हाईस्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से 2003 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान वह रूढ़िवादी छात्र पत्रिका *द प्रिंसटन टोरी* के संपादक व प्रकाशक रहे। बाद में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री भी हासिल की। उन्हें ब्रॉन्ज स्टार और कॉम्बैट इन्फैंट्रीमेन बैज जैसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान भी मिले। उन्होंने *वेट्स फॉर फ्रीडम और कंसर्न्ड वेटरन्स फॉर अमेरिका* जैसे संगठनों का नेतृत्व किया और बाद में अमेरिकी मीडिया में सक्रिय होकर फॉक्स न्यूज में प्रमुख टिप्पणीकार तथा फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड कार्यक्रम के सह-संचालक बने। वर्ष 2025 में वे अमेरिका के 29वें रक्षा मंत्री बने।

किताबें और कॉफी

पीट हेगसेथ का पसंदीदा खेल बास्केटबाल है। उन्हें लेखन, सार्वजनिक भाषण और नए स्थानों की यात्रा करना बेहद पसंद है। वह अक्सर इतिहास, राजनीति और सैन्य विषयों से जुड़ी किताबें पढ़ते हैं और इनसे जुड़े मुद्दों पर अपने विचार भी लिखते हैं। उन्हें अपने खाली वक्त में परिवार के साथ समय बिताना और खेल प्रतियोगिताएं देखना पसंद है। पीट हेगसेथ कॉफी पीने के शौकीन हैं। इसके अलावा, वह पौष्टिक व सादा भोजन करते हैं। मछली पकड़ना (फिशिंग) उनका एक और खास शौक है। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को अपना मार्गदर्शक मानते हैं।

तीन शादियां, सात बच्चे

हेगसेथ ने तीन शादियां की हैं। उनकी वर्तमान जीवनसंगिनी जेनिफर राउचर एक अमेरिकी टेलीविजन प्रोड्यूसर रही हैं। उनकी पहली पत्नी मेरेडिथ श्वार्ज थीं। 2009 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने 2010 में समंथा डीरिंग से विवाह किया, जो 2017 तक ही चल सका। पीट हेगसेथ कुल सात बच्चों के पिता हैं। उनकी दूसरी पत्नी समांथा डीरिंग से उनके तीन बेटे गनर हेगसेथ, बूने हेगसेथ और रेक्स हेगसेथ हैं। वर्तमान पत्नी से उनकी एक बेटी ग्वेन्डोलिन हेगसेथ है। इसके अलावा, उन्होंने जेनिफर राउचेट के पहले के तीन बच्चों को भी अपनाया है।

विवाद भी रहे

हेगसेथ ने अपने विभाग का नाम बदलकर फिर वही कर दिया है, जो 1789 से 1947 के बीच प्रचलित था। सितंबर 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग को आधिकारिक रूप से फिर युद्ध विभाग और उसके प्रमुख को युद्ध सचिव कहा जाने लगा। इस कदम के जरिये हेगसेथ सेना में 'योद्धा संस्कृति', यानी बहादुरी और लड़ने के जज्बे को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि, हाल के दिनों में वह विवादों में भी रहे। पेंटागन ने कुछ बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थानों के फोटोग्राफरों को प्रेस ब्रीफिंग से बाहर कर दिया, क्योंकि हेगसेथ के स्टाफ को हेगसेथ की प्रकाशित तस्वीरें पसंद नहीं आई थीं। साथ ही, विपक्षी नेताओं ने उन पर टैक्सदाताओं के पैसे की बर्बादी का आरोप भी लगाया।

आज का दिन

14 मार्च, 1931

भारत की पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन अर्देशिर ईरानी ने किया था। इसे दर्शकों ने इतना पसंद किया था कि यह फिल्म रिलीज के 8 सप्ताह बाद तक हाउसफुल रही थी।

- **1794 :** एली व्हिटनी को कपास साफ करने की मशीन (कॉटन जिन) के लिए पेटेंट मिला था।
- **1879 :** अलबर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था।
- **2004 :** व्लादिमीर पुतिन बहुमत हासिल कर दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे।
- **2018 :** ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी। **कल :** पापमोचनी एकादशी व्रत, नौचंदी मेला मेरठ प्रारंभ, वसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले। **राहुकाल :** सायं 16.30 से 18.00 तक।

कल का पंचांग

■ सूर्योदय : 06.35
■ सूर्यास्त : 18.26
(भारतीय मानक समयानुसार)

विक्रमी संवत 2082, 24 फाल्गुन मास शक 1947, चैत्र मास 02 प्रविष्टे, 25 रमजान हिजरी 1447, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी 09.16 तक उपरांत द्वादशी, श्रवण नक्षत्र 29.55 तक उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र, परिघ योग 10.24 तक उपरांत शिव योग, बालव करण 09.16 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा मकर राशि में दिन-रात।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : नौकरी में उन्नति का अवसर मिल सकता है। व्यावसायिक लाभ से संतुष्ट रहेंगे। सेहत नरम रहेगी।

वृष : नौकरी में नई परेशानी आ सकती है। धन उधार देने से बचें। व्यावसायिक निर्णय सोच-समझकर लें।

मिथुन : मानसिक तनाव में कमी आ सकती है। व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा। परिवार में आनंद बना रहेगा।

कर्क : आरोग्य सुख में कमी रहेगी। कार्य में विलंब होगा। नौकरी में दबदबा बना रहेगा। घर में शांति बनाए रखें।

सिंह : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में प्रशंसा मिल सकती है। व्यवसाय में नया अनुबंध हो सकता है।

कन्या : नई योजना में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में बदलाव हो सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है।

तुला : नौकरी में कार्य कुशलता का लाभ मिल सकता है। व्यवसाय में धन लाभ के अवसर मिल सकता है।

वृश्चिक : तनाव से बचें। नौकरी में सावधानी बरतें। आर्थिक दबाव बना रहेगा। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

धनु : व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अनुकूल सूचना से हर्ष होगा।

मकर : तनाव रहेगा। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। व्यवसाय में मंदी रहेगी। विरोधी पक्ष से सचेत रहें।

कुंभ : क्रोध एवं वाणी पर नियंत्रण रखें। नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। अटका धन मिलेगा।

मीन : सत्ता का सहयोग मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से अर्थ प्राप्ति संभव है। नौकरी में उन्नति हो सकती है।

जन्मदिन

आमिर खान, अभिनेता

आज जन्मे जातक व्यवहार कुशल, परिश्रमी एवं बुद्धिमान होते हैं। इस वर्ष मान प्रतिष्ठा को नया आकार मिलेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। रोजगारपरक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। साझेदारी का नया प्रस्ताव आ सकता है। इस वर्ष यदा कदा उदर कष्ट संभव है।

सुडोकू

				7	2	1	3	
1		5	3		6	8		7
3								
		4	5			7		6
6		2				5		9
7		1			8	2		
								4
8		7	6		4	3		1
	4	6	2	1				

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

4	6	9	8	7	2	1	3	5
1	2	5	3	4	6	8	9	7
3	7	8	1	9	5	4	6	2
9	3	4	5	2	1	7	8	6
6	8	2	4	3	7	5	1	9
7	5	1	9	6	8	2	4	3
2	1	3	7	8	9	6	5	4
8	9	7	6	5	4	3	2	1
5	4	6	2	1	3	9	7	8

डेली हेल्थ कैप्सूल

त्वचा और तेज याददाश्त के लिए गोटू कोला

गोटू कोला एक औषधीय पौधा है, जिस पर आधुनिक विज्ञान में कई मेडिकल और फार्माकोलॉजी रिसर्च हुई हैं।

मंडूकपर्णी को आम भाषा में गोटू कोला के नाम से जाना जाता है। यह छोटा-सा हरा पौधा होता है, जिसकी पत्तियां गोल होती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सेंटेला एशियाटिका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इसमें कई पोषक तत्व और एंटी-ऑक्सिडेंट्स होते हैं। यही कारण है कि इसे आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में काफी महत्वपूर्ण माना जाता

है। यह मानसिक थकान कम करने और याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। साथ ही ये घाव भरने में भी मदद करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि गोटू कोला के अर्क से क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी (पैरों में सूजन, भारीपन) के लक्षण कम हो सकते हैं। गोटू कोला शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। शरीर में रक्त संचार बेहतर तरीके से होने से अंगों तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं। गोटू कोला का उपयोग आप पत्तियों से हर्बल चाय बनाकर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पाउडर और कैप्सूल भी मिल जाते हैं। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर में होने वाली सूजन और दर्द को कम करते हैं। इससे गठिया के दर्द में भी राहत मिलती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

किसी भी हर्बल चीज का नियमित सेवन करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूरी होती है। सही मात्रा और सही तरीके से उपयोग करने पर ही गोटू कोला का पूरा लाभ मिलता है।

-डॉ. आर. पी. पाराशर
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद वीआईपी सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा करेगा गृह मंत्रालय

गृह मंत्री शाह ने दिए निर्देश, केंद्रीय सूची में करीब 400 वीआईपी

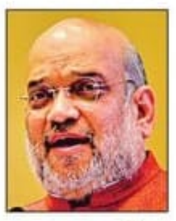

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले के प्रयास के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार, अगले सप्ताह सभी वीआईपी सुरक्षा प्रबंधों का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा।

यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और गृह मंत्रालय के वीआईपी सुरक्षा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय सूची में करीब 400 वीआईपी विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों में शामिल हैं। इनमें लगभग 220 लोगों को सीआरपीएफ, 156 को सीआईएसएफ, नौ को एनएसजी और कुछ को आईटीबीपी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल ही इन वीआईपी की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले समय में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी दौर में कई राजनीतिक वीआईपी को इन राज्यों में व्यापक यात्रा करनी होगी, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात जम्मू में एक विवाह समारोह से निकलते समय हमला करने की कोशिश की गई थी। ब्यूरो

पीएम मोदी आज प.बंगाल को देंगे 18,680 करोड़ की सौगात

कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वह दोपहर लगभग 2 बजे कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रधानमंत्री लगभग 16,990 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 420 किलोमीटर से अधिक की कुल लंबाई वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान कई जहाजरानी और बंदरगाह संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। वे हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के बर्थ नंबर 2 के मशीनीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो

228 करोड़ की धोखाधड़ी

अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल से पूछताछ

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े 228 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से शुक्रवार को पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शनिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ने यह पूछताछ उस मामले में की, जिसमें जय अनमोल अंबानी के साथ रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्व पूर्णकालिक निदेशक रविंद्र सुधाकर सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कंपनी की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले 9 दिसंबर, 2025 को सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनमोल के आवास पर तलाशी भी ली थी। ब्यूरो

आप चाहते हैं, हम पूरा देश चलाएं आपकी याचिका शॉपिंग मॉल जैसी

शीर्ष कोर्ट ने सड़कों, पुलों व बिजली समेत अन्य समस्याओं को लेकर व्यापक निर्देश देने की मांग वाली याचिका की खारिज

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों, पुलों और बिजली के तार समेत अन्य बुनियादी ढांचे को दुरुस्त रखकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जिस प्रकार शॉपिंग मॉल में तकरीबन हर प्रकार की चीज मिलती है, उसी तरह इस याचिका से भी हर प्रकार की राहत मांगी गई है। पीठ ने कहा कि जब तक उठाए गए मुद्दे स्पष्ट नहीं होते, ऐसे निर्देश जारी करना लगभग असंभव है, जिन्हें लागू करना असंभव होगा। हम इस रिट याचिका को खारिज करते हैं और याचिकाकर्ता को उचित तरीके से तैयार याचिका के साथ संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट देते हैं। पीठ ने साफ किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप व्यापक निर्देश मांग रहे हैं। याचिका के आधार पर दिए गए दिशानिर्देशों का वित्तीय प्रभाव भी होगा और संबंधित राज्यों के वित्त को समझने के लिए हाईकोर्ट सबसे उपयुक्त है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूरे देश में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पीठ ने याचिका में किए गए अनुरोधों का संदर्भ देते हुए पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं? आपकी याचिका बिल्कुल एक शोरूम या शॉपिंग मॉल जैसी है। सड़कों के गड्ढे भरने से लेकर सड़कें बनाने, अधूरे पुल जैसी संरचनाओं को पूरा करने तक, सब कुछ इसमें शामिल है। आप धरती पर किसी भी प्रकार की राहत का नाम लें, सब कुछ इसमें मौजूद है।

ममता पर टिप्पणी साझा करने वाले वकील के खिलाफ मानहानि मामले में यथास्थिति का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता कौस्तव बागची के खिलाफ दायर मानहानि मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। बागची पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित निजी जीवन पर आरोप लगाने वाली एक किताब के अंश सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बागची की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में उन्हें समन जारी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यह विवाद 2015 में प्रकाशित एक पुस्तक से शुरू हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने गुप्त रूप से शादी कर ली थी। इसमें मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले उनके निजी जीवन के कुछ अन्य विवरण भी छापे गए थे। ब्यूरो

डाटा संरक्षण कानून की चुनौती वाली अर्जी पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के डाटा संरक्षण कानून के प्रावधानों के खिलाफ दायर एक नई याचिका पर शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी किया। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अंजली भारद्वाज और अमृता जोहरी की याचिका को ऐसी ही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। नई याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण, विश्लेषण, प्रसार या पुनर्प्रकाशन पर 2023 अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसमें यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि 2023 अधिनियम के प्रावधान सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण पर लागू नहीं होंगे, जिसमें भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद के दुरुपयोग या अपराध के कमीशन का खुलासा करने वाले लोग भी शामिल हैं। ब्यूरो

न्यूज डायरी

भारत-अमेरिका में व्यापार समझौते पर बातचीत जारी, नहीं लगा विराम

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका पारस्परिक लाभप्रद द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत में लगे हुए हैं। मंत्रालय ने द्विपक्षीय वार्ता में विराम की खबरों का खंडन किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता से संबंधित एक मीडिया रिपोर्ट हमारे संज्ञान में आई है। इसमें वार्ता पर विराम लगाने की बात कही गई है। हम द्विपक्षीय वार्ता में किसी भी प्रकार के विराम का खंडन करते हैं। दोनों पक्ष व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। ब्यूरो

अन्नाद्रमुक से निष्कासित शशिकला ने बनाई पार्टी

चेन्नई। अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता वीके शशिकला ने शुक्रवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी के नाम की घोषणा कर दी। उनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया पुरैची थलाइवर मक्कल मुनेत्र कड़गम होगा। इससे पहले 24 फरवरी को दिवंगत जयललिता की जयंती पर उन्होंने रामनाथपुरम में पार्टी का झंडा फहराया था। शशिकला ने बताया कि पार्टी का चुनाव चिह्न नारियल का बाग होगा, जो एकता का प्रतीक है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। एजेंसी

पीएलएफआई का उग्रवादी गिरफ्तार, एके-47 समेत भारी संख्या में हथियार जब्त

पटना। बिहार के नवादा जिले के रजौली प्रखंड में शुक्रवार तड़के पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के उग्रवादी अजीत कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक एके-47 राइफल, .315 बोर की दो राइफल, 31 कारतूस और नक्सली वर्दी बरामद की है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए उग्रवादी से पूछताछ जारी है, ताकि उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। मामले में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो

शोपियां में जाली नोटों के रैकेट का खुलासा, बीडीओ समेत तीन लोग गिरफ्तार

शोपियां। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को शोपियां में जाली मुद्रा चलाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने एक ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 79,000 के जाली नोट बरामद किया। आरोपियों की पहचान मो.सैयद वानी निवासी बटपोरा, मो. मकबूल नाइकू निवासी बंगाम और बीडीओ पीरजादा अल्ताफ निवासी टुकरू बाबनाद के तौर पर हुई है। ब्यूरो

आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज...पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में करेगा प्रवेश

पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी, कई मैदानी राज्यों में आंधी और वज्रपात के आसार

अमर उजाला नेटवर्क

अटल टनल रोहतांग के सिस्सू के समीप बर्फबारी के बाद शुक्रवार को बर्फ से ढ़की पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी।

नई दिल्ली। देश में मौसम एक बार फिर तेजी से करवट लेने वाला है। भारत मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 14 मार्च से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों, खासकर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गर्मी और लू का असर जारी रहने की आशंका भी बनी हुई है।

पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 मार्च को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 15 से 18 मार्च के बीच इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

उत्तराखंड में भी 14 और 15 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, जबकि 15 और 16 मार्च को राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 17 मार्च के बीच पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। 15 से 17 मार्च के दौरान हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। उत्तर प्रदेश में 15 और 16 मार्च को आंधी और बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में 14 और 15 मार्च को गरज के साथ बारिश और वज्रपात हो सकता है।

कुछ राज्यों में लू का खतरा

जहां कई क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, वहीं कुछ इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात हिमाचल प्रदेश और कोंकण-गोवा के कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका है।

इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भीषण लू की स्थिति बन सकती है। गुजरात, केरल और तटीय कर्नाटक में उमस भरी गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में रात का तापमान भी अधिक रह सकता है, जिसे वार्म नाइट की स्थिति कहा जाता है।

जेट स्ट्रीम बना रही मौसम प्रणाली मजबूत

उत्तर-पश्चिम के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी सक्रिय है। यह लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बह रही है और इसकी हवा की गति करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब इसकी गति तेज होती है तो पश्चिमी विक्षोभ भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ जाती है।

पूर्वोत्तर भारत में आंधी-तूफान की आशंका... पूर्वोत्तर भारत में इस समय असम के आसपास एक चक्रवाती प्रसार सक्रिय है। इसके प्रभाव से असम और मेघालय में तेज आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी आंधी, वज्रपात और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सिक्किम और उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना जताई गई है।

सिविल जज के आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाएं हाईकोर्ट : शीर्ष कोर्ट

तीन साल के प्रैक्टिस नियम की समीक्षा के बीच आया निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की विशेष पीठ चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन साल के विधि अभ्यास की अनिवार्यता वाले पूर्व के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल थीं।

पिछले साल 20 मई को, शीर्ष न्यायालय ने तीन साल वकालत करने की न्यूनतम शर्त निर्धारित करते हुए, नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। हालांकि, सीजेआई की पीठ ने बाद में प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए तीन साल की अवधि के मानदंड पर सभी हाईकोर्ट, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और अन्य विधि विद्यालयों की राय मांगी। इसने पुनर्विचार याचिकाओं पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया। सीजेआई ने अगले सप्ताह याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई करने का निर्णय लेते हुए निर्देश दिया कि सभी मौजूदा और भविष्य में जारी होने वाली भर्ती अधिसूचनाओं में विस्तारित समय सीमा को दर्शाया जाना चाहिए। पीठ ने आदेश दिया, सभी हाईकोर्ट अगर विज्ञापन जारी कर चुके हैं तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2026 तक बढ़ाएं। ब्यूरो

गोवा : पणजी निकाय चुनाव में भाजपा का परचम, 30 में से 27 सीटों पर जमाया कब्जा

पणजी। गोवा विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राजधानी पणजी के नगर निगम (सीसीपी) चुनावों में भाजपा समर्थित पैनल ने प्रचंड जीत दर्ज की है। मंत्री अतानासियो मोन्सेराते के नेतृत्व वाले पैनल ने 30 में से 27 सीटों पर कब्जा कर विपक्ष को पूरी तरह किनारे कर दिया। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर की ओर से समर्थित पैनल केवल 3 सीटों पर सिमट गया।

विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जीत, उत्पल पर्रिकर के पैनल को मिली शिकस्त

इस जीत को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भाजपा खेमे में इस परिणाम से उत्साह है। मोन्सेराते ने जीत पर कहा कि हमने विकास के दम पर यह सफलता पाई है और आगे भी शहर की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। दूसरी ओर हार के बावजूद उत्पल पर्रिकर ने इसे जवाबदेही की लड़ाई बताई। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद केवल जीत नहीं, बल्कि नागरिकों को एकजुट कर शहर के मुद्दों पर चर्चा शुरू करना था। एजेंसी

महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण तो सात साल कैद, 5 लाख तक जुर्माना...विधेयक पेश

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने जबरन या धोखे से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। प्रस्तावित कानून में लालच, दबाव, धोखाधड़ी, धमकी या किसी भी अनुचित तरीके से धर्मांतरण कराने पर अधिकतम सात साल तक की सजा और पांच लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा में यह विधेयक राज्य के गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने पेश किया। इसके मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है या धर्मांतरण का कोई समारोह आयोजित किया जाता है तो उससे 60 दिन पहले संबंधित प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही, यदि धर्मांतरण को लेकर शिकायत दर्ज होती है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपित व्यक्ति पर होगी कि धर्मांतरण स्वेच्छा से हुआ है। यदि पीड़ित महिला, नाबालिग, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हो तो 7 साल तक की जेल और 5 लाख तक जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति या संस्था दोबारा ऐसा अपराध करती है तो 10 साल तक की सजा और 10 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि ऐसे विवाह से बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का धर्म मां के धर्म के आधार पर माना जाएगा। अगर, किसी का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया गया है तो वह स्वयं या उसके माता-पिता, भाई-बहन अथवा रिश्तेदार पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ब्यूरो

चुनाव से पहले ममता का बड़ा दांव, पांच समुदायों के लिए बनेंगे नए विकास बोर्ड

कोलकाता। प.बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पांच समुदायों के लिए नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की। राज्य सरकार का कहना है कि इन बोर्डों का उद्देश्य संबंधित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना है।

सामाजिक समूहों में समर्थन मजबूत करने की कोशिश आदिवासी-पिछड़ों पर फोकस

सरकार के अनुसार ये बोर्ड मुंडा (अनुसूचित जनजाति), कोरा (अनुसूचित जनजाति), डोम (अनुसूचित जाति), कुम्भकार (अन्य पिछड़ा वर्ग) और सदगोप (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदायों के लिए बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये बताया कि इन बोर्डों के माध्यम से इन समुदायों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वर्ष 2013 से उनकी सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए कई सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बना चुकी है और यह कदम उसी प्रयास का हिस्सा है। घोषित समुदायों में मुंडा और कोरा अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, जबकि डोम समुदाय अनुसूचित जाति में शामिल है। ब्यूरो

लातेहार से 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार

लातेहार। झारखंड के लातेहार जिले में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य मृत्युंजय भुइयां को गिरफ्तार किया है। उस पर सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

एसपी कुमार गौरव ने बताया कि छीपादोहर थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष सर्च ऑपरेशन के दौरान उक्त माओवादी को दबोचा गया। मृत्युंजय कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। फिलहाल सुरक्षाबल क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। यह गिरफ्तारी इलाके में सक्रिय माओवादी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। एजेंसी

आंध्र में अवैध ड्रग्स फैक्टरी पकड़ी, 237 किलो माल जब्त

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने आंध्र प्रदेश में अवैध अल्प्राजोलम फैक्टरी का भंडाफोड़ करते हुए 237 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 47 करोड़ है। इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 11 और 12 मार्च को चलाए गए ऑपरेशन व्हाइट हैमर के तहत यह कार्रवाई की गई। ब्यूरो

बैंक धोखाधड़ी : बीएनआर व एलीट इंफ्रा की 35 करोड़ की संपत्ति अटैच

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग, एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रालि. और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में 35.05 करोड़ की संपत्तियों को अटैच की। ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल की संपत्तियों को अटैच किया। ईडी ने सीबीआई, ईओडब्ल्यू, चेन्नई और सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद की दो एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। एफआईआर के अनुसार बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग और एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रालि. ने जाली दस्तावेजों से ऋण सुविधाएं प्राप्त कर एसबीआई को लगभग 8.20 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 26.86 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। ब्यूरो

छह घंटे से कम सोते हैं 46% भारतीय, देश में बढ़ रहीं नींद से जुड़ी बीमारियां

चिंताजनक : 72 फीसदी लोगों की रात में बार-बार टूट जाती है नींद, विशेषज्ञों ने चेताया-सेहत के लिए हानिकारक

अमर उजाला नेटवर्क

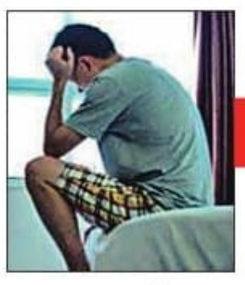

नई दिल्ली। भारत में नींद की कमी तेजी से एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 46 फीसदी लोग रोजाना छह घंटे से भी कम सोते हैं। विशेषज्ञ इसे साइलेंट स्लीप एपिडेमिक यानी चुपचाप फैलती नींद की महामारी बता रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार बदलती जीवनशैली, बढ़ता स्क्रीन टाइम, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण बड़ी संख्या में लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार कम नींद लेने से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बल्कि उत्पादकता घटने के कारण अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के लिए देश के 393 जिलों से लगभग 89,000 लोगों की राय ली गई। सर्वे में सामने आया कि 46 फीसदी लोग रोजाना छह घंटे से कम सोते हैं। इसके अलावा 72 फीसदी लोगों ने बताया कि उनकी नींद रात में बीच-बीच में टूट जाती है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें रात में बार-बार जागना पड़ता है, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि युवाओं और कामकाजी लोगों में नींद की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि रिपोर्ट में एक सकारात्मक संकेत भी देखने को मिला है। पिछले साल किए गए इसी सर्वे में 59 फीसदी लोग छह घंटे से कम सोते थे, जबकि इस बार यह संख्या घटकर 46 फीसदी रह गई है। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे लोग नींद के महत्व को समझने लगे हैं और अपनी आदतों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार युवाओं और कामकाजी लोगों में नींद से जुड़ी समस्याएं अधिक देखी जा रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें मोबाइल और लैपटॉप का अत्यधिक उपयोग, देर रात तक सोशल मीडिया चलाना, अनियमित दिनचर्या, पढ़ाई और काम का दबाव प्रमुख हैं। कई लोग देर रात तक फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता। इसका परिणाम यह होता है कि नींद आने में देरी होती है और नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

युवाओं और कामकाजी लोगों में ज्यादा समस्या

स्वास्थ्य पर गंभीर असर

विशेषज्ञों का कहना है कि नींद की कमी केवल थकान तक सीमित नहीं है बल्कि यह कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध के अनुसार लगातार कम नींद लेने से दिमाग, दिल, मानसिक स्वास्थ्य और शरीर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। शोध के मुताबिक केवल एक रात की कम नींद भी दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित कर सकती है जो निर्णय लेने और सोचने की क्षमता को नियंत्रित करता है। नींद की कमी से चिंता और डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, डायबिटीज और काम में खराब प्रदर्शन तथा त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इसी कारण विशेषज्ञ अब नींद को स्वास्थ्य का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम।

रक्तदान में एनएटी टेस्ट अनिवार्यता से सुप्रीम इन्कार...कहा-यह तय करना विशेषज्ञों का काम

शीर्ष अदालत ने याचिका ठुकराई कहा-हम मेडिकल साइंस जानने का दिखावा क्यों करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संक्रमण मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी ब्लड बैंकों में रक्तदान स्वीकारते समय न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन एसिड टेस्ट (एनएटी) अनिवार्य बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने इस विशेषज्ञों का काम माना और टिप्पणी की कि हमें मेडिकल साइंस जानने का दिखावा क्यों करना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील से यह भी कहा, क्या आपको लगता है कि जनहित याचिकाओं को विदेश से वित्त पोषित नहीं किया जाता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? पीठ ने याचिकाकर्ता

को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष अपना मामला रखने की सलाह देते हुए कहा कि हम निश्चित तौर पर इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। अदालत ने कहा कि एनएटी परीक्षण अपेक्षाकृत महंगा है और इसे अनिवार्य करने से राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद माना है कि एनएटी परीक्षण अन्य पारंपरिक जांचों की तुलना में अधिक खर्चीला है। ऐसे में अदालत के लिए इसे अनिवार्य बनाने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका में उठाया गया मुद्दा किसी मौजूदा कानून की व्याख्या से संबंधित नहीं है। ब्यूरो

- शीर्ष कोर्ट ने इससे पहले 25 फरवरी को एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों का पता लगाने के लिए देशभर के सरकारी अस्पतालों में एनएटी कराने की सुविधा की उपलब्धता और लागत जैसे विवरण मांगे थे। पीठ ने यह भी पूछा था कि क्या सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है, ताकि गरीब लोग भी इसका लाभ उठा सकें।

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

एक और महाभियोग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदन में जो नोटिस दिया है, वह ऐतिहासिक है। कई लोगों को इस पर अफसोस होगा और कई लोग इसके पीछे सिर्फ सियासत देख रहे होंगे, पर सच यही है कि इस नोटिस या महाभियोग को लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों का समर्थन मिल चुका है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रयासों से यह विपक्षी अभियान चल रहा है। देश में यह पहली बार है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाला नोटिस पेश किया गया है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त पर मुख्यतः सात आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जान-बूझकर बाधा डालने और सामूहिक मताधिकार से वंचित करने जैसे आरोप शामिल हैं। देश में पहले भी विपक्षी दल चुनाव आयुक्तों पर पक्षपात के आरोप लगाते थे, पर कभी महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ी थी। यह कहना ही चाहिए कि विपक्षी दल मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं।

विगत कुछ वर्षों से विपक्ष वोट चोरी जैसे आरोप कुछ ज्यादा ही लगाता आया है और चुनाव आयोग की भी शिकायत करता आया है। अच्छा मौका है, अब विपक्ष सदन में साबित कर दिखाए कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे अनैतिकता बरत रहे हैं। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी हटाने के हर मुमकिन उपाय किए थे, पर सफलता नहीं मिली। अब क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने में सफलता मिलेगी? विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है, पर क्या विपक्ष नैतिक रूप से इतना सुदृढ़ है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अकाट्य तथ्य पेश कर सकता है? यहां यह ध्यान रखने की जरूरत है कि एक लंबा दौर देश में ऐसा रहा है, जब चुनाव आयुक्तों को सत्तारूढ़ दल सिर्फ अपनी मर्जी से नियुक्त करता था। पहले की केंद्र सरकारों ने रिटायर हो चुके चुनाव आयुक्तों को ऊंचे पद दिए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया है। देश में शायद ही कोई ऐसा दौर रहा हो, जब चुनाव आयुक्तों को आरोपों का सामना न करना पड़ा हो। खैर, विपक्षी दल अपने अधिकार के तहत महाभियोग ला रहे हैं और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त अनैतिक हैं, तो उनके लिए चुनाव आयोग में जगह नहीं होनी चाहिए। वाकई, वोट चोरी और फर्जी मतदान को यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। उम्मीद है, महाभियोग पर सदन में जो बहस होगी, उससे देश को कुछ सबक हासिल होंगे।

विपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने में सफलता नहीं मिली, पर क्या अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने में सफलता मिलेगी?

ध्यान रहे, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ है। उसे लगता है कि यह पुनरीक्षण भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वैसे, तृणमूल कांग्रेस पुनरीक्षण के खिलाफ कोलकाता से दिल्ली तक हर तरकीब आजमा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुनरीक्षण की प्रक्रिया को रोका नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभी पुनरीक्षण का काम न्यायिक निगरानी में चल रहा है, पर स्पष्ट है, तृणमूल कांग्रेस या विपक्षी दलों को न्यायिक निगरानी पर विश्वास नहीं है। यह एक बड़ी चिंता की बात है। वास्तव में, पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों की भी बड़ी भूमिका होती है। ये दल और उनके कार्यकर्ता अगर ठान लें, तो फर्जी मतदान तो दूर की बात, कोई फर्जी मतदाता भी नहीं बन सकता। यह अफसोस की बात है कि अपने स्तर पर राजनीतिक दल मतदाता परीक्षण ठीक से नहीं करते हैं। महाभियोग अपनी जगह है, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल इस पूरी कवायद से कुछ सीखेंगे?

भारत के लिए बहुत अहम अमीरात

यशवंत देशमुख | संस्थापक, सीवोटर

यूएई सरकार लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए हर कदम उठा रही है। ड्रोन व मिसाइलों को रोक रही है। ठीक वैसे ही, जैसे 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने किया था।

कई बार छोटे देश भी दुनिया पर बड़ा असर डालते हैं, खासकर जब बात वैश्विक व्यवस्था की हो। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई के रिश्ते को देखते हुए यही बात सबसे पहले ध्यान में आती है। यूएई भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन उसकी रणनीतिक अहमियत, सोच, प्रभाव और उसके नेताओं की दूरदर्शिता बहुत बड़ी है। यही वजह है कि पिछले चार-पांच दशकों से भारत की अलग-अलग सरकारों ने उसके साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, जिसका फायदा सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकों और पूरे क्षेत्र को भी मिला है।

1980 के दशक में यूएई ज्यादातर भारतीयों के लिए कोई बड़ा देश नहीं था। हां, कुछ लोग दुबई, शारजाह और दूसरी जगहों पर काम करने जाते थे और अच्छी कमाई कर लेते थे। उनमें बड़ी संख्या केरल से थी, कुछ आंध्र प्रदेश से और कुछ अन्य राज्यों से भी। उस समय यूएई की पहचान भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैचों से ज्यादा थी। हालात 1980 के दशक के बाद तेजी से बदले। शारजाह ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीतते भी देखा और हारते भी, मगर तब जो रिश्ता बहुत साफ नहीं था, वह अब बहुत अहम बन गया है।

संयुक्त अरब अमीरात भले ही एक छोटा देश है, पर वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर से भी ऊपर जा चुका है। जरा सोचिए- अमेरिका, जिसकी आबादी करीब 35 करोड़ है और अर्थव्यवस्था लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की, और चीन, जिसकी आबादी लगभग 130 करोड़ है और अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की- ये दोनों भारत के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। लिहाजा ज्यादातर भारतीयों को यह जानकर हैरानी होती है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार न ब्रिटेन है, न कनाडा, न जापान और न ही कोई अन्य बड़ा देश। वह है- संयुक्त अरब अमीरात।

भारत-यूएई की यह साझेदारी पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। 2022 में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ, उसके बाद व्यापार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि कई शुल्क बाधाएं कम हुईं। और यह रिश्ता एकतरफा नहीं है, यूएई को भारत बड़े पैमाने पर सामान निर्यात भी करता है और वहां से आयात भी करता है। 2022 में लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच जाए। यह लक्ष्य तो एक साल से भी पहले पूरा हो चुका है। अब 200 अरब डॉलर का लक्ष्य भी असंभव नहीं लगता।

यहां करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं। वे यहां सिर्फ काम करके पैसा कमाने के लिए नहीं हैं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन के साथ रह रहे हैं। उन्हें यह भरोसा है कि कानून सबके लिए काम करता है। इसलिए बात अब सिर्फ इतनी नहीं रह गई कि भारतीय यूएई में रहते हैं और हर साल करीब 25 अरब डॉलर रकम भारत भेजते हैं। बात यह भी है कि जो देश आज से करीब पांच दशक पहले तक दुनिया में बहुत कम जाना जाता था, वह दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत आज व्यापार, बैंकिंग, वित्त और निवेश का बड़ा वैश्विक केंद्र बन चुका है। यह अब उन जगहों में शामिल हो चुका है, जिनको दुनिया भर के प्रवासी अपना घर मानते हैं। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान या कोई अन्य देश-यूएई मेहनती पेशेवरों, कारोबारियों और बेहतर जीवन का सपना देखने वालों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है।

इस देश की रणनीतिक अहमियत भी खूब है। भारत से यूरोप तक जाने वाला जो कॉरिडोर प्रस्तावित है, वह जब भी पूरी तरह आकार लेगा, उसमें यूएई की बड़ी भूमिका होगी। माना जा रहा है कि इसे पूरा होने में एक दशक का समय लग सकता है, पर तब तक भारत और यूएई एक-दूसरे के मजबूत साझेदार बने रहेंगे। यह रिश्ता राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। इसी वजह से पश्चिम एशिया में हाल का संघर्ष एक अस्थायी रुकावट की तरह देखा जाना चाहिए।

यहां रहने वाले भारतीय इसे अपना दूसरा घर मानते हैं। कुछ तो यहां दशकों से रह रहे हैं। मैं खुद यहां 15 साल से अधिक समय से हूं। लोगों ने अपने परिवार यहां ऐसे माहौल में पाले-बढ़ाए हैं, जहां सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। यहां के शासक सिर्फ व्यावहारिक नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़कर नेतृत्व करने वाले लोग हैं। भारत में बहुत से लोग दुबई को सिर्फ दो बातों से जोड़कर देखते हैं- कर-मुक्त अर्थव्यवस्था और सोना बेचने वाली मशीनें, पर यदि आप यहां रहने वाले लोगों से बात करें, तो वे बताएंगे कि यूएई की विशेषता क्या है।

सबसे बड़ी विशेषता है- यहां की सुरक्षा। दूसरी, आसान और डिजिटल व्यवस्था, जहां कारोबार चलाने में बेवजह की सरकारी रुकावटें बहुत कम हैं। तीसरी है, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा। चौथी है, बड़ा भारतीय समुदाय, खान-पान और संस्कृति की नजदीकी, जिसकी वजह से यहां अपनेपन का एहसास होता है। पांचवीं, भारत के करीब होना। यहां से भारत के एक दर्जन से ज्यादा शहरों के लिए सीधी उड़ानें हैं, और दिल्ली के लिए तो लगभग हर एक-दो घंटे में उड़ान मिल जाती है। इसलिए, इस मुल्क को 'दूसरा घर' मानने की वजह सिर्फ टैक्स-फ्री व्यवस्था या सस्ता सोना नहीं है। इस देश के संस्थापकों ने लगातार कोशिश की है कि यह लाखों मेहनती प्रवासियों के लिए अवसरों की जगह बने और वह भी अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाए रखते हुए। यह बात सीखने लायक है।

मौजूदा अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान मैंने कई जगहों पर पढ़ा है कि यह जंग यूएई की सुरक्षित छवि को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि, ऐसे दावे करने वाले लोग एक अहम बात भूल जाते हैं। सुरक्षा का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि कोई मिसाइल आपकी तरफ आए और उसे रास्ते में रोक दिया जाए। सुरक्षा का मतलब यह भी है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी सुरक्षित और व्यवस्थित है।

यहां की सरकार लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए हर कदम उठा रही है। ड्रोन और मिसाइलों को रोक रही है, ठीक वैसे ही, जैसे पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने किया था। तब जम्मू, अंबाला और अमृतसर जैसे इलाकों में आसमान में तनाव दिखा था, वैसा ही तनाव अभी अरब देशों में दिख रहा है। हम भी इस मुश्किल दौर से निकल जाएंगे। हमारे लिए यह घर है। दूसरा घर सही, पर घर तो है। और जब घर पर संकट आता है, तो इंसान उसे छोड़कर नहीं भागता।

(यूएई में रह रहे लेखक के अपने विचार)

फिल्म निर्माण में सहायक साबित हो रहा एआई

किंशुक पाठक | एसोसिएट प्रोफेसर, पंजाब केंद्रीय विवि.

प्रगतिशील डिजिटल क्रांति के इस युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई अब केवल विज्ञान-कथा की कपोल-कल्पना नहीं रहा, फिल्म-निर्माण की दुनिया में भी वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। एआई का उपयोग अब पटकथा लेखन से लेकर वीएफएक्स, डबिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन तक प्रत्येक चरण में अत्यधिक हो रहा है। यह तकनीक न केवल आर्थिक रूप से लाभ दे रही है, बल्कि अपार रचनात्मक एवं सृजनात्मक संभावनाओं को भी मूर्त रूप दे रही है।

'ग्रैंड व्यू' रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में एआई फिल्म-निर्माण बाजार का वैश्विक मूल्य लगभग 3.24 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2033 तक लगभग 23.54 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, यानी वर्ष 2025 से 2033 की अवधि में 25.4 प्रतिशत की अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर। इसी गति से एआई ने 2024 में लगभग 38.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ उत्पादन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। फिल्म-निर्माण में एआई का उपयोग एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से हो रहा है, जिसमें भारत, चीन और दक्षिण कोरिया का योगदान सराहनीय है।

एआई की मदद से स्वतंत्र फिल्मकार कम बजट में फिल्में बना सकते हैं, पर यह स्थायी विकल्प नहीं है, पूरक मात्र है।

प्रोडक्शन के स्तर पर रीयल-टाइम कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, वीएफएक्स ऑटोमेशन और डी-एजिंग का काम महत्वपूर्ण होता है। इसमें एआई की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। पिछले साल आई हॉलीवुड की फिल्म द *ब्रूटलिस्ट* में एड्रियन ब्रॉडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन को एआई से परिवर्तित और रचनात्मक बनाकर ऑस्कर भी जीता, वहीं *हियर* (2024) फिल्म में एआई का उपयोग करके टॉम हैंक्स और रॉबिन राइट की डी-एजिंग (उम्र को कम दिखाना) की गई। पोस्ट-प्रोडक्शन की बात करें, तो कलर करेक्शन, साउंड डिजाइन, डबिंग और लोकलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण कामों में एआई का उपयोग किया जा रहा है। रनवे और लूमा जैसे एआई उपकरण अब पूरी सीन फिल्माने में भी समर्थ हैं।

भारतीय फिल्म उद्योग वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा है और यहां पर एआई को हॉलीवुड से कहीं अधिक उत्साह व रचनात्मकता के साथ अपनाया जा रहा है। *नैशा* (2025) भारत की पहली फिल्म है, जिसे एआई से तैयार किया गया है। इसमें लगभग 95 प्रतिशत दृश्य मिडजर्नी और चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके फिल्माए गए हैं। एआई का उपयोग करके डी-एजिंग जैसे कार्यों का उत्कृष्ट उदाहरण मलयालम फिल्म *रेखाचित्रम* (2025) में दिखता है, जहां 73 वर्षीय ममूटी को 30 साल का युवा दिखाया गया है। बहुचर्चित फिल्म *कल्कि* (2024) में अमिताभ बच्चन का युवा अवतार एआई का शानदार उदहारण है। *डबिंग घोस्ट* फिल्म को एआई का उपयोग करके हिंदी, तेलुगु और मलयालम भाषा में डब किया गया। श्रीजित मुखर्जी ने दिवंगत सत्यजीत रे और उत्तम कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एआई का उपयोग करके आवाज क्लोन की। इस प्रकार के अनेक प्रयोग भारत में दिखाई देते हैं।

एआई के फायदे वैश्विक स्तर पर निर्विवाद हैं, पर इसके नुकसान को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। भारत में अभी कोई व्यापक कानून नहीं है, जिससे इसके उपयोग को लेकर कोई दिशा-निर्देश मिल सके। अभिनेताओं की निजता एवं व्यक्तित्व का दुरुपयोग और नौकरियों का खतरा चिंता के प्रमुख विषय हैं। निर्देशक जिथिन लाल जैसे अनेक निर्देशकों की मुख्य चिंता है कि एआई में भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक सूक्ष्मता का अभाव है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है।

एआई फिल्म-निर्माण विधि की पूरी प्रक्रिया को ही लोकतांत्रिक स्वरूप दे रहा है। स्वतंत्र फिल्मकार अब हॉलीवुड जैसी फिल्मों के समान फिल्में अत्यंत कम बजट में बना सकते हैं, परंतु यह मानव रचनात्मकता का स्थायी विकल्प नहीं है, बल्कि एक पूरक मात्र है। ऑस्कर अकादमी द्वारा 2025 में स्पष्ट किया गया था कि एआई से बनी फिल्में भी पुरस्कार के योग्य हैं, मगर उनमें मानवीय योगदान सर्वोपरि हो। भारतीय फिल्मों में अगर एआई को सावधानी से अपनाया जाए, तो हम विश्व पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। एआई की उपयोगिता तभी तक है, जब तक इसे उपकरण बनाकर रखा जाए, स्वामी नहीं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सब समझ का कमाल

समझ यानी वह तमीज, जिससे भलाई-बुराई में फर्क किया जाता है। मेरा ख्याल है कि अगर इंसानों के दिल को चीरकर उनका हाल देखा जाए, तो दाना और नादान, दोनों के दिलों में थोड़ा ही फर्क निकलेगा।

दोनों के दिलों में हमेशा बहुत से बेमतलब और बेकार ख्याल आते हैं। दोनों में यही फर्क होता है कि दाना आदमी समझता है कि कौन से ख्यालात ऐसे हैं, जिनको गुफ्तगू में लाना चाहिए, और कौन से ऐसे हैं, जिनको छोड़ देना चाहिए। नादान आदमी ऐसा नहीं करता और जो ख्याल उसके दिल में आता है, वह बगैर सोचे-समझे मुंह से बकता चला जाता है। दानिशमंद आदमी दोस्तों के साथ बातचीत करने में नादान की मानिन्द रहता है और उसके ख्यालात बुलंद आवाज में ही सामने आते हैं।

पिस्टली साहब का यह कौल है कि इंसान को दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव रखना चाहिए कि उसको दोस्त बनाने का मौका बना रहे और दोस्त से इस तरह बर्ताव करना चाहिए कि अगर वह कभी दुश्मन हो जाए, तो उसके नुकसान से बचने की जगह रहे। इस कौल की पहली बात जो दुश्मन के साथ बर्ताव की है, निहायत उम्दा है, मगर पिछली बात, जो दोस्त के साथ बर्ताव की है, वह कुछ अच्छी नहीं। उसमें समझ की कुछ भी बात नहीं, बल्कि निरी मक्कारी है। ऐसे बर्ताव से इंसान जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी से महरूम रहता है। अपने दिली दोस्तों से भी दिल की बात नहीं कह सकता। यह सच है कि कई बार दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दोस्त के भेद को खोल देते हैं, मगर दुनिया उन्हीं को दगाबाज व बुरा कहती है और दोस्त पर भरोसा करने वाले को नासमझ नहीं कहती। हां, दोस्तों के बीच फर्क करने और उन्हें समझने के लिए बड़ी समझ चाहिए।

समझ सिर्फ बातों या कथनी पर निर्भर नहीं है, यह हर किस्म के कामों से संबंधित है। इंसान में बहुत-सी बड़ी उम्दा सिफतें हैं, मगर समझ सबसे ज्यादा मुफीद है। समझ के सबब से ही तमाम सिफतों की कद्र होती है। समझ के ही सबब से वे तमाम सिफतें अपने-अपने मौके पर काम आती हैं। समझ से ही सिफत वालों को फायदा होता है। बगैर समझ इंसान अपने बर्ताव में गलतियां करता है और नुकसान पर नुकसान उठाता है। जिस शख्स को बड़ी से बड़ी लियाकत हासिल हो, पर समझ न हो, तो वह किसी अंधे आदमी की मानिन्द है। किसी शख्स को दुनिया में सब तरह के कमाल हासिल हों, मगर समझ न हो, तो वह दुनिया में किसी काम का नहीं।

इंसान में बहुत-सी उम्दा सिफतें हैं, मगर समझ सबसे ज्यादा मुफीद है। समझ के सबब से ही अन्य तमाम सिफतों की कद्र होती है। समझ के ही सबब से वे तमाम सिफतें काम आती हैं।

एक मुसन्निफ का कौल है कि समझ ही ऐसी रौनक चीज है, जिसका कभी अभाव नहीं, जो इसे चाहते हैं, आंखों के सामने देखते हैं, जो इसे ढूंढ़ते हैं, वे इसे आसानी से पाते हैं। इसकी तलाश में उनको बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, क्योंकि वे इसे अपने ही दरवाजे पर पाते हैं।

सर सय्यद अहमद

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 14 मार्च, 1951

भारतीयों का कर्तव्य

राजधानी में यों तो अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते रहते हैं, परन्तु भाषा के क्षेत्र में शनिवार 10 मार्च को हुई राजभाषा-परिषद का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान द्वारा हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कर लेने के बाद यह तो विवाद ही व्यर्थ है कि हिन्दी राजभाषा होने के उपयुक्त है या नहीं, अब तो केवल इस निश्चय को अमल में लाने का सवाल रह गया है।...

यह एक शुभ लक्षण है कि यह कार्य एक ऐसे व्यक्ति के सभापतित्व में किया गया, जिसकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है और भारतीय संसद का निर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह समस्त भारतीयों का सम्मान-भाजन ही नहीं है बल्कि उनका प्रतिनिधित्व भी करता है। हिन्दी के पक्ष में उठाई गई किसी भी आवाज को हिन्दी वालों की भाषाई प्रभुत्व की आकांक्षा कहकर उपेक्षित करने की जो हीन वृत्ति इन दिनों दीखने लगी है, इस दशा में, हम समझते हैं वह यहां कारगर नहीं हो सकेगी।

जहां तक परिषद और उसकी मांगों का संबंध है, उनमें सन्तुलन और निभाकर चलने की प्रवृत्ति मालूम पड़ती है। उदाहरण के लिए जहां सभापति श्री गणेश वासुदेव मावलंकर ने यह तथ्य सामने रखा कि 'स्वतंत्रता के बाद भारत का सारा कामकाज अब अंग्रेजी में नहीं चल सकता।' और 'यदि हम प्रचलित प्रथा को जल्दी-से-जल्दी बदलने की कोशिश न करें, तो संविधान के उद्देश्य की प्राप्ति हम बहुत समय तक न कर सकेंगे।' वहां, यह बताकर कि 'भारतीय संविधान के 343वें अनुच्छेद में निश्चित किया गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी एवं अनुच्छेद 351 ने ऐसा आदेश दिया है कि हिन्दी भाषा का प्रसार और वृद्धि करना, उसका विकास करना संघ का कर्तव्य होगा,' उन्होंने यह भी बताया कि 'वह हिन्दी कैसी हो, इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि वह भारत की संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां वांछनीय हो, वहां उसके शब्दभंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित हो।'

दलाई लामा | बौद्ध धर्मगुरु

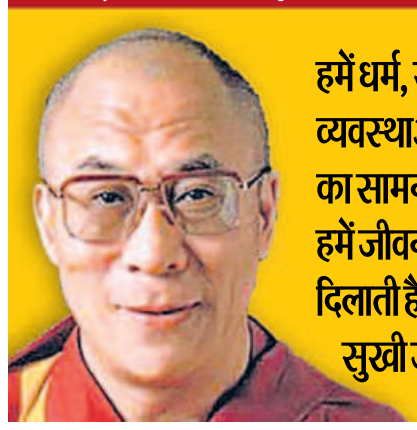

हमें धर्म, राष्ट्रीयता और राजनीतिक व्यवस्थाओं में बंटवारे के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं हमें जीवन की इस गहरी सच्चाई की याद दिलाती हैं कि मानवता की एकता में ही सुखी जीवन का सार है।

नदियों की रक्षा का काम अभी अधूरा

आज (14 मार्च) नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस है, जो नदियों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। नदियां केवल जल की धाराएं नहीं हैं, बल्कि वे मानव सभ्यता की जीवनरेखा हैं। दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुईं। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था, कृषि और अर्थव्यवस्था का आधार भी हैं।

आज बढ़ते प्रदूषण, अनियंत्रित औद्योगीकरण, अवैध खनन, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों का अस्तित्व गंभीर संकट में है। इसी चिंता को वैश्विक स्तर पर सामने लाने और नदियों के संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 14 मार्च को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम 'नदियों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा है' रखी गई है, जो स्पष्ट करती है कि नदियों का स्वास्थ्य सीधे मानव जीवन, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है।

वर्तमान समय में नदियों के सामने सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की लगभग 80 प्रतिशत नदियां किसी-न-किसी रूप में प्रदूषित हो चुकी हैं। भारत में स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, देश की 300 से अधिक नदियों के कई हिस्सों में जल की गुणवत्ता मानकों से नीचे गिर चुकी है। शहरी क्षेत्रों का असंशोधित सीवेज, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रसायन, प्लास्टिक कचरा और कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं।

भारत की लगभग 60 प्रतिशत सिंचाई और लोगों की पेयजल की जरूरत नदियों से पूरी होती है, इसलिए नदियों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि विकास और अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। नदियों के आसपास अतिक्रमण को हटाया जाए, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों को बिना शोधन के नदियों में प्रवाहित करने पर कड़े दंड दिए जाएं और समाज में जल संरक्षण की संस्कृति को मजबूत किया जाए। जब तक नदियों को जीवित इकाई मानकर उनका सम्मान नहीं किया जाएगा, तब तक उनका संरक्षण संभव नहीं होगा। 'नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस' संदेश देता है कि यदि हमें सुरक्षित भविष्य चाहिए, तो नदियों की रक्षा करना अनिवार्य है, क्योंकि नदियों की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

नदियों की सफाई

संरक्षण में अब दिखने लगी सक्रियता

नदियों की सफाई और उसका पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। केंद्र सरकार देश में नदियों के प्रदूषण में कमी लाने के लिए 'नमामि गंगे' कार्यक्रम, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और अटल पुनरुद्धार एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसी योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को समर्थन-सहयोग भी वह दे रही है।

देश भर में नदी प्रदूषण कम करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण, समुदाय और गैर-सरकारी संगठन भी प्रयास कर रहे हैं। नदियों के संरक्षण में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की गई हैं। जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, नगालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नदियों के तट पर आरती, नदी सफाई अभियान, जन जागरण यात्राएं की जाती हैं। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, ताकि बच्चे जागरूक बन सकें।

सामुदायिक भागीदारी और संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' द्वारा डॉल्फिन सफारी, होम स्टे, आजीविका केंद्र जैसे विभिन्न मॉडलों को भी विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, गंगा बेसिन में नदियों की जैव विविधता और स्वच्छता की रक्षा तथा संरक्षण के लिए स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित स्थानीय समुदाय के सदस्यों को गंगा प्रहरियों के रूप में तैनात किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता सम्मेलन के दौरान विश्व पुनरुद्धार की शीर्ष दस प्रमुख पहलों में से एक माना गया है।

पवित्र गंगा के प्रति सम्मान के रूप में 'गंगा उत्सव' मनाया जाता है, जिसमें नदी पुनर्जीवन और पर्यावरण जागरूकता पर जोर दिया जाता है। नदियों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जाते हैं। 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत नदियों की सफाई, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही 'कैच द रेन' जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जो जल प्रबंधन, जल निकायों को पुनर्जीवित करने, जन जागरूकता बढ़ाने, स्थानीय निकायों और समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। यानी, अब संरक्षण को लेकर व्यापक सक्रियता दिखने लगी है।

विभा चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता

कार में फीचर बहुत पर काम के कितने

एक अध्ययन में 70 फीसदी से ज्यादा कार खरीदारों ने ऐसी कारों को प्राथमिकता दी, जो सुविधाओं से लैस हों। हालांकि, इस शौक के चलते कई बार कार में ऐसे गैर-जरूरी फीचर भी शामिल हो जाते हैं, जिससे कार की कीमत बढ़ जाती है। जरूरी है कि अपने लिए जब कार खरीदें, तो फीचर और किफायत का संतुलन बिठाएं।

जो सुविधाएं पहले लग्जरी कारों में मिलती थीं, वे अब आम कारों में भी मिलने लगी हैं। एक दशक पहले जहां किसी मिड-वेरिएंट कार में 12-15 फीचर्स ही होते थे, अब यह बढ़कर 30-35 तक पहुंच गए हैं। डेलॉयट की दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट भारतीय कार खरीदारों की बदलती सोच को दिखाती है। अध्ययन के अनुसार 72 फीसदी भारतीय खरीदार बेहतर तकनीकी फीचर्स के लिए अपने पसंदीदा कार ब्रांड बदलने को तैयार थे। हालांकि, वास्तविकता यह भी है कि इन फीचर्स में से कई का हम शायद ही इस्तेमाल करते हैं। वे अकसर स्टेटस सिंबल बनकर रह जाते हैं।

पसंद अपनी-अपनी

जेडी पावर की बीते साल जारी एक ग्लोबल रिपोर्ट में पाया गया कि कारों में 35 फीसदी ऐसे फीचर्स होते हैं, जिन्हें कार मालिक द्वारा इस्तेमाल किए जाने की संभावना न के बराबर होती है। जैसे जेस्चर कंट्रोल या वॉइस कमांड। लग्जरी कारों में इनका चलन बढ़ा है। नोएडा में अपना फिनटेक चला रहे नमन कहते हैं, 'दुर्घटनाओं के लिहाज से कार में आधुनिक सेफ्टी फीचर्स होना अच्छा है, लेकिन सुविधा के कुछ फीचर्स मुझे झंझट लगते हैं। मुझे टच स्क्रीन की बजाय स्टीयरिंग से मेन्यू कंट्रोल करना सुविधाजनक लगता है। सनरूफ को ही लें-गर्मी के दिनों में मैं सनरूफ खोलने की सोच भी नहीं सकता। क्रूज कंट्रोल अच्छा फीचर है, लेकिन सिटी लाइफ में मुझे इसकी कम ही जरूरत पड़ती है। मुझे डिजिटल के बजाय एनालॉग डैशबोर्ड देखना ज्यादा रोमांचक लगता है।'

सबसे ज्यादा उपयोगी फीचर्स

स्टैटिस्टा के एक कंज्यूमर सर्वे में कार खरीदारों की पसंद के अनुसार सबसे अहम फीचर्स में एअर कंडीशनिंग, अच्छा माइलेज, मजबूत बनावट, सुव्यवस्थित स्टोरेज स्पेस और पर्याप्त ग्राउंड क्लीयरेंस शामिल हैं। ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टिल्ट व टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और फ्रंट फॉग लैंप्स जैसी व्यावहारिक सुविधाएं भी उपभोक्ताओं की प्राथमिकता में रहती हैं। सुरक्षा के लिहाज से एयरबैग्स की बढ़ी हुई संख्या, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और आइसोफिक्स जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग ज्यादा है। वहीं लेवल-2 अडास सूट, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे उन्नत फीचर्स महंगे होते हैं और ज्यादा रखरखाव भी मांगते हैं। औसत ड्राइवर अपनी हर यात्रा में सिर्फ 5-7 फीचर्स का ही सक्रिय उपयोग करता है। इसमें रिवर्स कैमरा और सेंसर, एंड्रॉयड ऑटो या एपल कार प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स प्रमुख हैं।

विश्लेषण करें, तो किसी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी के बेस और टॉप मॉडल के बीच कीमत में अंतर का करीब 60-70% हिस्सा ऐसे फीचर्स के कारण हो सकता है, जो रोजमर्रा इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे। टॉप वेरिएंट में जो कार 15 लाख रुपये तक में आ रही होगी, सिर्फ जरूरी फीचर्स के आधार पर 11-12 लाख रुपये तक में आ सकती है। ज्यादा फीचर्स हों, तो कीमत बढ़ती है और इस आधार पर सालाना बीमा भुगतान भी ज्यादा करना होगा। कई राज्यों में 10 लाख रुपये की कीमत पार करते ही टैक्स का प्रतिशत बढ़ जाता है। कुछ फीचर्स जैसे सनरूफ की देखभाल भी आसान नहीं होती।

सुरक्षा को दें वरीयता

रेसिंग स्पोर्ट्स से जुड़े संगीत भट्ट इस संदर्भ में कहते हैं, 'आप अपनी कार में क्या-क्या चाहते हैं यह एक निजी पसंद का मामला है। हालांकि, किफायत की बात करें तो वाकई में फीचर्स के चक्कर में पड़कर कई बार पूरा सौदा 1 से 2.5 लाख रुपये अतिरिक्त पड़ जाता है। यहां मैं 800 सीसी यानी आल्टो जैसी छोटी कार से लेकर 2500 सीसी यानी स्कॉर्पियो, इनोवा जैसी बड़ी एसयूवी तक की बात कर रहा हूं। ये कारें शहर, हाइवे और पहाड़ी इलाकों तक में लोग ले जाते हैं। यहां पूरी फैमिली की सुरक्षा का सवाल है। सेफ्टी फीचर्स में एअरबैग्स, कार का अच्छा सस्पेंशन, अच्छी सुरक्षा रेटिंग, माइलेज और एबीएस जैसे फीचर्स तो बेसिक हैं और इन्हें जरूर लें। पार्किंग कैमरा का फीचर जरूरी है। इसमें 4के कैमरा और उसके लिए दी गई स्क्रीन का रिजॉल्यूशन अच्छा हो। पीछे की स्क्रीन केलिए डीफॉगर अहम है और आजकल आ रहा ब्लाइंड स्पॉट मॉनीटरिंग सिस्टम भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि एक आम परिवार की कार में कई बार इतने लोग बैठे होते हैं कि हर जगह देख पाना ड्राइवर के लिए आसान नहीं होता। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है रियर सीटबेल्ट। इसे कार में जरूर होना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी लोगों को जरूर करना चाहिए। भारत में लोगों को इसकी आदत अभी नहीं है।'

संगीत भट्ट कार में सेफ्टी के लिहास से अडास सूट को एक अच्छा सौदा मानते हैं। उनके शब्दों में, 'सरकार जल्द ही लेवल वन अडास को कारों में अनिवार्य करने वाली है। कार में इसके फीचर हों, तो अच्छा होगा। वहीं, कारों में जरूरी फीचर हो गया है ट्यूबलेस टायर। हाइवे की यात्रा में हैं, तो इसमें नाइट्रोजन जरूर डलवाएं। टायर मॉनीटरिंग सिस्टम भी बेहद उपयोगी फीचर है।'

प्रतिमा पांडेय

कार खरीदारों के लिए

एचटी ऑटो के एक लेख के अनुसार भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में आधुनिक फीचर्स छाए हुए हैं, जिससे खरीदारों के लिए सही विकल्प चुनना चुनौतीपूर्ण हो गया है। विशेष रूप से पहली बार कार खरीदने वालों के लिए ईएसपी, इमोबिलाइजर और अडास जैसे तकनीकी शब्द भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। छह एअरबैग सबसे जरूरी हैं। इसके साथ ही पहली बार कार खरीदने वालों के लिए निम्नलिखित फीचर्स भी बेहद उपयोगी हैं :

- **इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) :** यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर है, जो अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में कार को फिसलने या नियंत्रण खोने से बचाता है। यह एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ मिलकर काम करता है।
- **रियर पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट और थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट :** हेडरेस्ट गर्दन को झटके से बचाता है, जबकि थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट टक्कर की स्थिति में यात्रियों को सीट पर सुरक्षित रखती है।
- **पावर स्टीयरिंग :** यह ड्राइविंग को आसान बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से असिस्टेड होने के कारण, कार को मोड़ने या चलाने में बहुत कम शारीरिक मेहनत लगती है।
- **इंजन इमोबिलाइजर के साथ सेंट्रल लॉकिंग :** सेंट्रल लॉकिंग से सभी दरवाजे एक साथ लॉक हो जाते हैं, जिससे चोरी का खतरा कम होता है। इंजन इमोबिलाइजर से कार इंजन को कोई अन्य ऑन नहीं कर पाएगा।
- **फॉग लाइट्स :** ये लाइटें कोहरे के दौरान दृश्यता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं, खासकर भारत जैसी जलवायु परिस्थितियों में जहां भारी कोहरा सामान्य बात है। इन्हें बाद में एक्सेसरी के रूप में भी बाहर से लगवाया जा सकता है।

भीड़ भरी सड़कों पर बहुत कारगर छोटी ई-कारें

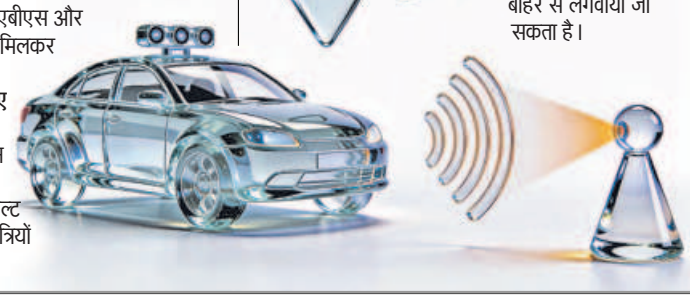

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से प्रचलन में आ रहे हैं, खासकर शहरों में रोजमर्रा की आवाजाही के लिए। यहां कुछ कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों की चर्चा की गई है, जो छोटे आकार और अच्छी रेंज के साथ शहरी यातायात के लिए उपयुक्त विकल्प बन रही हैं

कार बाजार

शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और सीमित पार्किंग के बीच छोटी इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सुविधाजनक साबित हो रही हैं। इसलिए कॉम्पैक्ट ई-कारें सिटी ड्राइव के लिए लोकप्रिय हो रही हैं। एचटी ऑटो के अनुसार सूची में शामिल ये पांच कारें आपकी भी पसंद बन सकती हैं-

एमजी कॉमेट ईवी : रहें किफायती

एमजी कॉमेट ईवी देश की सबसे छोटी कारों में से एक है और इसकी कीमत बैटरी-एज-ए-सर्विस के साथ मात्र 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है। यह कार सिर्फ 2974 एमएम लंबी है और 2010 एमएम व्हीलबेस के साथ आती है, जो तंग जगहों में आसानी से मुड़ सकती है। 17.3 केडब्लूएच बैटरी और 41 बीएचपी मोटर के साथ यह एक बार चार्ज में लगभग 230 किमी चल सकती है।

टाटा पंच ईवी : दो बैटरी विकल्प

कॉम्पैक्ट साइज और आधुनिक फीचर्स के साथ टाटा पंच ईवी शहर की भीड़भाड़ में ड्राइविंग करना आसान बनाती है। इसमें दो बैटरी विकल्प हैं - छोटी बैटरी वाला मॉडल एक बार चार्ज में करीब 275 किमी तक चलता है और बड़ी बैटरी वाला मॉडल करीब 355 किमी तक की दूरी तय कर सकता है। कार में फ्रंट वेंटिलेशन, वॉइस-सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और एअर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स भी हैं। कीमत 9.69 लाख से शुरू है।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक : रेंज में आगे

यह प्रीमियम और कॉम्पैक्ट एसयूवी दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है: 51.4 केडब्लूएच की बड़ी बैटरी 169 बीएचपी पावर देती है और लगभग 473 किमी की रेंज प्रदान करती है, जबकि 42 केडब्लूएच बैटरी 390 किमी तक चलती है। इंटीरियर में दो 10.25इंच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 अडास और 360डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं हैं। कीमत 18.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

विंडसर ईवी : दमदार एसयूवी

एमजी विंडसर ईवी शहर और हाईवे दोनों के लिए एक दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इस कार की लंबाई 4295 एमएम और व्हीलबेस में 2700 एमएम है, जिससे ड्राइविंग और पार्किंग दोनों आसान हैं। लगभग 332 किलोमीटर की रेंज देती है और 15.6 इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसी खूबियों से भरी है। बैटरी-एज-ए-सर्विस कीमत 9.99 रुपये से शुरु है।

सिट्रोएन ईसी3 : फीचर से भरपूर

शहर की ट्रैफिक और सीमित पार्किंग में चलाने के लिए सिट्रोएन ईसी3 बढ़िया विकल्प है। एक बार चार्ज में करीब 320 किमी चल सकती है। इसमें टच स्क्रीन, फोन कनेक्शन, स्टीयरिंग कंट्रोल और आरामदायक ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स हैं। कीमत 12.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है।

- फीचर डेस्क

स्कूटर या बाइक : किफायत में कौन बेहतर

दोपहिया में स्कूटर और मोटरसाइकिल का मुकाबला अकसर होता है। अगर आपको लगता है कि माइलेज में स्कूटर मोटर-साइकिल पर भारी पड़ता है, तो आइए जानते हैं कुछ जरूरी तथ्य

दोपहिया

ईंधन की खपत का सीधा संबंध वाहन पर होने वाले खर्च से होता है। स्कूटर की माइलेज मोटरसाइकिल से कम होती है, इसके बावजूद, युवाओं, महिलाओं और विभिन्न कूरियर व डिलीवरी पार्टनर्स के बीच स्कूटर लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हर टू-व्हीलर निर्माता इस सेगमेंट में हिस्सेदारी चाहता है। हालांकि, स्कूटर की माइलेज कम होना लंबी अवधि में ज्यादा खर्च का कारण बनता है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं -

सीवीटी के कारण ईंधन खपत ज्यादा

स्कूटर में सीवीटी (कॉन्टिन्यूअसली वैरिएबल ट्रांसमिशन) होता है, जिससे यह उच्च आरपीएम रेंज में रहता है और ईंधन खपत ज्यादा होती है। इसके विपरीत मोटरसाइकिल में मैनुअल गियरबॉक्स होता है, जिससे राइडर आरपीएम नियंत्रित कर उच्च गियर में कम आरपीएम पर चलाकर बेहतर माइलेज पा सकता है, जो स्कूटर में संभव नहीं है। इस तरह स्कूटर की फ्यूल इकोनॉमी को सीवीटी प्रभावित करती है।

ईंधन टैंक का आकार भी रखता मायने

मोटरसाइकिल की तुलना में स्कूटर का फ्यूल टैंक छोटा होता है, इसलिए एक बार भरने पर दूरी कम तय होती है और लंबी दूरी के सफर में इसे बार-बार भरवाना पड़ता है। वहीं, मोटरसाइकिल में बड़ा ईंधन टैंक होने के कारण यह एक बार में लंबी दूरी तय कर सकती है, जिससे ईंधन में किफायत का अहसास बढ़ता है।

चलाने का तरीका और माइलेज

ईंधन की खपत केवल वाहन पर नहीं, बल्कि राइडर के स्टाइल पर भी निर्भर करती है। मैनुअल गियर वाली मोटरसाइकिल में कुशल राइडर गियर को सही ढंग से संभालकर बेहतर माइलेज पा सकता है। वहीं, स्कूटर का ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन कुछ परिस्थितियों में ईंधन के लिए कम कुशल साबित होता है। स्कूटर आमतौर पर शहर में कम्यूटिंग के लिए बनाए जाते हैं, जबकि मोटरसाइकिल लंबी दूरी के सफर के लिए बेहतर हैं। शहर की ट्रैफिक में बार-बार स्टार्ट-स्टॉप भी माइलेज पर असर डालते हैं।

mint

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मसंयत रहें। शांति बनाए रखने का प्रयास करें। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। मान-सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है।

वृष : मन परेशान हो सकता है। धैर्य बनाए रखें। सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

मिथुन : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में नकारात्मक विचारों से भी बचें। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

कर्क : मन में निराशा और असंतोष हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में भी कठिनाई आ सकती है, परंतु कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी।

सिंह : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, परंतु आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं।

कन्या : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। परिवार में मान-सम्मान में वृद्धि होगी। सेहत का भी ध्यान रखें।

तुला : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। सुस्वादु खान-पान में भी रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। भवन सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा।

धनु : मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में बढ़ोतरी होगी।

मकर : मन परेशान हो सकता है। धैर्य धारण करें। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं।

कुंभ : किसी अज्ञात भय से मन परेशान हो सकता है। आत्म-संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं।

मीन : मन शांत रहेगा। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

14 मार्च, शनिवार, **शक संवत्:** 23,फाल्गुन, सौर शक 1947, **पंजाब पंचांग :** 01, चैत्र मास प्रविष्टे 2082 **इस्लाम :** 24, रमजान, 1447 **विक्रमी संवत** चैत्र कृष्ण दशमी तिथि प्रात : 08.11 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 04.49 मिनट तक पश्चात श्रवण नक्षत्र, विष्टि (भद्रा) करण प्रात : 08.11 मिनट तक। चन्द्रमा धनु राशि में प्रात : 09.33 मिनट तक, उपरांत मकर राशि। **सूर्य उत्तरायण।** प्रात : 09 बजे से प्रात : 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रात : 08.11 मिनट तक। चैत्र संक्रान्ति।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि यदि हमारा मुख्य द्वार गलत दिशा में बन गया है और हम उसे बदल नहीं सकते तो अब क्या उपाय करने चाहिए? - यशस्वी नागर, नई दिल्ली

- आप सुबह को स्नान करके अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर जाएं।
- फिर उस पर थोड़ा साफ जल छिड़कें। उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। उसके बाद जल में थोड़ी हल्दी डालकर चौखट पर छिड़कें। फिर चौखट के दाएं ओर शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं।
- चौखट के दोनों और एक-एक फूल रखें। उसके बाद वहां पर धूप या अगरबत्ती जलाएं।
- यदि संभव हो, तो वहां पर एक मिसरी का दाना भी रख दें।

वर्ग पहेली : 8267

■	1	2		3	■	4	■	5
6	■		■	7				
8				■	■		■	
	■		■	9	■	■	10	
	■	11				12	■	
13		■	■		■		■	
	■	14	■	■	15			
16				17	■		■	
	■		■	18				■

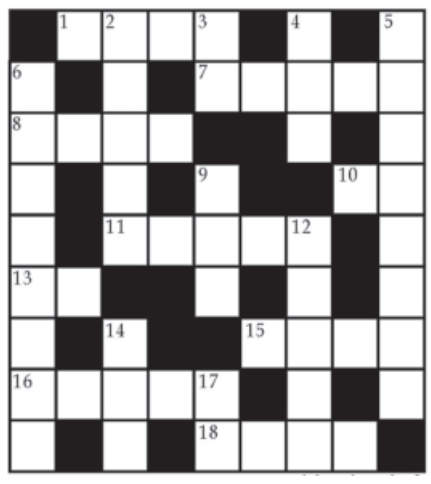

बाएं से दाएं
1. अंधियारी रात; कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि; अमावस्या (4)
7. नाम मात्र के लिए; दिखावे के तौर पर (5)
8. एक फल; मकोय; रस से भरी (4)
10. एक मीठा रसीला फल; सामान्य; साधारण; मामूली (2)
11. आश्लेषा नक्षत्र; नागों में अनंत आदि आठ प्रमुख सर्प (5)
13. मेख; मुहांसे का अंश (2)
15. कार्यारंभ की पहली अवस्था; प्रथमारंभ; तैयारी; योजना (4)
16. धुआं खींचना; चिलम का कश लेना (2,3)
18. किसी अधिकारी के पद का सूचक (4)

ऊपर से नीचे
2. पीट कर भगाना; हराना (2,3)
3. सभी; समस्त; सारा (2)
4. गाने वाला (3)
5. पूरी तरह से छा जाना; सब जगह होना; सर्वत्र व्याप्त होना (2,2,1,3)
6. अल्पकालीनता; थोड़े समय का सुख; सुख की अल्पावधि (2,2,1,3)
9. सिरा; कूल; तीर; तट (3)
12. उग्र होना; कठोरता अपनाना; सख्त होना; दृढ़ता दिखाना (2,3)
14. न्यारा; पृथक; भिन्न (3)
17. परिमाण; पैमाना; मानदंड; माप (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8266

■	1 प	2 र	लो	क	3 सि	धा	4 र	ना
5 रं	■	सो	■	■	रा	■	त	■
6 ग	ले	प	ड़	7 ना	■	8 र	ज	9 त
उ	■	ल	■	मु	■	■	10 गा	र
त	■	■	11 दा	म	न	■	■	क्की
12 र	13 न	■	■	कि	■	14 वी	■	क
15 ना	ट	क	■	16 न	ग	र	द्वा	र
■	ख	■	17 खा	■	■	र	■	ना
18 घ	ट	घ	ट	मे	ब	स	ना	■

सुडोकू : 8249

*आसान

	4	7	5		2	1	6	
		5				7		
	3						5	
		4	2		9	5		
6	2						8	3
		8	6		3	2		
	9						4	
		6				9		
	1	3	9		8	6	2	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8248

9	4	2	5	6	7	3	8	1
7	8	6	9	1	3	2	5	4
5	1	3	8	4	2	7	9	6
1	2	4	6	5	8	9	3	7
6	9	8	7	3	1	5	4	2
3	7	5	2	9	4	6	1	8
4	5	7	1	2	9	8	6	3
2	3	9	4	8	6	1	7	5
8	6	1	3	7	5	4	2	9

संपादकीय जागरण

शनिवार, 14 मार्च, 2026 : चैत्र कृष्ण – 10 वि. 2082

दुख हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है

राजनीतिक दीवालियापन

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मिली पराजय के बाद विपक्ष ने जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दिया, वह उसके राजनीतिक और साथ ही बौद्धिक दीवालिएपन का ही परिचायक है। यह लगभग तय है कि संख्याबल के अभाव और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जटिल एवं लंबी प्रक्रिया के चलते विपक्ष की यह पहल सफल नहीं होने वाली, फिर भी यदि वह ऐसा कर रहा है तो जाहिर है कि खबरों में आने और यह शोर मचाने के लिए कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के जरिये उसके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा ही शोर बिहार में एसआइआर के समय मचाया गया था, पर सब जानते हैं कि चुनावों में विपक्ष को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट न जाने कितनी बार कह चुका है कि एसआइआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और वह इस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देने वाला। जिस तृणमूल कांग्रेस को एसआइआर पर सबसे अधिक आपत्ति है और जिसकी पहल पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट से केवल निराशा ही हाथ नहीं लगी है, बल्कि उसकी फटकार का भी सामना करना पड़ा है।

लगता है तृणमूल कांग्रेस इससे खीझी है कि एसआइआर पर बंगाल प्रशासन की अड़ंगेबाजी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बंगाल प्रशासन की निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाला ही है। यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल में एसआइआर को लेकर और सुनवाई करने के मूड में नहीं है। इसका अर्थ है कि वहां जारी एसआइआर में कोई गड़बड़ी नहीं। यदि इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह सोच रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की उनकी कोशिश उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ प्रदान करेगी और वे देश की जनता का ध्यान खींचने में सफल हो जाएंगे तो यह एक तरह का दिवास्वप्न ही है। यदि विपक्ष की यह योजना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित कर वह चुनाव आयोग को लांछित करने में सफल हो जाएगा तो इसे भी उसकी एक गैर जरूरी राजनीतिक कवायद ही कहा जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हाल के वर्षों में आयोग के प्रति न केवल देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि उसने अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी हासिल की है। झूठे आरोपों के सहारे एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करना राजनीतिक आत्मघात के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस समेत जो कई विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं, वे इसी आयोग की ओर से कराए गए चुनावों के जरिये ही सत्ता में हैं।

उचित निर्णय

दिल्ली में चांदनी चौक पुनर्विकास योजना में भ्रष्टाचार की जांच कराने संबंधी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निर्देश सर्वथा उचित है। शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी) की बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस परियोजना की लागत लगभग 65 करोड़ रुपये बताई गई थी, वह बढ़कर करीब 148 करोड़ रुपये हो गई। उनका कहना था कि उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें उस समय के बोर्ड के चेयरपर्सन एवं संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। इन सभी अनियमितताओं की जांच की जाएगी।

> चांदनी चौक का योजनाबद्ध तरीके से पुनर्विकास कराया जाए, ताकि ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे

चांदनी चौक पुनर्विकास योजना सफल नहीं रही, यहां सुंदरीकरण के लिए जो प्रयास किए गए वो भी उचित योजना न होने के कारण सफल नहीं हो सके। ऐसे में ये आवश्यक है कि शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम द्वारा कराए गए कार्यों की जांच की जाए और संबंधित अधिकारियों व बोर्ड पदाधिकारियों को जांच के दायरे में लाया जाए। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली की अमूल्य विरासत है। दिल्ली की भाजपा सरकार को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से इसका पुनर्विकास कराना चाहिए, ताकि ये क्षेत्र भविष्य में भी दुनियाभर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा वाले प्रस्ताव का समर्थन करके सही किया?

आज का सवाल

क्या एनसीईआरटी पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला पाठ तैयार करने वालों पर पाबंदी सही है?

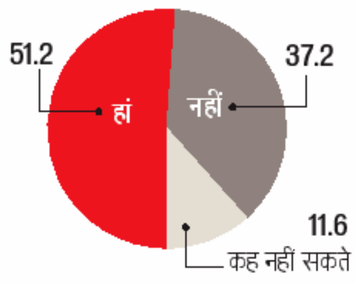

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

संवेदनशील बने न्यायिक तंत्र

ऋतु सारस्वत

कई बार न्यायपालिका की औपचारिक प्रक्रिया के बीच वह पीड़ा अनकही रह जाती है, जो पीड़िता के हिस्से में आती है

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद कर दिया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो) के एक मामले में समन के महत्व को कम कर दिया गया था। जज सूर्यकांत, जायमाल्य बागची और एनवी अंजारी की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के मूल समन आदेश को बहाल किया और कहा कि प्रथमदृष्ट्या आरोपों से दुष्कर्म करने का “प्रयास” प्रतीत होता है, न कि केवल “तैयारी”। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक संवेदनशीलता के नवीन मानकों को स्थापित करते हुए यौन अपराधों के मुकदमों में अधिक संवेदनशील और एकसमान न्याय-निर्णय के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। इन निर्देशों को जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लैंगिक रूढ़ियों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 में जारी की गई हैंडबुक को रद कर दिया। उक्त मामला 17 मार्च, 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय से संबंधित है, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट के समन को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दुष्कर्म के आरोप से घटाकर धारा 354 बी के तहत “वस्त्र उतारने के इरादे से हमला” कर दिया था। इसके साथ ही पोक्सो के संबंधित प्रविधानों को भी धारा 18 से घटाकर धारा 10 कर दिया गया था, जिसमें आजीवन कारावास की आधी सजा का नियम है, जबकि धारा 18 में 5-7 वर्ष के कारावास का प्रविधान है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि देश की विभिन्न अदालतों में संवेदनशीलता को लेकर बरती जाने वाली सावधानी में कहीं न कहीं चूक हो जाती है, इसीलिए उसने यह कार्य प्रशिक्षण प्रणाली को सौंप दिया तथा भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आग्रह किया। समिति को भाषाई विविधता और आम लोगों के लिए सुगम्यता का ध्यान रखते हुए एक व्यापक रिपोर्ट और दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करने को कहा गया है। न्यायालय का इस पर विशेष जोर था कि समिति प्रतिवेदन तैयार करते समय राष्ट्र की भाषाई विविधता को ध्यान में रखे। उसने यह भी इंगित किया कि विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों में प्रचलित अनेक ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां हैं, जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती हैं, पर वे दंड विधि के तहत आपत्तिजनक या अपराध की श्रेणी में आ सकती हैं। अतः समिति का यह दायित्व होगा कि वह विभिन्न भाषाओं के ऐसे शब्दों की पहचान कर उनका संकलन करे, ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया में अनदेखे न रह जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति से इस विषय पर एक समग्र रिपोर्ट तैयार करने को कहा कि यौन अपराध के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता कैसे विकसित की जाए। इससे पूर्व ‘अपर्णा भट बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 18 मार्च, 2021’ मामले में शीर्ष न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से कहा था कि वह युवा न्यायाधीशों के प्रशिक्षण और न्यायाधीशों की सतत शिक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित आवश्यक सामग्री को शीघ्रता से तैयार करे, जिसमें न्यायिक तर्क में अंतर्निहित रूढ़ियों और अचेतन पूर्वाग्रहों के प्रति पर्याप्त जागरूकता कार्यक्रम शामिल हों।

अवधेश राजपूत

सुप्रीम कोर्ट लगातार देश की विभिन्न अदालतों द्वारा यौन अपराधों के मामलों में प्रदर्शित संवेदनात्मक कमी और रूढ़िगत दृष्टिकोण पर आपत्ति व्यक्त करता रहा है। हालिया निर्णय में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी चिंता को दोहराते हुए कहा, ‘हमारे सभी निर्णयों में करुणा, मानवता एवं समझ की भावना झलकनी चाहिए। यही तत्व एक निष्पक्ष एवं प्रभावी न्यायप्रणाली के निर्माण के लिए जरूरी हैं।” यह टिप्पणी सिर्फ एक न्यायिक अवलोकन भर नहीं, संवेदनशील न्यायशास्त्र की दिशा में किया गया एक सशक्त और ऐतिहासिक हस्ताक्षर है। यह यौन शोषण से गुजरी पीड़िता के लिए आश्वस्ति और सहानुभूति का संदेश देती है। एक ऐसा ही संदेश हाल में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने तब दिया, जब उसने कहा कि यौन अपराधों में सेक्सुअल इंटेंट यानी यौन मंशा सबसे महत्वपूर्ण है। उसने यह भी कहा कि किसी लड़की के शरीर के ऊपरी हिस्से को छूना, दबाना और खींचना यौन उत्पीड़न है।

निःसंदेह यौन अपराध की यातना को उसकी संपूर्ण गहराई में वही समझ सकता है, जिसने उस आघात को अपने जीवन में भोगा हो। न्यायपालिका की यह मानवीय दृष्टि न केवल विधिक प्रक्रिया को अधिक करुणामय और उत्तरदायी बनाती है, बल्कि पीड़ितों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और गरिमा की भावना को भी पुनर्जीवित करती है। यह कथन उल्लेखनीय है कि “यौन अपराध की यातना को गहराई से वही समझ सकता है, जिसने उसे भोगा हो।” इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि न्यायपालिका की जटिल और औपचारिक शब्दावलियों के बीच कई बार वह मानवीय पीड़ा अनकही रह जाती है, जो वास्तव में पीड़ित के हिस्से में आती है। विधिक तर्क अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, परंतु वे हमेशा उस आंतरिक टूटन, भय और आत्मसम्मान पर पड़े आघात को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाते। मैं यह बात केवल सैद्धांतिक आधार पर नहीं कह रही, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर कह पा रही हूं। लगभग 15 वर्ष पूर्व एक सर्द रात को टहलते समय अंधेरे में अचानक एक अजनबी पुरुष ने सामने आकर मुझे स्पर्श किया और पल भर में ओझल हो गया। वह क्षणिक था, पर उसका प्रभाव दीर्घकालिक रहा। उस दिन के बाद से आज तक मैं सड़क पर पैदल चलते हुए सहजता का अनुभव नहीं कर पाती। यदि कभी चलना भी पड़े तो मेरी दृष्टि सामने से अधिक पीछे की ओर रहती है, जैसे भय ने मेरे आत्मविश्वास के स्थान पर स्थायी निवास बना लिया हो।

जब कोई समर्थ, शिक्षित महिला केवल एक अनचाहे स्पर्श से वर्षों तक अपने भीतर असुरक्षा ढो सकती है, तो यह कल्पना सहज ही की जा सकती है कि वे बच्चियां, जो यौन शोषण जैसी गंभीर त्रासदी का सामना करती हैं, उनमें आत्मसम्मान, विश्वास और सुरक्षा की भावना किस गहराई तक आहत होती होगी। अतः यह केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, न्यायिक दायित्व का अनिवार्य विस्तार है कि संपूर्ण न्यायिक तंत्र यौन पीड़िताओं के लिए ऐसा परिवेश निर्मित करे, जो संवेदनशील, करुणामय एवं संरक्षात्मक हो।

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)

response@jagran.com

सवालों के घेरे में सिविल सेवा परीक्षा

देश के सर्वोच्च प्रशासनिक ढांचे के लिए अफसरों की भर्ती करने वाली संस्था यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के हालिया परिणामों ने पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हलचल पैदा की है। पहले दो दिनों तक सफल उम्मीदवारों में एक ही नाम की दो आकांक्षा सिंह को लेकर खबरें चर्चा में रहीं। इस मामले की जांच के बीच एक अन्य अभ्यर्थी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें 2024 में सामान्य वर्ग से भारतीय पुलिस सेवा मिली थी, पर 2025 में उन्होंने अपना वर्ग सामान्य के बजाय ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) घोषित कर दिया। आइपीएस बनने के बाद ऐसा कैसे संभव है? पिछले पांच वर्षों में ऐसे कई मामले यूपीएससी, अदालतों और कार्मिक मंत्रालय के सामने आ चुके हैं। कहीं न कहीं नियमों में लचीलेपन, स्पष्टता का अभाव और स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। तीन वर्ष पहले महाराष्ट्र की पूजा खेडकर का मामला भी सामने आया था, जिसमें आरोप लगा कि उन्होंने कई नियमों की अनदेखी करते हुए आइएएस सेवा प्राप्त की।

प्रेमपाल शर्मा

नियमों में लचीलेपन और स्पष्टता के अभाव का असर यूपीएससी के परिणाम पर भी पड़ रहा है

स्वजन के साथ यूपीएससी टापर अभ्यर्थी ● प्रेट्र

फर्जी एससी-एसटी प्रमाणपत्रों से जुड़े भी अनेक मामले यूपीएससी के सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि हाल में यूपीएससी ने इन गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके। इस बार के परीक्षा परिणाम में एक और तथ्य ने ध्यान खींचा। वह है आदिवासी कोटे में 73 में से एक जनजाति के करीब 30 प्रतिशत अभ्यर्थियों का चयन। ऐसे छात्र, जो दिल्ली जैसे महानगरों में पैदा हुए, आधुनिक सुविधाओं के बीच पले-बढ़े और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़े, यदि आदिवासी कोटे का लाभ ले रहे हैं तो क्या वे उन सैकड़ों जरूरतमंद आदिवासियों का हक नहीं छीन रहे, जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। इस बार भी अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच असमानता का प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का चयन मुश्किल से पांच प्रतिशत तक ही सीमित क्यों रह जाता है, जबकि लगभग 95 प्रतिशत चयन अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवारों का होता है? इस बार इंटरव्यू के अंकों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा 1,750 अंकों की होती है, जबकि इंटरव्यू के लिए 275 अंक निर्धारित हैं। इस बार के परिणामों के आंकड़े बताते हैं कि लिखित परीक्षा में टापर्स सहित किसी के भी 50 प्रतिशत से अधिक अंक नहीं आए, लेकिन इंटरव्यू में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक है। 275 में से 200 या उससे अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक है। जिस परीक्षा में एक-एक अंक उम्मीदवारों के भविष्य का निर्धारण करता हो, वहां यूपीएससी के इस प्रकार के परिणाम स्वाभाविक रूप से कई गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं।

इस बार का टापर उम्मीदवार एमबीबीएस डाक्टर है। प्रश्न है कि ऐसे डाक्टर लगातार सिविल सेवाओं की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं, जबकि विश्व के कई देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति डाक्टरों की उपलब्धता अभी भी बहुत कम है। पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं न होने के कारण देश की एक बड़ी आबादी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह भागीदारी नहीं कर पाती। इसी तरह आइआइटी जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों से पढ़े हुए छात्र भी पिछले लगभग दो दशकों से बड़ी संख्या में सिविल सेवाओं की ओर रुख कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास कर आइआइटी जैसे संस्थानों में प्रवेश पाने वाले अनेक छात्र सिविल सेवा परीक्षा में अपने मूल विषय इंजीनियरिंग को वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं चुनते। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत एंथ्रोपोलाजी, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषयों को चुनते हैं। कई बार वे संस्कृत, मैथिली या अन्य भारतीय भाषाओं को भी वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं। यह प्रवृत्ति सिविल सेवा परीक्षा की संरचना और विषय चयन की प्रकृति को लेकर भी कई प्रश्न खड़े करती है। ये सभी प्रश्न नए नहीं हैं, लेकिन अब उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया है।

किसी भी जीवंत समाज के लिए प्रश्न उठाना और उन पर गंभीर चर्चा करना आवश्यक होता है। यह देश के शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन प्रश्नों के हल के लिए ठोस पहल करे। बेहतर होगा कि 1979 में गठित दौलत सिंह कोठारी समिति द्वारा तैयार प्रशासनिक सेवाओं के ढांचे की व्यापक समीक्षा की जाए। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई व्यवस्था आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ लागू है, इसलिए समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि सफल उम्मीदवारों में कार्य के प्रति निष्ठा, सादगी, ईमानदारी और सच्चे जनसेवक बनने की भावना कैसे विकसित की जाए। यह कार्य आसान नहीं है, फिर भी यूपीएससी की प्रतिष्ठा और प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।

(लेखक भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परिवर्तन की राह

परिवर्तनशीलता जगत का शाश्वत नियम है। युगीन सभ्यताएं सदैव परिवर्तनशील रही हैं। कितनी सभ्यताओं का जन्म हुआ और कितनी काल के गर्त में समा गईं। सतत प्रक्रिया होने पर भी सामाजिक हित में परिवर्तन की राह आसान नहीं होती। प्रगतिशीलता के इस दौर में इतनी अपेक्षा अवश्य की जाती है कि सुशिक्षित और बुद्धिमान नेतृत्व की अगुआई में परिवर्तन अधोगामी न होकर ऊर्ध्वगामी हो, जिससे विकास यात्रा विनाश में परिवर्तित न हो सके। हमारा शरीर अपरिमित ऊर्जा का भंडार है। इसे नव सृजन में व्यय होना चाहिए, विध्वंस में नहीं। यह तभी संभव है जब परिवर्तन का उद्देश्य मंगलकारी हो। यद्यपि प्रकृति भी परिवर्तन करती है, किंतु अधिकांश परिवर्तन मानव के अधीन हैं। सभी सामाजिक परिवर्तन मानव की रचनात्मक क्रियाशीलता और पवित्र मनोदशा पर निर्भर करते हैं।

पूर्व अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, “दुनिया में परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है।” यदि मानव चाहे तो अपने ज्ञान से धरती पर स्वर्ग का अवतरण करा सकता है, किंतु शिक्षा यदि विवेक और विनय की जन्मदात्री नहीं होगी तो परिणाम भी अच्छे नहीं हो सकते। आज विज्ञान एवं टेक्नोलाजी के क्षेत्र में विलक्षण प्रगति के बावजूद वैश्विक संघर्ष और युद्ध का उन्माद शिक्षा पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। इसका समाधान भारतीय शिक्षा और दर्शन में है। महान शिक्षाविद् डा. राधाकृष्णन के अनुसार, ‘विद्यालय और विश्वविद्यालय मात्र बौद्धिक ज्ञान के मंदिर नहीं, अपितु चरित्र निर्माण की उत्कृष्ट पाठशाला हैं।” जहां उच्च आदर्श वाले महापुरुषों का निर्माण होता है, किंतु यह आध्यात्मिक ज्ञान के बिना संभव नहीं। यही आत्म विकास का आधार है। इसीलिए महर्षि अरविंद बौद्धिक ज्ञान की अपेक्षा आत्मिक विकास को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। इसके बिना सर्वजनहिताय की संकल्पना पूरी नहीं हो सकती।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

बेरोजगारी का समाधान

प्रमथ राज सिन्हा का लेख ‘सरकार के हाथ मजबूत करे निजी क्षेत्र’ बेरोजगारी के समाधान के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर बल देता है। इसी दिशा में सरकार युवाओं के कौशल विकास और करियर को नई दिशा देने के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना लेकर आई है। इसके तहत देश की बड़ी कंपनियों को दायरे में लाया गया है, जहां युवाओं को काम सीखने के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि युवा प्रशिक्षण पाकर या तो स्वयं का व्यवसाय शुरू करें या संबंधित कंपनी में रोजगार प्राप्त कर सकें। यद्यपि यह योजना कागजों पर प्रभावशाली है, किंतु इसकी सफलता कंपनियों के ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। सबसे बड़ा प्रश्न ग्रामीण युवाओं की पहुंच का है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में, जहां सभी को सरकारी नौकरी देना असंभव है, युवाओं को कृषि और स्वरोजगार की ओर भी देखना होगा। कृषि, मत्स्य पालन और डेरी उद्योग जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। स्वरोजगार की सबसे बड़ी बाधा पूंजी का अभाव है। सरकारी ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अधिकांश युवा दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते निराश हो जाते हैं। सरकार को चाहिए कि ऋण वितरण को भ्रष्टाचार मुक्त और सुलभ बनाया जाए। हर गांव में मत्स्य पालन और आधुनिक दूध डेरियों के लिए विशेष पैकेज जारी किए जाएं। यदि ग्रामीण स्तर पर अनाज, मछली और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ता है तो निर्यात के माध्यम से न केवल युवाओं की आय बढ़ेगी, बल्कि सरकारी खजाना भी समृद्ध होगा। यदि सरकारें कृषि-आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दें और बुनियादी ढांचा गांवों तक पहुंचाएं तो बेरोजगारी की लंबी होती कतारों को कम किया जा सकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सिलिंडर की कालाबाजारी

केंद्र सरकार के इशारे पर पेट्रोलियम मंत्रालय के दिशानिर्देशों से एनसीआर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडरों के वितरण पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश के क्रियान्वयन से दिल्ली एवं नोएडा के आसपास के इलाकों में लाखों पीएनजी उपभोक्ता एवं कई हजार एमएसएमई इकाइयों के लिए सिलिंडरों की आपूर्ति में कमी होना भारी परेशानी का विषय बन गया है। पश्चिम एशिया में वैश्विक तनाव के कारण गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। हालांकि आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं अस्पतालों, सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों आदि को इस रोक से छूट दी गई है। मांग के अनुरूप आपूर्ति के संतुलन में भारी अंतर होने के कारण गैस के व्यापार से जुड़े एक वर्ग ने कालाबाजारी शुरू कर दी है, जो कि गैरकानूनी, अनैतिक एवं समाज विरोधी कदम माना जाना चाहिए। कृत्रिम अनुपलब्धता उत्पन्न करने वाले चोरी और सीनाजोरी करते हैं तो वे दंड के भागीदार होने चाहिए। इस समय तो अधिक संतुलन की आवश्यकता है, ऐसे में लोगों को भी संयम दिखाना चाहिए।

–युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

नकारात्मक राजनीति पर प्रहार

कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टारगेट करना खासकर कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य लगा। लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के आरोपों पर आरोप लगाने के बजाय आरोपों का जिस तरह से सुस्पष्ट, पारदर्शी और अकाट्य तथ्यों से जवाब दिया, निस्संदेह ऐसा कोई राजनीतिक पंडित या कहें राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सदन में भूमिका निभाई, अतिशयोक्ति नहीं होगी। सकारात्मक तथ्यों की राजनीति से लबरेज गृहमंत्री के बंकर ब्लास्टर भाषण ने विपक्ष को असहज ही नहीं किया, वरन ना बोलने देने वाले अनर्गल एजेंडे को तहस-नहस कर बखिया ही उधेड़ दी। इसीलिए विपक्षी दलों ने गृहमंत्री के भाषण के दौरान हूटिंग, शोर-शराबे, असभ्यता, असहनशीलता आदि का अपरिपक्व परिचय दिया। वहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक स्वयंभू कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और उनके प्रमुख नेतागण दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू स्थित कोर्ट के बिना ट्रायल चलाए फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां व नया आदेश आप नेताओं को एकबार फिर से असहज और किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। हास्यास्पद है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को अनर्गल रूप से प्रो-भाजपा बताकर दूसरे जज के पास केस स्थांतरित करवाने की मांग कर रही है।

–दीपक गौतम, सोनीपत।

पोस्ट

पिछले 24 घंटों में विभिन्न राज्यों में छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में जमाखोरी किए गए एलपीजी सिलिंडरों को जब्त किया गया है। ये केवल वे मामले हैं जो पकड़े गए हैं। यह हमारे देश में नागरिक चेतना के स्तर के बारे में बहुत कुछ बताता है।

आराध्या सक्सेना@ihailmyindia

जिस देश में महज एक घंटे की अफवाह पर लोग 200 रुपये किलो नमक खरीदने के लिए लाइनों में लग जाते हों, वहां गैस सिलिंडर की कालाबाजारी पर कैसी हैरानी? हम वे लोग हैं जो आपदा में अवसर नहीं, बल्कि दूसरों की मजबूरी में अपना फायदा ढूंढने में माहिर हैं। शर्मनाक पर सच! अमित यादव@amityadavamit

कोविड से लेकर लद्दाख गतिरोध, यूक्रेन युद्ध, ट्रंप की टैरिफ आक्रामकता और अब ईरान युद्ध तक के ये छह उथल-पुथल भरे साल एक कठोर सच्चाई उजागर करते हैं। भारत अब भी ऊर्जा, हथियार, तकनीकी, रेयर अर्थ, उर्वरक आदि उन चीजों के लिए दुनिया पर खतरनाक रूप से निर्भर है, जिन्हें एक गंभीर वैश्विक शक्ति को अपने देश के भीतर नियंत्रित करना चाहिए। शिव अरूर@ShivAroor

जनपथ

डमरू शंकर का बजे रुके चल रहा युद्ध,
इस अशांति के दौर में जागो गौतम बुद्ध।
जागो गौतम बुद्ध शांति का दो संदेशा,
होगा बड़ा विनाश दिख रहा है अंदेशा।
बना गले की फांस आजकल जो जलडमरू,
खुलवाओ भगवान बजाकर अपना डमरू!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 238

गुरुग्राम के फार्म हाउस में बिना लाइसेंस चल रही थी हुक्का पार्टी

जासं, गुरुग्राम: डीएलएफ फेस एक थाना क्षेत्र के बालियावास स्थित एक फार्म हाउस में बिना लाइसेंस शराब और हुक्का पार्टी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर ग्वाल पहाड़ी चौकी पुलिस और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने फार्म हाउस में गुरुवार रात छापेमारी की। इस दौरान 35 से ज्यादा लोग शराब और हुक्का का सेवन करते पाए गए। पुलिस टीम ने मौके से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

जांच में पता चला कि इस पार्टी का संचालन दिल्ली के पंजाबी बाग के रहने वाले लोकेश अरोड़ा की तरफ से किया जा रहा था। यहां 35 से ज्यादा लोग मौजूद मिले। जब आरोपितों से इसके लाइसेंस के बारे में पूछा गया, तो कोई कागज पेश नहीं कर पाए। फार्म हाउस से पांच हुक्का, छह फ्लेवर हुक्का व भारी मात्रा में अंग्रेजी और विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस टीम ने लोकेश के साथ फार्म हाउस संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

नोएडा रजिस्ट्री दफ्तर में 3035 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन मिला

आयकर विभाग को जांच में मिले भारी संख्या में दोषपूर्ण पैन

जागरण संवाददाता, नोएडा : कानपुर के बाद अब गौतमबुद्ध नगर के नोएडा रजिस्ट्री सिस्टम में भी बड़ा खेल सामने आया है। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे आयकर विभाग की टीम सेक्टर-33 स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय नोएडा-1 (एसआरओ-1) में पहुंची, और रिकार्ड की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में ही करीब 3035 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, जांच में संपत्ति रजिस्ट्रियों के रिकार्ड में अमान्य, अधूरे और दोषपूर्ण पैन नंबरों की बड़ी संख्या मिली है, जिससे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई गई है।

टीम ने डिजिटल डाटा, रजिस्ट्रियों के दस्तावेज और स्टेटमेंट आफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) रिकार्ड को खंगाला है। कई मामलों में संपत्ति की रजिस्ट्रियों में पैन नंबर या तो गलत दर्ज हैं या बिल्कुल नहीं दिए

नोएडा का निबंधन कार्यालय● आर्काइव

गए, जबकि बड़े लेन-देन में पैन अनिवार्य है। फार्म-61 और फार्म-61ए की रिपोर्टिंग में भी भारी अंतर सामने आया है।

पिछले कई वर्षों में रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा भेजे गए डाटा में बड़ी संख्या में त्रुटियां और अनियमितताएं पाई गई हैं। कई घंटों तक जांच चली। नोएडा में चल रही कार्रवाई के बाद अब जिले के अन्य सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के रिकार्ड की भी जांच होगी। अन्य रजिस्ट्री कार्यालयों पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, ताकि संपत्ति लेन-देन से जुड़े डाटा की स्थिति सामने आ सके। जांच की पुष्टि एआइजी स्टांप अरुण कुमार शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि जांच करने के लिए आयकर विभाग की टीम आई थी। उनसे बैनामा संबंधी तीन साल का रिकार्ड मांगा गया है।

कानपुर में मिलीं अनियमितताएं, फिर बढ़ा जांच का दायरा: इससे पहले कानपुर और कानपुर देहात के रजिस्ट्री कार्यालयों में भी आयकर विभाग को करोड़ों की अनियमितताएं मिली थीं, जिसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी रजिस्ट्री रिकार्ड की जांच शुरू की गई है। नोएडा में सामने आया मामला उसी जांच का हिस्सा माना जा रहा है। यदि जांच में गड़बड़ी की मिली तो संबंधित अधिकारियों और दस्तावेज तैयार करने वाले एजेंटों पर आयकर अधिनियम और अन्य प्रविधानों के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

बोगस फर्म बना 1.74 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाला गिरफ्तार

जासं, नोएडा : जाली दस्तावेज से बोगस फर्म बना आइटीसी क्लेम कर जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को सीआरटी और सेक्टर 58 थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार रात को सेक्टर 62 से गिरफ्तार किया। आरोपित ने अपने साथियों संग मिलकर जीएसटी विभाग को 1.74 करोड़ रुपये राजस्व का चूना लगाया था। उससे एक मोबाइल फोन, एक टेबलेट व दो फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ। पुलिस आरोपित के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि फर्म के लेनदेन में हेरफेर मिलने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। राज्यकर अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने 25 अक्टूबर 2025 को सेक्टर 58 थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपित की पहचान दिल्ली तुगलकाबाद एक्सटेंशन के रोहन गुप्ता के रूप में हुई। उसने मेसर्स केएस 2024-25 में बिना किसी वास्तविक खरीद के 1.74 करोड़ रुपये का बोगस आइजीएसटी क्लेम किया था।

सिग्नल व राकेट एप का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी-कट्टरपंथी संगठन

आशुतोष गुप्ता● जागरण

- दोनों एप पर सरकार का नियंत्रण नहीं होने से आतंकियों की पसंद
- आतंकी ग्रुप के सदस्य के कहने पर डाउनलोड किया सिग्नल एप

गाजियाबाद : आतंकी व कट्टरपंथी संगठन देश में अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सिग्नल व राकेट एप का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों एप पर सरकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण यह आतंकियों की खास पसंद हैं। यूएपीए के तहत पकड़े गए छह आरोपितों से सनसनीखेज जानकारी सामने आई हैं। पकड़े गए ग्रुप लीडर शावेज ने आतंकी संगठन के सदस्य के कहने पर सिग्नल एप डाउनलोड किया था। इसके बाद से वह आतंकी और कट्टरपंथी ग्रुपों से जुड़ा। विभिन्न ग्रुप से वीडियो डाउनलोड कर अपने ग्रुप पर प्रसारित करता था। इन्हीं वीडियो से वह कोर ग्रुप पर जुड़े पांच सदस्यों को ट्रेनिंग देता था।

शावेज इंस्टाग्राम अकाउंट पर आतंकी और कट्टरपंथी संगठनों के सदस्यों को तलाशता था। यहीं पर उसका संपर्क पाकिस्तानी आतंकी और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले के आरोपित फरातुल्ला घोरी के ग्रुप के सदस्य आफताब आलम से हुआ। शावेज ने खुद को आतंकी संगठनों के ग्रुप से जोड़ने के लिए कहा तो आफताब ने सिग्नल या राकेट एप डाउनलोड करने की सलाह दी। शावेज ने सिग्नल एप डाउनलोड किया। इसी एप से उसने जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप के वीडियो डाउनलोड किए और अपने वाट्सएप ग्रुपों पर प्रसारित करने लगा। सिग्नल एप पर उसने जैश-ए-मोहम्मद, हमजा, फरातुल्ला घोरी, अजहर मसूद, स्वात-उल-हक समेत अन्य ग्रुपों व चैनल पर जुड़ने का प्रयास किया था, लेकिन अनजान होने के कारण एडमिन ने रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की।

फैल रहा है डिजिटल स्लिपर सेल का जाल : डिजिटल स्लिपर सेल माड्यूल पूरे देश भर में फैल रहा है। इस नए पैटर्न से खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान व अरब देशों से फंडिंग की आशंका भी जताई जा रही है।

यति नरसिंहानंद भी थे आतंकियों के निशाने पर

श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी भी आतंकियों के निशाने पर हैं। पकड़े गए आरोपित भी यति का सिर तन से जुदा करने की साजिश रच रहे थे। आरोपितों की सूची से चार नाम और मिले हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर हमाद बरकाती ने वीडियो में इनकी गर्दन उड़ाने की अपील की थी। इनमें हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी, डा. प्रकाश व पप्पू चौधरी शामिल हैं।

गरिमापूर्ण विदाई का संवेदनशील पल, हरीश को पैलिएटिव केयर में भर्ती करने की तैयारी

शहनवाज अली● जागरण

गाजियाबाद : हरीश राणा जैसे संवेदनशील व ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस केवी विश्वनाथन ने दिल्ली एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश राणा को पैलिएटिव केयर में भर्ती कर चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में जीवनरक्षक उपकरण हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। स्वजन हरीश की गरिमापूर्ण विदाई को लेकर भावुक हैं व दिल्ली एम्स की चिकित्सीय टीम के इंतजार में हैं।

बता दें कि पैलिएटिव केयर का उद्देश्य असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को तब आराम, सम्मान व गरिमा देना होता है, जब उपचार की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हों। कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में बृहस्पतिवार को एम्स की विशेषज्ञ टीम के आने की उम्मीद थी, पर वह नहीं आ सकी। शुक्रवार को टीम के आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन शाम तक टीम नहीं आई।

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के फ्लैट में बेड पर लेटे हरीश राणा को करवट दिलाता छोटा भाई आशीष राणा व उन्हें देखते सीएमओ डा. अखिलेश मोहन● जागरण

हरीश को वेटलिफ्टिंग में चैंपियन व सिविल इंजीनियर देखने का अधूरा सपना: हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि संघर्ष, सपनों व अचानक टूटी उम्मीदों की मार्मिक दास्तां है। वर्ष 2013 में हरीश बीटेक (सिविल इंजीनियरिंग) के फाइनल ईयर के छात्र थे। पढ़ाई के साथ वह वेटलिफ्टिंग का बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। इस हादसे से पहले वह दो प्रतियोगिता जीत चुके थे। उनका सपना सिविल इंजीनियरिंग के साथ वेट लिफ्टिंग में चैंपियन बनने का भी था, जिसे उनके पिता अशोक राणा पूरा होते देखना चाहते थे। लेकिन यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। हरीश चंडीगढ़ के एक पेइंग गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल होने के बाद कोमा में चले गए ।

डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले में आरोपित को अग्रिम जमानत से इन्कार

- कहा- आरोपित के खाते में 30 लाख जमा होने के दिन ही अन्य खाते में स्थानांतरित हुई थी राशि
- महिला को सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी आदेश दिखा डिजिटल की गई थी 1.10 करोड़ की ठगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले और इसके जरिये लोगों से हर दिन होने वाली करोड़ों रुपये की ठगी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आरोपित को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोपित पर साइबर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है और इस पूरी आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उससे हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली न्यायिक दस्तावेज के आधार पर किए जाने वाले डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया है और इस प्राथमिकी के पीड़ित को उस मामले में एक हस्तक्षेपकर्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की मदद करने की अनुमति दी गई है। पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराध तकनीकी माध्यमों से किए जाते हैं ताकि मासूम पीड़ितों को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठे जा सकें। ऐसे में अदालत का मानना है कि इस चरण पर अग्रिम जमानत देना जांच में बाधा डाल सकता है।

याचिका के अनुसार एक पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि 15 मार्च 2025 को साइबर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी आदेश दिखाकर उसे डिजिटल अरेस्ट किया। जालसाजों ने 18 मार्च को उनके खाते से 30 लाख रुपये एक बैंक खाते में स्थानांतरित कराया। एक अन्य खाते में भी 80 लाख रुपये स्थानांतरित कराए। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि 30 लाख रुपये का ट्रांसफर एक ऐसी फर्म के खाते में किया गया था जिसका संबंध याचिकाकर्ता आरोपित से था। वहीं, आरोपित ने दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया था और वह खुद एक साजिश का शिकार हुआ है। उसने दावा किया कि उसका ई-मेल खाता हैक कर लिया गया था और उसने अपने खाते में कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में बैंक को भी सूचित किया था।

पश्चिम रेलवे
भावनगर मंडल
क्वार्टर एवं लॉन टेनिस कोर्ट उपलब्ध कराने का कार्य

ई-निविदा संख्या: 292-2025-26 कार्य का नाम: समूह कार्य: (1) भावनगर परा में प्रतिस्थापन के आधार पर टाइप-II के 13 क्वार्टर, टाइप-III के 2 क्वार्टर तथा टाइप-IV का 1 क्वार्टर उपलब्ध कराना। (2) भावनगर परा में ORH के पास लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण। निविदा मूल्य (रुपये): ₹ 4,82,03,157.68 EMD (रुपये): ₹ 3,91,000.00 बिडिंग प्रारंभ तिथि: 20/03/2026 बिडिंग की समापन तिथि: 03/04/2026 उपरोक्त निविदा को 12/03/2026 को रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।
BVP 287
में लाइक करें facebook.com/WesternRly

thsti **ब्रिक-ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान** **BRIC** a DST Organisation
(जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद का एक संस्थान, भारत सरकार)
एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर, तीसरा माइलस्टोन, फरीदाबाद-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, पी.ओ. बॉक्स नंबर 04, फरीदाबाद – 121001
भर्ती सूचना सं. टीएचएस-सी/आरएन/06/2026 और टीएचएस-सी/आरएन/07/2026
सीडीएसए – टीएचएसटीआई निम्नलिखित पदों को भरने का प्रस्ताव रखता है 1. सहायक डेटा प्रबंधक 2. सहायक डेटा प्रबंधक 3. प्रधान परियोजना सहायक 4. अनुसंधान वैज्ञानिक 5. कनिष्ठ अनुसंधान वैज्ञानिक 6. डेटा वैज्ञानिक
विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.thsti.res.in पर जाएं।

thsti **ब्रिक-ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान** **BRIC** a DST Organisation
(जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद का एक संस्थान, भारत सरकार)
एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर, तीसरा माइलस्टोन, फरीदाबाद-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, पी.ओ. बॉक्स नंबर 04, फरीदाबाद – 121001
भर्ती सूचना सं. टीएचएस/आरएन/40/2025 और टीएचएस/आरएन/41/2025
टीएचएसटीआई अपनी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों को भरने का प्रस्ताव रखता है: 1. परामर्शदाता एवं औषधि विज्ञान विभागाध्यक्ष 2. परामर्शदाता (अध्ययन समन्वयक) 3. तकनीकी सहायक (सामुदायिक जागरूकता) 4. परियोजना वैज्ञानिक (फार्मासिस्ट)
विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.thsti.res.in पर जाएं।

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY
(A State University established by Govt. of NCT of Delhi)
SECTOR-16 C, DWARKA, NEW DELHI-110078
Website : www.ipu.ac.in
TENDER NOTICE FOR INVESTMENT OF FUNDS
Guru Gobind Singh Indraprastha University intends to invest its funds approx. **Rs.295 Cr. (Rupee Two Hundred Ninety Five Crore Only)** in fixed deposit and accordingly invites competitive interest rates only from the Nationalized Banks only by **18th March 2026** upto 12.00 Noon by post or via Email at Email Id:- investment@ipu.ac.in with validity of interest rates till **23.03.2026**. Kindly refer the detailed notice on the University website "**www.ipu.ac.in**" under the Head "Tenders" in Events & Notices.
(CONTROLLER OF FINANCE)

अग्निवीर (एस एस आर/एम आर) और एस एस आर (मेडिकल) के रूप में जुड़िये

भारतीय नौसेना अग्निवीर(एस एस आर/एम आर) और एस एस आर (मेडिकल) के लिए ई-आवेदन पत्र आमंत्रित करती है

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि : 14 मार्च से 06 अप्रैल 2026

प्रवेश (Post)	शैक्षणिक योग्यता
अग्निवीर एस एस आर (सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट)	भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से गणित और भौतिकी के साथ 10+2 में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। **अथवा** केंद्रीय, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ ऑटोमोबाइल/ कंप्यूटर साइंस/ इंस्ट्रुमेंटेशन टेक्नोलॉजी/ सूचना प्रौद्योगिकी) में कुल 50% अंकों के साथ तीन साल का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। **अथवा** केंद्रीय, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों से गैर-व्यावसायिक विषय अर्थात भौतिकी और गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ दो साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
अग्निवीर एम आर (मैट्रिक रिक्रूट)	उम्मीदवार को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
एस एस आर (मेडिकल)	भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से बायोलॉजी, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ 10+2 में न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ (40% न्यूनतम प्रति विषय) उत्तीर्ण होना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन के लिए कृपया स्कैन करें
www.joinindiannavy.gov.in | www.ssc.gov.in
रोजगार समाचार पत्र 21 मार्च 2026
विकसित समृद्ध भारत के लिए समुद्रों की सुरक्षा
CBC 10701/13/0024/2526

चिंतन

सदन की मर्यादा बनाए रखना सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी

संसद वह मंच है जहां देश के करोड़ों लोगों की आवाज उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाई जाती है। संसद केवल बहस और विरोध का स्थान नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मर्यादा, नियमों और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि सदन में उपस्थित प्रत्येक सांसद अपने आचरण से संसद की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखे। हाल ही में लोकसभा में गैस और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान जो घटनाक्रम सामने आया, उसने एक बार फिर इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि सदन की मर्यादा और संसदीय नियमों का पर्याप्त सम्मान कर रहे हैं। लोकसभा में हाल ही में कांग्रेस की ओर से तेल और गैस की स्थिति पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया था। यह एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि देश के कई हिस्सों में एलपीजी और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर गंभीर और तथ्यपरक चर्चा की अपेक्षा स्वाभाविक थी। हालांकि, चर्चा के दौरान घटनाक्रम कुछ अलग दिशा में मुड़ गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब इस विषय पर अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने एलपीजी और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे से हटकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से जुड़े कुछ आरोपों का उल्लेख किया। इन आरोपों में अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के नामों का भी जिक्र किया गया, जिससे सदन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस विषय पर नोटिस दिया गया है, उसी विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने राहुल की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उसे संसद की कार्यवाही से हटाने के निर्देश भी दिए। स्पीकर ने यह भी दोहराया कि सदन की कार्यवाही संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही चलेगी और बिना पूर्व नोटिस के किसी अन्य मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संसद में बहस का स्तर जितना गंभीर और तथ्यपूर्ण होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। यदि बहस मुद्दों से भटककर व्यक्तिगत आरोपों और राजनीतिक टकराव तक सीमित हो जाए तो इसका नुकसान लोकतांत्रिक व्यवस्था को होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों से उम्मीद करती है कि वे संसद में उनके मुद्दों को गंभीरता से उठाएं और समाधान की दिशा में सार्थक चर्चा करें। दरअसल, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लेकिन इन मतभेदों को व्यक्त करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। संसदीय लोकतंत्र में नियम, प्रक्रिया और मर्यादा केवल औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि वे उस व्यवस्था की नींव हैं जो देश को लोकतांत्रिक रूप से संचालित करती है। आज जब देश अनेक आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब संसद से यह अपेक्षा और भी बढ़ जाती है कि वहां होने वाली बहसें गंभीर, सार्थक और समाधान की दिशा में हों। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि संसद केवल राजनीतिक प्रदर्शन का मंच नहीं है, बल्कि यह नीति निर्माण और लोकतांत्रिक जवाबदेही का केंद्र है। कुल मिलाकर यह सभी सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे सदन की गरिमा, नियम और मर्यादा को बनाए रखें। वहीं विपक्ष भी अपने उठाए मुद्दों पर बहस से न भागे और संसद के नियमों का पालन करे।

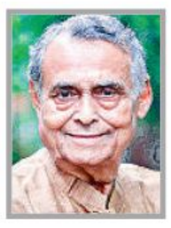

जिरहनामा
कनक तिवारी

कांग्रेस के इन्टेलेक्चुअल्स कहां गुम हैं?

भारतीय राजनीति फिलवक्त तेज घुमाव के मोड़ पर है। आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्पादित हिन्दुत्व की सबसे बड़ी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की अंकगणित में अच्छा खासा बहुमत हासिल कर रखा है। दूसरी ओर प्रतिपक्ष की कई अलग थलग पार्टियां हमकदम और एकराय होकर भी केन्द्रीय निजाम को कारगर चुनौती देने के नतीजे तक नहीं पहुंची हैं। तराजू के पलड़ों पर मेंढकों को जिस तरह तौला नहीं जा सकता, उसी तरह भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को खुदगर्जी छोड़कर देश की एकता के लिए एकजुट नहीं किया जा सकता रहा है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की अब अजीब हालत है। हालिया वर्षों में विरोधाभासों, गलतफहमियों, आत्ममुग्धता और बिखराव के कारण कांग्रेस का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर जाता लगा था। उन पर आरोपित नौसिखियापन के बावजूद शायद अकेले राहुल गांधी गाफिल और भौंचक दिखती पार्टी में उद्दाम फूंकने की कोशिश तो करने लगे हैं। उनकी 'भारत जोड़ो यात्रा' राजनीतिक सफर में मील का पत्थर भी तो कही जाने लगी। पता नहीं मंजिल मिले, न मिले। दिक्कत यह है कि सबसे पुरानी, बुनियादी और पहले बुद्धिजीवी रही पार्टी गैर मुनासिब सियासी ढकोसलों में ज्यादा फंसती रह गई है। उसके ज़्यादातर नेताओं को पार्टी की ऑइडियोलॉजी तक ठीक से कार्यकर्ताओं को समझाने क्या खुद समझने की भी कूबत नहीं है। गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, श्रीनिवास शास्त्री जैसे असाधारण ख्याति के तमाम आला दर्जे के बौद्धिक रहे। हालांकि शीराजा नेहरू युग के बाद बिखरता गया।

नेहरू ने ही युवा समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया को कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां देकर शामिल किया है। कांग्रेस का शुरुआती ऐसा ही सलूक जयप्रकाश, नरेन्द्र देव और अन्य समाजवादी नेताओं के साथ भी रहा। हालांकि बाद के वर्षों में कांग्रेस सोशलिस्टों ने पार्टी से छोड़ छुट्टी कर ली। तब नेहरू आग बबूला भी हो गए। नेहरू के ही प्रधानमंत्री काल में कांग्रेस की दरकती साख और सरकार की कई नाकामियों को देखकर कांग्रेस को चुस्त दुरुस्त करने कम्युनिस्टों से लगाव हुआ। यह क्रम इंदिरा गांधी ने भी जारी रखा। कृष्ण मेनन, केशव देव मालवीय, चंद्रजीत यादव, मोहन कुमार मंगलम और समाजवादी खेमे से अशोक मेहता, मोहन धारिया, चंद्रशेखर जैसे कई नेता कांग्रेस पार्टी में समय समय पर आवाजाही करते रहे।

नेहरू ने ही युवा समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया को कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां देकर शामिल किया है। कांग्रेस का शुरुआती ऐसा ही सलूक जयप्रकाश, नरेन्द्र देव और अन्य समाजवादी नेताओं के साथ भी रहा। हालांकि बाद के वर्षों में कांग्रेस सोशलिस्टों ने पार्टी से छोड़ छुट्टी कर ली। तब नेहरू आग बबूला भी हो गए। नेहरू के ही प्रधानमंत्री काल में कांग्रेस की दरकती साख और सरकार की कई नाकामियों को देखकर कांग्रेस को चुस्त दुरुस्त करने कम्युनिस्टों से लगाव हुआ। यह क्रम इंदिरा गांधी ने भी जारी रखा। कृष्ण मेनन, केशव देव मालवीय, चंद्रजीत यादव, मोहन कुमार मंगलम और समाजवादी खेमे से अशोक मेहता, मोहन धारिया, चंद्रशेखर जैसे कई नेता कांग्रेस पार्टी में समय समय पर आवाजाही करते रहे।

फिर तो ज्यादातर कांग्रेसी बरसों से किताबों से बैर किए बैठे रहने लगे। भले ही गाल बजाते रहे कि हमारी सबसे बड़ी और बुनियादी बुद्धिजीवी पार्टी रही है। किताबें, बहस, मुबाहिसा, लेखन और वैचारिकता कमोबेश दाखिल दफ्तर होते रहे हैं। कांग्रेसियों को एक और बड़ी गलतफहमी है। वह यह कि संघ परिवार और भाजपा में स्तरीय बुद्धिजीवियों का टोटा है। समाजसेवक शासक या जमावडे. में काम चलाऊ किस्म के मझोले दरजे के कुछ बुद्धिजीवी भले हो सकते होंगे। कांग्रेसी नहीं देख पाते कि संघ परिवार में जो जितना आलिम फाजिल है, उस पर भरोसा कर उसे जिम्मेदारी के अनुपात में उतने काम सौंप दिए जाते हैं। वह धीरे धीरे प्रोन्नत और विकसित होता सशक्त भी होता चलता है। उसे इत्मीनान होता है कि पार्टी नेतृत्व उसके पीछे है।

कांग्रेस पार्टी में टांग घसीटो अभियान भी काफी वक्त से चल ही रहा है। यह लक्षण तो तकलीफदेह है। कई नेताओं को पार्टी की वैचारिकता, संविधान, इतिहास और किए गए आधे अधूरे वायदे और राष्ट्रीय अधिवेशनों के ऐलान तक मालूम नहीं होता। इधर भाजपा ने अपने पार्टी दफ्तरों को अधुनातन बना लिया है। तकनीकी सरंजाम मुहैया करने के साथ साथ पुस्तकालय और सूचना तंत्र भी विकसित किए हैं। लगता नहीं इसके मुकाबिले कांग्रेस दफ्तरों में किसी तरह पुस्तकालय और सूचना संस्कृति का बीजारोपण भी हो रहा है। एयर कंडीशन्ड हॉल में बैठकर मुट्ठी भर लोगों के सामने पाटी के जश्न और जलसे किए जाने से राजनीति में सफलता के दिन लद रहे हैं। अलबत्ता कांग्रेस में अभी भी कुछ बुद्धिजीवी शेष रह गए हैं। उनकी लेकिन कांग्रेस के मौजूदा सत्ता संकुल में कोई निर्णायक पूछ परख नहीं है।

कांग्रेस सम्मेलनों और सेमिनारों में बुद्धिजीवियों को तरजीह देना और उन्हें शामिल शरीक कर लक्ष्यभेदी आयोजन करने के बदले इंवेट मैनेजमेंट का मौसम उगा लिया जाता है। पार्टी की समझ को फिलवक्त फिर से वाम बुद्धिजीवी सरगनाओं को मानो लीज पर दिया जा रहा है। कांग्रेसी मंत्रियों की ऐसी फौज भी उग रही है जिसे पढ़ने लिखने से ही सरोकार नहीं रहा। पारम्परिक कांग्रेसी समझ के सयाने बुद्धिजीवियों की केन्द्रीय भूमिका से बेदखली, उपेक्षा और अपमान तक की साजिशें समझ के परे हैं। मंत्री और संगठन के शीर्ष पदाधिकारी मुंह लगे बाजार-सुलभ निठल्लों को किचन कैबिनेट में शामिल करते हैं। कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्र कोई उठाकर देखे। चेहरों की सूची में प्रतिबद्ध कांग्रेसियों और बुद्धिजीवी परिवारों को बेदखल किया जाना साफ साफ दिखाई पडेगा।

पता नहीं क्यों कांग्रेस को अपने ऊपर खुद की गफलत से लगाई जा रही कीचड़ को सुखाने का न तो मौका मिल रहा है और न ही नीयत दिखाई दे रही है। दुखद है कि लोकतंत्र में अब मंत्री ही सर्वेसर्वा हो गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर भद्दा कमेन्ट करने वाले बुद्धिजीवी कहलाते मणिशंकर अय्यर हाशिए पर डाले जाने के बाद भी पार्टी का फिर नुकसान करते फिर रहे हैं। सत्ताविहीन छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी कांग्रेसियों में कारगर बुद्धिजीवी खोजना किसी खल्वाट में जुएं बीनने जैसा पराक्रम है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)।

स्वास्थ्य
मनीष कुमार चौधरी

खानपान में मिलावट का घुलता धीमा जहर

दशकों पहले मुनाफे के लिए छोटी-मोटी छेड़छाड़ के रूप में शुरू हुआ मिलावट का खेल अब एक बेरहम खतरा बन गया है। एक धीमा जहर, जो हमारी रसोई और थालियों में घुल-मिल गया है। मिलावट, जिसे कभी एक अलग-थलग गलती माना जाता था, उसे अब मॉडर्न फूड सप्लाई चेन में एक प्रणालीगत कमजोरी के तौर पर पहचाना जा रहा है। खाने में मिलावट और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाना भारत में एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। मिलावटी भोजन की पहचान आमतौर पर तब तक नहीं हो पाती जब तक कि उससे स्वास्थ्य संबंधी खतरा न दिखने लगे। मात्रा बढ़ाने के लिए मिलावट करने वाले पदार्थ मिलाना, ठोस पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के लिए गाढ़ा करने वाले पदार्थ मिलाना, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की मात्रा की भरपाई करना, शेल्फ लाइफ बढ़ाना, सौंदर्यबोध बढ़ाना और इसे असली जैसा दिखाना...। ये कुछ तरीके इतने आम हो चले हैं कि रोजमर्रा की खरीदारी में गिनती में ही नहीं आते। कुछ खाद्य उत्पादक/व्यापारी अपने उत्पादों का बढ़ा-चढ़ाकर विज्ञापन करते हैं। भ्रामक/झूठे विज्ञापनों के कारण उपभोक्ता के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थों का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाने में मिलावट अब कभी-कभार होने वाली घटनाओं तक सीमित नहीं है। दूध, पनीर, मसाले, सब्जियां, अंडे, मीट, मछली और पैकेज्ड फूड, जिन्हें रोजाना लाखों लोग खाते हैं, अब आए दिन वैज्ञानिक जांच के दायरे में आ रहे हैं। सर्विलांस रिपोर्ट, फूड टेस्टिंग डेटा और रेगुलेटरी नतीजों से पता चलता है कि उत्पादन और वितरण के कई चरणों पर बार-बार गड़बड़ियां होती हैं। यह कई रूपों में होती हैं। जैसे मिलावट, प्रतिस्थापन, पैकेजिंग सामग्री में खराब गुणवत्ता को छिपाना, सड़े हुए खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए रखना, गलत ब्रांडिंग या झूठे लेबल लगाना और विषाक्त पदार्थों को मिलाना। खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर, यकृत रोग, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी और तंत्रिका तंत्र संबंधी कई बीमारियां होती हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना स्वास्थ्य और ग्राहक संतुष्टि की रीढ़ है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का बने रहना कोई संयोग नहीं है। यह आर्थिक लालच से प्रेरित है, सिस्टम की कमियों के कारण संभव होता है और उपभोक्ता की अज्ञानता व लापरवाही से कायम रहता है। अधिकांश खरीदारों को पता नहीं होता कि इसकी कहां-कैसे शिकायत करें। कानून की कमजोरियों और लचर सिस्टम का फायदा उठाकर कई कारोबारी इस मिलावट के खेल में शामिल रहते हैं। नियामक निकाय, कानूनों और एजेंसियों के बावजूद यह खतरा इसलिए जारी है, क्योंकि प्रवर्तन अधूरा है और अपराधी अक्सर बिना सजा के बच निकलते हैं। अब तो मिलावट के तरीके और भी ज्यादा परिष्कृत हो गए हैं। ऐसे रसायनों और रंगों का उपयोग किया जा रहा है जो असली भोजन की बनावट, रंग और स्वाद की नकल करते हैं, जिससे आम उपभोक्ता के लिए शुद्ध-अशुद्ध की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भारत में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कई मानक तय किए हुए हैं। निरीक्षण भी होता है और जुर्माना भी लगता है। वैज्ञानिक और उन्नत प्रयोगशाला तकनीकें भी मौजूद हैं। परंतु नियमों को लागू करने के लिए अभी भी ज्यादा मैनपावर, बेहतर तालमेल और तेज व गतिशील कानूनी प्रक्रियाओं की जरूरत है। हाल ही में सरकार की ओर से खाद्य पदार्थों के लिए स्टार रेटिंग की प्रक्रिया पर और सुधार की जरूरत बताई गई है। एक शपथ पत्र में, एफएसएसएआई ने 'फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' के लिए एक मैकेनिज्म को फाइनल करने से पहले ड्राफ्ट रेगुलेशन को वापस लेने और आगे शोध करने का प्रस्ताव दिया है। इंडस्ट्री चाहती है कि लेबलिंग प्रोडक्ट पर छपने तक ही सीमित न रहे। हमें यह बताकर वैल्यू ऐड करनी होगी कि यह अच्छी है, बुरी है या कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि एफएसएसएआई के 2022 के नियमों में प्रस्तावित स्टार-बेस्ड सिस्टम सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन कम से कम यह एक ऐसा सिस्टम बनाने की शुरुआत थी, जहां ग्राहक पैकेज्ड खाद्य उत्पादों को खरीदने से पहले सोच-समझकर फैसला ले सकें। हर मिलावटी चीज न सिर्फ भरोसे का धोखा है बल्कि इंसानी सेहत पर सीधा हमला है, जो पोषण को खतरा बना देता है। कड़वी सच्चाई यह है कि कई 'भरोसेमंद' ब्रांड भी मिलावट से अछूते नहीं हैं। आम उपभोक्ता अक्सर इस खतरे के सामने खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। खाने में मिलावट चुपचाप पनपती है और यह तभी खत्म होंगी जब सरकारें कड़े कदम उठाएंगी, उद्योग नियमों का पालन करेंगे और उपभोक्ता समझौता करने से इनकार करेंगे। शुद्धता कोई विलासिता नहीं है, यह एक अधिकार है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सत्य, तप, दया और पवित्रता

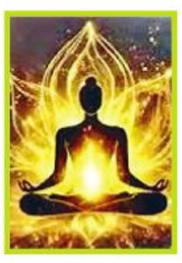

संकलित
दर्शन

सत्य ही सर्वस्व है। सत्य के बिना सदाचार, दान, कीर्ति, धन किसी काम के नहीं। जहां सत्य होगा, वहां ये सभी होंगे। सत्य परमात्मा है। सत्य प्रभु से भिन्न नहीं है। सत्य के द्वारा मनुष्य ईश्वर के निकट जा सकता है। जंगलों, पहाड़ों और वीराने में एकांतवास करना तपस्या नहीं है। जीवन में सच बोलना और सच की राह पर चलना ही सबसे बड़ी तपस्या है। धर्म के चार पद हैं- सत्य, तप, दया और पवित्रता। इन चार चरणों में सत्य सर्वोपरि है। महाभारत में राजा सत्यदेव की कथा आती है। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा कि चंचला लक्ष्मी उनके महल से कुछ समय पश्चात चली जाएगी। एक दिन सुबह जब सत्यदेव उठे, तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को घर से निकलते देखा। राजा ने आश्चर्य से उस स्त्री से पूछा, 'आप कौन हैं?' जवाब मिला, 'मेरा नाम लक्ष्मी है। अब मैं इस घर से जा रही हूं।' राजा ने कहा कि आप जा सकती हैं। लक्ष्मीजी चली गईं। उसके पीछे एक सुंदर पुरुष को बाहर जाते देखकर राजा ने पूछा, 'आप कौन हैं?' उत्तर मिला, 'मेरा नाम दान है। लक्ष्मी के जाने के बाद आप दान नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं आपका घर छोड़ कर जा रहा हूं।' राजा ने कहा कि आप भी जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा सदाचार और चौथा यश, पुरुष के रूप में बाहर आए। राजा के पूछने पर लक्ष्मी तथा दान के साथ जाने की कहने पर राजा ने दोनों को जाने दिया। जब पांचवां पुरुष सत्य जाने लगा, तो राजा ने हाथ जोड़ विनयपूर्वक कहा, 'मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। आप मुझको किसलिए छोड़ रहे हैं? आपके लिए मैंने लक्ष्मी, दान आदि सबका त्याग किया है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आपके जाने पर मेरा सब कुछ चला जाएगा।' यह सुनकर सत्य वहीं रह गया। सत्य घर में से बाहर नहीं आया, अतएव गई हुई लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी वापस आ गए। सत्य ही सर्वस्व है।

चेतन अमल सहज सुख रासी

संकलित
प्रेरणा

वस्तु, व्यक्ति और क्रिया- ये तीन चीजें दिखने में आती हैं। इनमें वस्तु तथा क्रिया- ये दोनों प्रकृति हैं और व्यक्ति रूप में जो दिखता है, यह शरीर भी प्रकृति ही है, परंतु इसके भीतर में जो न बदलने वाला है, यह परमात्मा का अंश है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया- ये तीन चीजें दिखने में आती हैं। इनमें वस्तु तथा क्रिया- ये दोनों प्रकृति हैं और व्यक्ति रूप में जो दिखता है, यह शरीर भी प्रकृति ही है, परंतु इसके भीतर में जो न बदलने वाला है, यह परमात्मा का अंश है। अब अगर 'यह' वस्तु, क्रिया और व्यक्ति में नहीं उलझे, तो यह स्वाभाविक ही मुक्त है; क्योंकि 'यह' परमात्मा का साक्षात अंश है। इसके लिए कहा है- 'चेतन अमल सहज सुख रासी।' यह चेतन है, शुद्ध है, मलरहित है और सहज सुख राशि है, महान आनंद राशि है। यह महान आनंद राशि अपने स्वरूप की तरफ ध्यान न देकर संसार के संबंध से सुख चाहने लग गया। इससे यही भूल हुई है। यह संयोग जन्य सुख में फंस गया। जैसे, धन मिले, तो सुख हो। भोजन मिले, तो सुख हो। भोग मिले, तो सुख हो। कपड़ा, वस्तु, आदर, मान, सत्कार मिले, तो सुख हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला है- 'सहज सुख रासी' स्वाभाविक ही सुख राशि है, परंतु इसमें यह वहम पड़ गया है कि संसार के पदार्थ मिलने से सुख होगा। यह बिछुड़ेगा जरूर ही 'संयोगा विप्रयोगान्ताः' जितने संयोग होते हैं, उनका अंत में वियोग होता है, तो संबंध से होने वाला सुख रहेगा कैसे? मनुष्य यह विचार नहीं करता है कि आज दिन तक संयोग से जितने सुख लिए थे, वे आज नहीं रहे।

दशामाता व्रत

राजस्थान के बेवार में दशामाता व्रत के दौरान पूजन-अर्चन करती महिलाएं।

आज की पाती

बदलता मौसम और अनिश्चित भविष्य

फरवरी का महीना कभी सर्द हवाओं, हल्की धूप और पहाड़ों पर जमी बर्फ के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा है। कश्मीर घाटी, जिसे बर्फ और ठंड की धरती माना जाता है, वहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह फरवरी के इतिहास में असामान्य माना जा रहा है। 24 फरवरी 2016 को 20.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था, लेकिन इस वर्ष उससे भी अधिक गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीनगर के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डा. मुख्तार अहमद के अनुसार इस बार कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ, जिससे सामान्य शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी नहीं हो सकी। यह केवल एक मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि वायुमंडलीय असंतुलन का संकेत है। -परेश कौशिक

ट्रेंड

डीजल-पेट्रोल की कमी नहीं

उत्तर प्रदेश में डीजल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। रसोई गैस की कमी से संबंधित अफवाहों से बचें। यदि कोई वितरक एजेंसी अथवा निजी व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

आधुनिक वाहन

झारखंड राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज झारखंड पुलिस के हजारों आधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही नए थानों की आधारशिला रखी तथा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया।
- हेमन्त सोरेन, सीएम, झारखंड

विकास बोर्डों का गठन

हमारी सरकार मुंडा (अनुसूचित जनजाति), कोरा, डोम (अनुसूचित जाति), कुंभकार और सदगोपे (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदायों के लिए शीघ्र ही पांच नए सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डों का गठन करने जा रही है। ये समुदाय बंगाल की जीवंत संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। इन सभी को बधाई।
-ममता बनर्जी, सीएम, प. बंगाल

विपक्ष के पास एजेंडा नहीं

विपक्ष के पास रचनात्मक कार्य करने का कोई एजेंडा नहीं बचा है। उनका एकमात्र उद्देश्य विकास कार्यों में बाधा डालना है। वे न तो सकारात्मक सोच रखते हैं, न ही देशहित में कोई सार्थक योगदान देना चाहते हैं।
-अरुण गोविल, सांसद, भाजपा

करंट अफेयर

भारत होर्मुज से अपने व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान के संपर्क में

भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक जहाजरानी मार्ग से भारतीय ध्वज वाले लगभग 28 व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने को लेकर ईरान के साथ संपर्क में है। अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष के बीच ईरान ने इस मार्ग को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष के बीच हुई बातचीत के दौरान जहाजरानी की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे उठे थे। पता चला है कि ईरान ने पिछले चार-पांच दिन में भारतीय ध्वज वाले किसी भी वाणिज्यिक टैंकर को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी है। पोत परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में भारतीय ध्वज वाले कुल 24 जहाज 677 भारतीय नाविकों के साथ मौजूद हैं, जबकि रणनीतिक जलमार्ग के पूर्व में 101 भारतीय नाविकों वाले चार जहाज तैनात हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, ''हाल के दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच तीन बार बातचीत हुई है। आखिरी वार्ता में जहाजरानी की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे आगे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

ऑफ बीट

भगवान नृसिंह की छवि के रूप में स्थापित मां प्रत्यंगिरा देवी

उज्जैन में मां भगवती के ऐसे अद्भुत रूप की पूजा होती है, जो दिखने में भगवान नृसिंह की छवि लगती है। खास बात यह है कि मंदिर में मौजूद मां, असुर रावण की कुलदेवी हैं। उज्जैन में यह मंदिर भैरवगढ़ रोड स्थित बगलामुखी धाम के नजदीक ही है। मां प्रत्यंगिरा देवी का रूप मां के बाकी अवतारों से अलग और क्रोध को दिखाने वाला है। मां का चेहरा सिंह के जैसा है और बाकी का शरीर देवी के समान है। मां का ये प्रतिरूप सिंह की गर्जना की तरह दिखता है। पौराणिक कथा की मानें तो जब परम भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने भगवान नृसिंह का रूप लिया था, तब हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। भगवान नृसिंह के क्रोध की वजह से देवता और असुर दोनों घबरा गए थे। तब सभी देवताओं के आह्वान के बाद मां प्रत्यंगिरा प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान नृसिंह को शांत करवाया था। रावण की कुलदेवी हैं निकुंबला- खास बात ये है कि प्रत्यंगिरा देवी को निकुंबला देवी का ही रूप माना जाता है, जिनकी पूजा रावण और उसके पुत्र मेघनाद ने की थी। रामायण में मां निकुंबला देवी का जिक्र भी है कि कैसे युद्ध पर जाने से पहले रावण और उसके पुत्र मेघनाद ने विजय पाने के लिए मां के विशेष अनुष्ठान किए थे।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

एलपीजी के मुद्दे पर हुए हंगामे के बीच लोकसभा में पारित हुई अनुदान की अनुपूरक मांगें

वित्त वर्ष-2026 में 2.01 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त सरकारी खर्च को सदन ने दी मंजूरी

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

लोकसभा में शुक्रवार को एलपीजी संकट के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा। जिसकी वजह से सदन में प्रश्नकाल, शून्यकाल तक नहीं हुआ और कार्रवाई भी दो बार के स्थगन के बाद अगले सप्ताह 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी हंगामे और शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष-2026 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर हुई चर्चा का जवाब दिया। जिसके बाद सदन से इन्हें ध्वनिमत से पारित कर दिया है। वित्त मंत्री ने हालांकि विपक्ष के आचरण की निंदा करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि एक ओर विपक्ष के सदस्य संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पी रहे हैं और फिर यहां सदन में आकर एलपीजी के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। मैं अपने बयान में इस मामले पर उठाए गए सरकारी कदमों के बारे में ही जानकारी दे रही हूं। लेकिन उन्हें देखकर लगता है कि उनकी रुचि केवल हंगामा और नारेबाजी करने में ही है। सदन में शोरगुल करके विपक्ष मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। जबकि इन्हें मौजूदा दौर में दुनिया के कुछ देशों में जारी युद्ध की वजह से उपजे संकट के बीच केंद्र द्वारा आमजन के हित में उठाए जा रहे तमाम कदमों को अपना समर्थन देना चाहिए। लेकिन इनका व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन में इसी व्यवधान के बीच एप्रोप्रिएशन बिल भी पेश किया गया और वह भी पारित हो गया है। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तन्नेटी ने विपक्षी सांसदों से अपनी जगहों पर जाकर बैठने का अनुरोध किया। जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, बीएसी की बैठक में दोनों मुद्दों पर चर्चा को लेकर सहमति बनी थी। लेकिन विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, अब इनके सांसद भी उन्हीं के रास्ते पर हैं।

खास बातें
- संकट के समय में सरकार संग खड़ा होने की बजाय विपक्ष संसद की सीढ़ियों पर बैठकर पीते हैं चाय, फिर मांगते एलपीजी पर चर्चा

केंद्र को मिली अतिरिक्त खर्च की अनुमति

उक्त चर्चा का निष्कर्ष यही है कि इसके जरिए सरकार को लोकसभा से चालू वित्त वर्ष के लिए 2.01 लाख करोड़ के अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मिल गई है। जो कि मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 80 हजार करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों के अनुमान वास्तविक अतिरिक्त खर्च की धनराशि 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि अतिरिक्त खर्च का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे राजकोषीय घाटा सरकारी लक्ष्य के आंकड़े को पार नहीं करेगा यानी अनुदान की मांगों की मदद से 2025-26 के बजट अनुमान से ज्यादा कुल खर्च नहीं होगा। केंद्र के संशोधित अनुमान के तहत वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 फीसदी पर बना रहेगा। जो कि बजट अनुमान में तय लक्ष्यों के समान ही है।

उर्वरकों की कमी नहीं होगी, निश्चिंत रहें किसान

उन्होंने मौजूदा चिंताजनक हालात के बीच देश के किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि इसके लिए हमने अनुदान की अनुपूरक मांगों में पर्याप्त प्रावधान किया है। इनमें एक लाख करोड़ का आर्थिक स्थिरीकरण कोष बनाने का भी प्रावधान किया गया है। जो अचानक आने वाले संकटों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। जैसा कि अभी ईरान युद्ध की वजह से संकट उत्पन्न हुआ है। उर्वरक सब्सिडी के लिए 19 हजार 230 करोड़, पीएमजीकेवाई के लिए 23 हजार 641 रुपए के अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी गई थी। जबकि रक्षा मंत्रालय के लिए 41 हजार 882 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। पूर्व सैनिकों के कल्याण को सरकार गर्व से समर्थन करती है। इनके लिए हमने अतिरिक्त धनराशि के जरिए 14 हजार 458 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जो कि पूर्व में 6 हजार 141 करोड़ रुपए था।

एक अप्रैल से लागू होगा जी राम जी

उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से मनरेगा की जगह पर सरकार द्वारा बनाई गई नई योजना विकसित भारत- जी राम जी देश में लागू हो जाएगी। इस बाबत नियम बनाए गए हैं। इस संबंध में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है।

खबर संक्षेप

7 साल जेल के बाद शख्स को मिली जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी एक व्यक्ति को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वह व्यक्ति पिछले सात साल से अधिक समय से जेल में बंद है और उसकी अपील पर फिलहाल जल्दी सुनवाई होने की संभावना नहीं है। पीठ ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया।

महाराष्ट्र में सभी वाहनों के लिए एक नियम होंगे

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने अब पैसेंजर लेकर चलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-रिक्शा) और ई-बाइक के लिए परमिट लेना जरूरी कर दिया है। यह फैसला राज्य में नियमों को एक जैसा बनाने के लिए लिया गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को दी। इससे पहले, इलेक्ट्रिक ऑटो को अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं थी।

बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी

पटना। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद विधानसभा परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

कोकराझार में 4,570 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया

असम के तेज विकास के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध, 3 नई रेल सेवाएं शुरू

मौसम की खराबी के चलते निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच सके

एजेंसी ⏭ गुवाहाटी

पीएम नरेंद्र मोदी के असम के दो दिवसीय दौरे के दौरान खराब मौसम की वजह से उनके कार्यक्रम में अचानक बदलना पड़ा। प्रधानमंत्री को शुक्रवार को कोकराझार जाना था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया, जिसके बाद पीएम गुवाहाटी पहुंचे। इलाके में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया। गुवाहाटी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्रीमोदी ने राजधानी गुवाहाटी से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने 3नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि मौसम खराब होने की वजह से मैं कोकराझार नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप सभी का क्षमाप्रार्थी हूं। यहां गुवाहाटी से ही आपसे संवाद संभव हुआ है। मैं दिल्ली से निकला था आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा और अब मैं यहां से आपके दर्शन भी कर रहा हूं और आपसे बात भी कर रहा हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी से ही दी सौगातें

प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दी योजनाओं की सौगातें

सरकार यहां तेज विकास के लिए निरंतर काम कर रही

उन्होंने कहा कि भाजपा-एनडीए की डबल इंजन सरकार असम की विरासत के संरक्षण और असम के तेज विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। आज यहां इस कार्यक्रम में ही इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें से 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड की सड़कों के लिए खर्च होने जा रही है। 'असम माला अभियान' के तीसरे चरण से असम की रोड़ कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त होगी।

'असम माला 3.0' की शुरुआत की

पीएम मोदी ने 3,200 करोड़ की लागत वाली एक प्रमुख सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना 'असम माला 3.0' की शुरुआत की। अंतर-राज्यीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए असम भर में 900 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

छह सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास किया

उन्होंने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) क्षेत्र में लगभग 1,100 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित छह सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें चार फ्लाईओवर और दो पुल शामिल हैं।

इन परियोजनाओं से कोकराझार जिले में यातायात जाम कम करने और संपर्क, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण आवागमन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, पीएम मोदी ने कोकराझार जिले के बाशबारी में आवधिक मरम्मत (पीओएच) कार्यशाला की आधारशिला रखी।

3 रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई

पीएम मोदी ने असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संपर्क सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई तीन नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें कामाख्या-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है, जो उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, असम और पश्चिम बंगाल के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगी।

विपक्ष पर किया हमला- कांग्रेस को बताया झूठे वादों की दुकान

प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक बोडोलैंड का ये क्षेत्र कांग्रेस के विश्वासघात का साक्षी रहा है। बोडोलैंड की अनेक पीढ़ियों को कांग्रेस ने झूठे सपनों में उलझाए रखा। कांग्रेस सरकारों ने सिर्फ दिखावे के लिए कागजी समझौते किए। इसी सोच के साथ बोडो शांति समझौता किया गया। इस दैरान कांगरेस को झूठे वादों की दुकान बताया।

बृजमोहन के सवाल पर लोस में विदेशमंत्री का जवाब

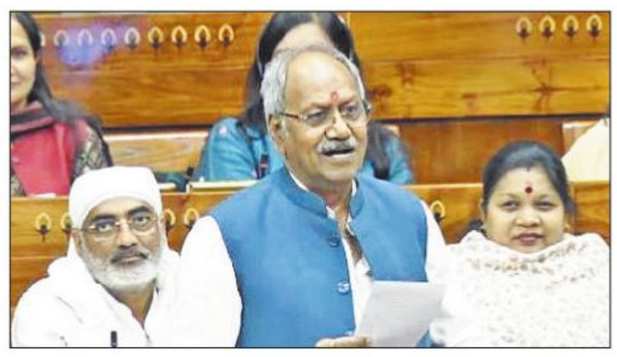

पाकिस्तान, चीन को छोड़ पड़ोसी देशों को 4,320 करोड़ की मदद दे रहा है भारत

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

विश्व में मचे भारी उथल पुथल, युद्ध और कलह के बीच रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में शुक्रवार को पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबन्धों सहित अन्य कूटनीति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जवाब चाहा। अग्रवाल ने विस्तारवादी नीति के समर्थक चीन की हिंद महासागर क्षेत्र की गतिविधियों पर भारत की नज़र और पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान के साथ संबन्धों और उनको दी जा रही आर्थिक सहायता पर भी जानकारी चाही। जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका के साथ भारत का विकास सहयोग श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताओं और वहां के लोगों की जरूरत के अनुरूप है। इस क्षेत्र में भारत ने इस साल श्रीलंका को 300 करोड़ की मदद की है, जबकि अगले साल 400 करोड़ की मदद प्रस्तावित है।

इसके अलावा बांग्लादेश को 120 करोड़, भूटान को 1775 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, मालदीव को 600 करोड़, म्यांमार को 350 करोड़ और अफगानिस्तान को 100 करोड़ की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। भारत अभी अपने इन पड़ोसी देशों को 4320 करोड़ की मदद देता है। जयशंकर ने बताया कि भारत अपनी पड़ोस प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टिकोण के अनुरूप अपने पड़ोसी देशों में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। भारत बिमस्टेक क्षेत्र में क्षमता और संस्था निर्माण की दिशा में अनेक पहल कर रहा है। जिसमें बिमस्टेक सचिवालय को अनुदान प्रदान करना, कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण करना और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यापार आदान-प्रदान युवा आदान-प्रदान और सांस्कृतिक आधार प्रदान का आयोजन करना शामिल है। साथ ही बिमस्टेक क्षेत्र में उन्नत क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत का दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता सुरक्षा पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों, समुद्री और साइबर सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, आपदा तैयारी, खाद्य सुरक्षा और मानव सुरक्षा सहित उनको मजबूत बनाने,कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और लोगों की आपसी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित है।

भारत अपनी पड़ोस प्रथम नीति के तहत मदद कर रहा

देश में बढ़ते ऊर्जा संकट पर सरकार करे ठोस तैयारी: सैलजा

हरियाणा में एलपीजी संकट चिंताजनक लोगों को राहत देने ठोस कदम उठाए जाएं

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने देश में उभरते ऊर्जा संकट और हरियाणा में एलपीजी की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और कई स्थानों पर धक्का-मुक्की तक की नौबत आ रही है। यह स्थिति सामान्य नहीं है और सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि दुनिया में तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाना बेहद आवश्यक है, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि यह केवल एलपीजी का मुद्दा नहीं है, बल्कि पेट्रोल, डीजल और अन्य ऊर्जा संसाधनों से जुड़ा बड़ा सवाल है। यदि समय रहते सरकार ने ठोस तैयारी नहीं की तो इसका सीधा असर करोड़ों लोगों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह ऊर्जा सुरक्षा को लेकर स्पष्ट रणनीति बनाए, एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे और राज्यों में पैदा हो रही समस्या को तुरंत दूर करे।

विपरीत परिस्थितियों में भी केंद्र की मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश रखने में बहुत हद तक सफल

वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी भारत में फिलहाल महंगाई डायन नहीं खाए जात है ....

शिशिर सोनी ⏭ नई दिल्ली

भारत में खुदरा महंगाई दर फरवरी महीने में बढ़कर 3.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों में दी गई। इससे पहले जनवरी में खुदरा महंगाई दर 2.75 प्रतिशत थी। फरवरी में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में तेजी के कारण दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला, जिसमें 2024 को आधार वर्ष बनाया गया है, उसी के तहत यह आंकड़ा जारी किया गया है। अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे में फरवरी के लिए लगभग 3.1 प्रतिशत महंगाई का अनुमान लगाया गया था, जबकि वास्तविक आंकड़ा उससे थोड़ा अधिक रहा। यह अप्रैल 2025 के बाद सबसे अधिक स्तर है, जब खुदरा महंगाई 3.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी। हालांकि हाल के महीनों में महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है।

हरिभूमि विशेष

पिछले वर्ष 2025 के अधिकतर महीनों में महंगाई दर 2 प्रतिशत से भी नीचे रही थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियां भी आने वाले समय में महंगाई को प्रभावित कर सकती हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसके कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव से कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत कच्चे तेल के आयात पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव का असर देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ सकता है। विशेष रूप से हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ती भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम मानी जा रही है। यदि यहां किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है, तो तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देशों पर पड़ेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का कितना बोझ खुद वहन करती हैं और कितना उपभोक्ताओं पर डालती हैं। पिछले दो वर्षों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।

हालांकि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो तेल कंपनियां इसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं और उद्योगों पर डाल सकती हैं। इससे परिवहन लागत बढ़ेगी और इसका असर अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। अगर कच्चे तेल की औसत कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहती है, तो उसका असर सकल घरेलू उत्पाद और महंगाई दोनों पर पड़ सकता है। अलग-अलग परिस्थितियों में जीडीपी पर 50 से 130 बेसिस प्वाइंट तक प्रभाव पड़ने का अनुमान है, जबकि खुदरा महंगाई में 10 से 130 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ोतरी हो सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की टोकरी में खाद्य और पेय पदार्थों का लगभग 37 प्रतिशत वजन है। जनवरी में इस श्रेणी की महंगाई 2.1 प्रतिशत थी, जो फरवरी में बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में महंगाई का रुख काफी हद तक वैश्विक तेल कीमतों, खाद्य आपूर्ति और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा।

अनुप्रिया ने बताया- सरकार ने टैगिंग व जबरन बिक्री रोकने के उपायों को मजबूत किया

नकली उर्वरकों और धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई, गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता के लिए अप्रैल 2025 से अब तक 4,30,541 छापे मारे गए: पटेल

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

भारत सरकार ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश में नकली उर्वरकों के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि भारत सरकार राज्यों द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरकों और हेराफेरी के मामलों में की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर निगरानी करती है। अप्रैल 2025 से अब तक देश भर में कुल 4,30,541 छापे मारे गए हैं। इसके परिणामस्वरूप 15,544 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 6,620 लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए हैं और दोषियों के खिलाफ 794 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश राज्यों ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में नकली रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में कोई भी कारखाना या कंपनी शामिल नहीं पाई गई है। हालांकि कुछ राज्यों ने व्यक्तियों एवं विक्रेताओं के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए हैं और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में दो एफआईआर दर्ज की गईं। हरियाणा में 4, कर्नाटक में 15 , मध्य प्रदेश में नकली उर्वरकों के 16 मामले दर्ज किए गए और 14 एफआईआर दर्ज की गईं हैं। महाराष्ट्र में नकली उर्वरकों में शामिल 19 निर्माताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। ओडिशा में 3मामले दर्ज किए गए। राजस्थान ने संदिग्ध उर्वरकों के 42 निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में 36 मामले दर्ज किए गए। अनुप्रिया ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रशासित उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश, 1985, निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले उर्वरकों के निर्माण या बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। राज्य सरकारें इस अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं, जिनमें लाइसेंस रद्द करना या निलंबित करना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करना शामिल है। इसके अंतर्गत तीन महीने से लेकर सात वर्ष तक की कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया है और राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार की टैगिंग या जबरन बिक्री को रोकने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए हैं। हालांकि उर्वरक विभाग ने उर्वरक कंपनियों और राज्य सरकारों को नियमित रूप से निर्देश जारी किए हैं कि वे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग को हतोत्साहित करें।

गृहमंत्री शाह की अध्यक्षता में मंजूरी

आपदा पीड़ित 6 राज्यों को 1,912 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिलेगी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान 'मोंथा' से प्रभावित छह राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रकी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से देंगे। सरकार आपदाओं के समय राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर संभव मदद प्रदान कर रही है।

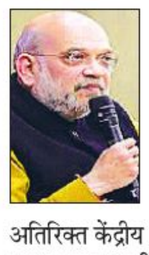

इन राज्यों को मिलेगी सहायता

इस राशि में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ , छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़, गुजरात को 778.67 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़, नगालैंड को 158.41 करोड़ और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह वर्ष के शुरुआती बैलेंस के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन होगी।